BLM Academy

Affiliated to C.B.S.E. New Delhi, C.B.S.E. Affiliation No.: 3530343
ISO 9001:2015 (QMS) Certified School

"The Best Way To Predict Your Future Is To Create It With BLM Academy."

Admission Open

For The Academic Session 2026-27
(Classes Nursery to IX & XI)

LIMITED SEATS
APPLY NOW

Vision -
To prepare the children empowered with Indian ethical and spiritual values to face the global challenges.

Mission-
To produce enriched and enlightened human resource for the country.

Pillars -
SATYA, PURUSHARTH & PARAMARTH

Goal-
ब्रह्म तत् लक्ष्यम्

Streams: Science, Commerce & Humanities

Celebrate The Gift of Life

+91 7055515681
+91 7055515683
www.blmacademy.com

Padampur Devaliya, Gora Parao, Haldwani (Nainital), Uttarakhand

blma.principal@gmail.com

प्रणवो धनु: शरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्मुच्यते।
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ।। (मुण्डक उपनिषद)

पोस्टल रजि.नं.यूए-नैनीताल-356-2021-2023

अप्रैल 2026

उत्तरांचल दीप पत्रिका

यशस्वी पत्रकार वेदप्रकाश गुप्ता को समर्पित

दुनिया के लिए ट्रंप खतरा

₹:40

मोदी, योगी, धामी का रिकार्ड

ई-मेल: uttranchaldeepatrika@gmail.com

Web: uttaranchaldeep.com

मासिक
उत्तरांचल दीप
पत्रिका

वर्ष:8, अंक 12, अप्रैल 2026

संस्थापक संपादक
स्व.वेदप्रकाश गुप्ता
प्रधान संपादक
साकेत अग्रवाल
संपादक
श्रीमती आदेश अग्रवाल
मुख्य कार्यकारी संपादक
केके चौहान
मुख्य उप संपादक
उदयभान सिंह
मार्केटिंग हेड
तारु तिवारी
प्रबंधक
दीपक तिवारी
वरिष्ठ संवाददाता
रवि दुर्गापाल

उत्तरांचल दीप ब्यूरो
दिल्ली : शालिनी चौहान
रुद्रप्रयाग : हिमांशु पुरोहित
नैनीताल : अफजल फौजी
अल्मोड़ा : कमल कपूर
पिथौरागढ़ : ललित जोशी
बागेश्वर : नरेंद्र बिष्ट
चंपावत : मनोज राय
बरेली : अनुज सक्सेना
मुरादाबाद : आशेंद्र कुमार अग्रवाल
डोईवाला : चंद्रमोहन कोठियाल
किच्छा : राजकुमार राज
रामनगर : एचसी भट्ट
थत्यूड़ : मुकेश रावत
रुद्रपुर : मुकेश गुप्ता
बाजपुर : इंद्रजीत सिंह
ग्राफिक्स डिजाइन: देवेंद्र सिंह बिष्ट
सभी पद अवैतनिक एवं परिवर्तनीय

मुख्यालय
हल्द्वानी: चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने
नैनीताल रोड, हल्द्वानी (उत्तराखंड)

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक श्रीमती आदेश अग्रवाल द्वारा उत्तरांचल दीप, चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने नैनीताल रोड हल्द्वानी से मुद्रित व प्रकाशित।
आएनआई नंबर: UTTHIN/2018/77440
पोस्टल रजि.नं.यूए-नैनीतील-356-2021-2023

उत्तरांचल दीप पत्रिका में प्रकाशित लेख, पत्र व अन्य कालम में लेखकों के विचार होते हैं, उनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।
समस्त विवाद हल्द्वानी न्यायालय के अधीन होंगे।

www.uttaranchaldeep.com
uttranchaldeepatrika@gmail.com
+91 8881788066 @uttranchaldeep

अंदर

भारत में पैनिक बाइंग आम है

कोरोना काल में लॉकडाउन में लोगों ने ज्यादा से ज्यादा राशन खरीदा, नतीजा दुकानों में राशन की कमी हो गई जबकि बाद में दुकानों में पर्याप्त सामान उपलब्ध था, कोरोना काल में ही ऑक्सिजन गैस की भी जमाखोरी हुई, जिसे जरूरत नहीं थी उसके पास ऑक्सिजन ...

पर्यटन

उत्तराखंड की सीक्रेट वैली

हिमालय की गोद में बसी उरगम घाटी उत्तराखंड के सबसे छिपे हुए रत्नों में से एक है, चोपटा और औली की भीड़-भाड़ तथा ...

साहस नजरिए

इंडिया में ईद खाड़ी में धमाके

मुस्लिम देशों ईरान, गाजा, लेबनान, संयुक्त अरब अमीरात सऊदी अरब, कतर, ओमान और बहरीन के साथ पाकिस्तान और ...

दिल्ली सियासत

स्पीकर ने एलओपी की हेकड़ी निकाली

12 मार्च को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी की सारी हेकड़ी निकाल दी और ...

राजनीति

भाजपा का फोकस मालवा निमाड़ पर?

मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में निमाड़ के बड़वानी जिले की नागलवाड़ी में कैबिनेट बैठक का ...

साकेत अग्रवाल

273 सांसदों का बढ़ेगा बोझ

2029 में लोकसभा का नक्शा बदल जाएगा। जी हां केंद्र सरकार लोकसभा सीटों की संख्या और लोकसभा में महिला आरक्षण बढ़ाने वाला बिल ला सकती है। सरकार लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव ला रही है, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 2011 की जनगणना के आंकड़े को आधार बनाकर परिसीमन करने की तैयारी है। कुल सीटों में से 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सरकार इस प्रक्रिया को कानूनी रूप देने के लिए मौजूदा सत्र में नहीं तो अगले सत्र में संशोधन विधेयक ला सकती है। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी विपक्षी सांसदों के साथ अहम बैठक कर चुके हैं, तो वहीं एनडीए नेताओं की बैठक में आगे का पूरा रोडमैप तय किया जाना है। यदि प्रस्ताव पर मोहर लगी तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 120 कर दिया जाएगा। इसी तरह बिहार की 40 सीटों में 20 का इजाफा होगा और लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या 60 हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में 42 से बढ़कर 63 सांसद हो जाएंगे। तमिलनाडु 39 से बढ़कर सांसदों की संख्या 59 हो जाएगी। महाराष्ट्र में 48 से बढ़कर 72 सांसद हो जाएंगे। कर्नाटक में 28 से बढ़कर 42, केरल में 20 से बढ़कर 30, आंध्र प्रदेश में 25 से बढ़कर 38, गुजरात में 26 से बढ़कर 39, राजस्थान में 25 से बढ़कर 38 सांसद हो जाएंगे। इसी तरह दिल्ली में वर्तमान 7 सांसदों के स्थान पर 11 सांसद होंगे। ओडिशा में 21 से बढ़कर सांसदों की संख्या 32 हो जाएगी जबकि झारखंड में सांसदों की संख्या 14 से बढ़कर 21 हो जाएगी। यानी 273 सांसदों के वेतन भत्तों का भारी भरकम बोझ उठाने के लिए देश की जनता को तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में सांसदों का संसद में क्या आचरण है, संसद सत्रों में कितना काम होता है, पूरे संसद सत्र हंगामों की भेट चढ़ जाते हैं। इसलिए सरकार को एक विधेयक और लाना चाहिए। संसद सत्र में जिन सांसदों का आचरण सिर्फ हंगामा करने वाला हो, बेल में आकर सदन की कार्रवाई रोकने का हो, सदन का वाकआउट करने का हो उन्हें पूरे महीने के वेतन और भत्तों से वंचित किया जाए। क्योंकि सांसदों को वेतन भत्ते और सुविधाएं संसद की कार्रवाई में बाधा डालने या हंगामा करने के लिए नहीं मिलती। ये किसी भी सूरत में किसी सांसद को मौलिक अधिकार भी नहीं हो सकता। एक तरह से कहा जाए तो काम नहीं तो दाम नहीं वाला सिस्टम सांसदों पर लागू होना चाहिए। फिर देखिए बिना किसी अवरोध के संसद के दोनों सदनों में शांति के साथ जनहित के कार्य किस गति से होते हैं? सरकार ने मार्च 2025 में सांसदों के वेतन और पेंशन में 24 प्रतिशत की वृद्धि की तब किसी भी सांसद ने न तो हंगामा किया और न ही सदन की कार्यवाही बाधित की।

हैरानी की बात ये है कि उस वृद्धि को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया। सरकार ने कहा कि जन प्रतिनिधियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि का यह फैसला कॉस्ट ऑफ लिविंग और इंफ्लेशन रेट को ध्यान में रखकर किया गया है। इस वृद्धि के साथ, सांसदों का मासिक वेतन 1 लाख रुपये प्रति माह से बढ़कर 1.24 लाख रुपये हो गया है, जबकि उनका दैनिक भत्ता 2,000 से बढ़कर 2,500 रुपये हो गया। अगर एक वर्ष में 100 दिनों का संसद सत्र होता है, तो इस हिसाब से दैनिक भत्ते के रूप में एक सांसद पर एक वर्ष में 2.5 लाख रुपये खर्च होता है। पूर्व सांसदों की पेंशन भी 24 प्रतिशत बढ़ाकर 25,000 रुपये से 31,000 रुपये प्रति माह कर दी गई। वेतन और दैनिक भत्ते के अलावा, सांसदों को प्रति माह 70,000 रुपये का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है, जो सालाना 8.4 लाख रुपये होता है और ऑफिस एक्सपेंस 60,000 रुपये प्रति माह होता है जो कुल मिलाकर 7.2 लाख रुपये प्रति वर्ष होता है। इसके अतिरिक्त सांसदों को ट्रैवल अलाउंस एवं अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जिसका अनुमानित खर्च हर साल प्रति सांसद 10 लाख रुपये है। इस तरह कुल वर्तमान दोनों सदनों के 788 सांसदों (लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245) पर प्रति वर्ष होने वाला वर्तमान खर्च लगभग 3,386.82 करोड़ रुपये है। इनमें 273 महिला सांसदों की संख्या बढ़ने पर प्रति महिला सांसद 7.2 रुपये के खर्च का मतलब है कि सालाना 1965.60 करोड़ रुपये का देश पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा। जो सांसदों पर सालाना खर्च 5352.42 करोड़ रुपये होगा। ऐसे में सवाल ये है कि जिन सांसदों पर देश की मोटी रकम खर्च होती है उसका जनता को क्या लाभ है। आम तौर पर बड़ी संख्या में सांसद भत्ता लेते हैं पर क्षेत्र में कभी नजर नहीं आते। यह भी सच है कि अधिकांश सांसद अपनी निधि तक खर्च नहीं कर पाते है। अगर संसद सत्र में 2500 रुपये दैनिक भत्ता न मिले तो बड़ी संख्या में सांसद संसद से भी गायब हो जाएंगे। क्योंकि भत्ता मिलने पर भी कुछ सांसदों की संसद में 50 प्रतिशत हाजिरी भी नहीं होती। सांसदों की बात छोड़िए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष तक गायब रहते हैं। जो विपक्षी सांसद सदन में आते हैं तो वो सिर्फ हंगामा करते हैं। धरना, प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे सांसदों का बोझ देश क्यों ढोए। क्यों जनता के खून पसीने की कमाई ऐसे सांसदों पर खर्च की जाए। हैरानी की बात ये भी है कि सांसदों द्वारा खुद ही अपने वेतन में वृद्धि निर्धारण कर लेते हैं। आलोचकों का तर्क है कि सांसदों द्वारा अपने वेतन में वृद्धि पर फैसला संसद में मतदान के बजाय एक स्वतंत्र आयोग द्वारा किया जाए।

देश का गौरव डॉ.पूनम गुप्ता

एचपी शर्मा
मुरादाबाद

डॉ. पूनम गुप्ता का मानना है कि आज के युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की गाथाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि वे देश के इतिहास और बलिदान को बेहतर ढंग से समझ सकें, डॉ.पूनम को लेखन का शौक है, वह कई धार्मिक पुस्तकें लिख चुकी हैं जिन्हें पाठकों द्वारा सराहा गया है।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 12 नवंबर, 1963 को जन्मी डॉ.पूनम गुप्ता द्वारा अतीत के द्वार खोल दिए गए हैं, जिससे पाठक गुमनाम नायिकाओं के संघर्षों और विजय से जुड़ सकते हैं। अपने गहन शोध और प्रभावशाली कहानी कहने की शैली के माध्यम से, उन्होंने उन लोगों को आवाज दी है जिन्हें लंबे समय से इतिहास ने खामोश कर रखा था। यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवित रहे। अंततः डॉ. पूनम गुप्ता की उपलब्धि न केवल एक रिकॉर्ड है, बल्कि इतिहास की दिशा तय करने वाली महिलाओं की अनकही कहानियों को संरक्षित और सम्मानित करने में कहानी कहने की शक्ति का प्रमाण है। 'महान वीरांगनाओं की गाथाएं' किताब महिला स्वतंत्रता सेनानियों के साहस, दृढ़ता और अटूट भावना को ऐतिहासिक श्रद्धांजलि है, जो हमें भारत की स्वतंत्रता की यात्रा पर उनके गहरे प्रभाव की याद दिलाती है। प्रसिद्ध लेखिका और इतिहासकार डॉ. पूनम गुप्ता ने 14 दिसंबर, 2024 को यह इतिहास रचा। उन्होंने 'महान वीरांगनाओं की गाथाएं' नामक पुस्तक में 1367 महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कहानियां लिखकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। इस असाधारण संकलन ने उन्हें विश्व के अभिलेखों में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया है। एक ही पुस्तक में महिला स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों का नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। डॉ. पूनम गुप्ता को इस विशाल कार्य को शुरू करने की प्रेरणा कहां से मिली? इस पर लेखिका का कहना है कि उनकी प्रेरणा महिला सशक्तिकरण के प्रति उनके गहरे लगाव और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिला स्वतंत्रता सेनानियों के अविश्वसनीय लेकिन अक्सर उपेक्षित योगदान को उजागर करने की इच्छा से मिली। इन गुमनाम नायिकाओं की कहानियों को सुनाकर, डॉ. गुप्ता का उद्देश्य उनकी बहादुरी और दृढ़ता को सम्मानित करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां देश के इतिहास को आकार देने में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाने और उसका जश्न मनाएं।

1367 वीरांगनाओं की गाथाएं

विरासत में मिली समाज सेवा और देशभक्ति की पूंजी एवं विगत 34 वर्ष से साहित्य साधना में तल्लीन साधक डॉ. पूनम गुप्ता है। मुरादाबाद के महाविद्यालय में प्रवक्ता पद पर कार्यरत डॉ. पूनम को विभिन्न विधाओं में लिखने का इतना जुनून है कि अभी तक उनके द्वारा लिखित 25 पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है। उनके द्वारा लिखित महान वीरांगनाओं की गाथाएं पुस्तक को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सराहनीय साहित्यिक भूमिका को लिखित रूप से सराहा गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से जुड़ी डॉ. पूनम गुप्ता ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली 1367 वीरांगनाओं की गाथाओं को अपनी पुस्तक 'महान वीरांगनाओं की गाथाएं' में संकलित कर देश को समर्पित किया है। इस पुस्तक को लिखने में उन्हें आठ वर्ष लगे, इसके लिए उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण कर ऐतिहासिक तथ्यों को संकलित किया। इसे देशभर के पुस्तकालयों और शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन वीरांगनाओं के अदम्य साहस से प्रेरणा ले सकें। डॉ. पूनम गुप्ता का मानना है कि आज के युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की गाथाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि वे देश के इतिहास और बलिदान को बेहतर ढंग से समझ सकें। डॉ. पूनम गुप्ता को पुस्तकें लिखने का शौक है। इससे पहले भी वह कई पुस्तकें लिख चुकी है, जिनमें कई धार्मिक पुस्तकें भी शामिल हैं। उनकी ये पुस्तकें हिंदी भाषा में प्रकाशित हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से जुड़ी डॉ. पूनम गुप्ता ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली 1367 वीरांगनाओं की गाथाओं को अपनी पुस्तक 'महान वीरांगनाओं की गाथाएं' में संकलित कर देश को समर्पित किया है।

डॉ पूनम गुप्ता की झोली में अवार्ड

डॉ पूनम गुप्ता द्वारा रचित पुस्तक को वर्ल्ड वाईड बुक रिकार्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड, सुषमा स्वराज अवार्ड और जैमिनी साहित्य अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त डॉ पूनम गुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक में कुछ विशेष सुझावों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विगत वर्ष अपने संबोधन में सम्मलित कर डॉ पूनम की साधना को सम्मान दिया गया। डॉ पूनम गुप्ता ने कविताओं के सृजन के लिए 6 पुस्तक प्रकाशित कराई हैं जबकि अन्य 19 पुस्तक में उनके द्वारा लिखित शिवपुराण और रामचरित मानस को अधिक प्रसिद्धि मिली है। अन्य विशेष पुस्तकों में भारत का इतिहास, मिशन शक्ति अभियान, राष्ट्रीय ध्वज की शौर्य गाथा, मेरा देश मेरी आत्मा और मेरी आत्मकथा को भी पाठकों द्वारा बहुत सराहा गया है। आकाशवाणी से उनकी कविताओं का 35 वर्षों से नियमित प्रसारण हो रहा है। मुरादाबाद में प्रवक्ता डॉ पूनम गुप्ता के पिता का नाम सामाजिक सेवा के लिए आज भी लोग बहुत सम्मान से लेते है उनके सामाजिक प्रयास और सेवा को लक्ष्य मानकर डॉ पूनम साहित्य के साथ ही सामाजिक दायित्वों का कुशलता से निर्वहन करते हुए रैली मिशन शक्ति और स्वच्छता के प्रभारी पद कुशलता से निर्वाह कर रही हैं। डॉ पूनम की साहित्य सृजन के साथ ही सामाजिक दायित्वों की भागीदारी और समर्पण को देखते हुए भारत राष्ट्रवादी संगठन का जिला अध्यक्ष और स्वदेशी मंच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समय समय पर निर्धन बालिकाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निःशुल्क शिविर लगाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की सार्थक और सकारात्मक पहल की गई। डॉ गुप्ता निरंतर साहित्यिक और समाज सेवा की मशाल लेकर महानगर का नाम गौरवान्वित कर रही है।

सुर्खियां

हिंदुत्व पर चलेगी धामी सरकार

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गैरसैण विधानसभा में भाषण न सिर्फ विपक्ष के लिए बल्कि नौकरशाही के लिए भी स्पष्ट संदेश था। यानी उनकी सरकार हिंदुत्व और सनातन के एजेंडे पर चलेगी। धामी ने विधानसभा में दिए अपने डेढ़ घंटे से भी अधिक लंबे भाषण में कई बार देवभूमि के सांस्कृतिक स्वरूप को कायम रखने की बात दोहराई। उनके संबोधन में सनातन संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटने का साफ संदेश था। धामी ने मदरसा बोर्ड खत्म करने का उल्लेख करते हुए कहा कि मदरसों में कट्टरपंथी, जिहादी, निकलते हैं। चार सौ साल पुरानी शिक्षा को अब नहीं पढ़ाया जाएगा। उन्होंने ये तक कह दिया कि मदरसे आतंकवाद की फैक्ट्री बने हैं। धामी ने थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसी घृणित मानसिकता को सहन नहीं करने के अपने संकल्प को दोहराया और कहा कि हमारी सरकार ने इसके खिलाफ कठोर कानून बनाए है। धर्मांतरण रोकने के कानून, दंगा विरोधी कानून देवभूमि के लिए जरूरी थे, ताकि यहां का सांस्कृतिक स्वरूप बना रहे, हम आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित उत्तराखंड देना चाहते है। उत्तराखंड में हो रहे डेमोग्राफी चेंज पर भी स्पष्ट कहा कि घुसपैठियों को देवभूमि में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा, हमने 12 हजार एकड़ सरकारी भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई है और ये अभियान जारी रहेगा। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कराने के लिए कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अतिक्रमण को संरक्षण देने वाले कांग्रेस के नेता हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अतिक्रमण करने वालों को संरक्षण देते है। धामी ने अवैध मजारों के खिलाफ अपनी सरकार के अभियान को जरूरी बताते हुए कहा कि नकली मजारों का खेल देवभूमि में अब नहीं चलेगा। सरकारी भूमि पर लैंड जिहाद की मानसिकता को कांग्रेस शासनकाल में पनपने दिया। हमारी सरकार इस अभियान को जारी रखेगी। धामी ने अपनी सरकार के सनातन एजेंडे को आगे रखते हुए कहा कि मानसखंड केदार खंड के मंदिरों देवालयों के संरक्षण के काम शुरू किए गए है। यमुना घाट का निर्माण हो रहा है आगे भव्य कुंभ की तैयारी की जा रही है। सीएम धामी ने विधानसभा में दिए अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रवाद और सनातन के एजेंडे पर कार्य करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रवाद पर चल रही है और सनातन के संरक्षण के साथ चल रही है। उन्होंने विपक्ष को भी एक संदेश दे दिया कि तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। सीएम धामी ने शासन प्रशासन को भी इशारा कर दिया कि वे क्या चाहते है और सरकार की नीति क्या है?

जनसंख्या नियंत्रण की मांग

उत्तराखंड में यूसीसी की तरह जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाया जाना चाहिए, ये मांग रुद्रपुर के भाजपा विधायक शिव अरोरा ने विधानसभा सत्र के दौरान उठाई। विधायक शिव अरोरा ने विधानसभा में उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सब एक वर्ग विशेष द्वारा किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। विधायक शिव अरोरा ने सदन में कहा कि सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, यदि सरकार कानून लाती है तो उस दिन से तीन से अधिक बच्चे होने पर उसके परिवार को समस्त सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाना चाहिए, जिनमें सरकारी राशन, आयुष्मान कार्ड, गैस, प्रधानमंत्री आवास, हर तरह की पेंशन आदि सुविधाएं शामिल हों। क्योंकि एक वर्ग विशेष द्वारा नारा दिया जाता है कि हम पांच हमारे पच्चीस। इसी मानसिकता से धार्मिक आधार पर जनसंख्या बढ़ाई जा रही है। उत्तराखंड के मैदानी जिले ही नहीं बल्कि सुदूर पर्वतीय जिलों में भी बाहर से आए घुसपैठियों ने तेजी से घुसपैठ की है जिसकी वजह से यहां की सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर विचार करना चाहिए। विधायक शिव अरोरा ने कहा कि जैसे यूसीसी पहली बार उत्तराखंड में लागू हुआ, जैसे मदरसा बोर्ड उत्तराखंड में पहली बार समाप्त हुआ वैसे ही राज्य सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून ला कर देश में पहला राज्या बनना चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड राज्य जब बना था तब मुस्लिम आबादी कितनी थी ये आंकड़े सबके पास है और अब ये आबादी 2011 में 14 प्रतिशत पहुंच गई है जो अब अनुमान से 18 प्रतिशत के आसपास हो गई है। बाहरी राज्यों से आए घुसपैठियों ने उत्तराखंड सरकार के बजट को बिगाड़ दिया है। सब्सिडी का फायदा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को मिल रहा है।

भाजपा के बागी कांग्रेस में शामिल

उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर थोड़ी हलचल हुई है। भाजपा में हासिये पर चल रहे कुछ नेताओं ने 28 मार्च को कांग्रेस का दामन थाम लिया। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा भाजपा के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल को लेकर हो रही है। इन नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर राजनीतिक विश्लेषको सवाल उठा रहे हैं कि क्या इससे वास्तव में कांग्रेस को उत्तराखंड में कोई ठोस फायदा मिलेगा? क्या ये नेता अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे? रुद्रपुर से दो बार भाजपा के विधायक रहे और एक बार नगर पालिका के अध्यक्ष रहे राजकुमार ठुकराल के नाम की चर्चा इसलिए हो रही है कि वो कभी भाजपा के कट्टर समर्थक थे। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था। इसके बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। भाजपा ने साफ संदेश भी दे दिया था कि अब राजकुमार ठुकराल का पार्टी में कोई महत्व नहीं है। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में ऊधमसिंह नगर जिले की रुद्रपुर सीट से ठुकराल की जगह शिव अरोड़ा को प्रत्याशी बनाया था। लिहाजा तभी साफ हो गया था कि पार्टी ने उनसे दूरी बना ली है। अब भाजपा यदि किसी नेता से दूरी बनाती है तो उसका क्या हस्र होता है यह जगजाहिर है। ऊधमसिंह नगर जिले की सितारगंज सीट से दो बार बसपा के विधायक रहे नारायण पाल का सियासी सफर कई दलों के बीच झूलता रहा है। वह सबसे पहले कांग्रेस में रहे, फिर बसपा में गए, फिर भाजपा में प्रवेश की कोशिश की, लेकिन अब पुनः जो कांग्रेस छोड़ी थी उसका ही दामन थामना पड़ा। रुड़की के पूर्व [illegible] कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रुड़की नगर निगम का चुनाव लड़ा था और भाजपा व कांग्रेस को हराकर जीत दर्ज की थी। टिहरी की घनसाली विधानसभा सीट से दो बार विधायक रह चुके भीमलाल आर्य, भीमताल सीट से 2022 में निर्दलीय प्रत्याशी रहे ब्लॉक प्रमुख लाखन सिंह नेगी और मसूरी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अनुज गुप्ता भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की मौजूदगी में सभी नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चुनाव संचालन समिति अध्यक्ष और वर्तमान विधायक प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित पार्टी की सीनियर लीडरशिप मौजूद थी। हालांकि उत्तराखंड की राजनीति पर नजर रखने वाले मान रहे हैं कि इन नेताओं के कांग्रेस में जाने से भाजपा को कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। क्योंकि एक अहम तथ्य यह भी सामने आ रहा है कि इन नेताओं में से अधिकांश अपना मजबूत जनाधार पहले ही खो चुके हैं। राजनीतिक जमीन कमजोर होने के कारण अब ये नेता अपनी साख बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे में पार्टी बदलना उनके लिए एक विकल्प बन गया है। इनमें से ज्यादातर का टारगेट 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट हासिल करना है।

मोबाइल कंपनियों का वैरायटी खेल

संसद में बीते दिनों मोबाइल रिचार्ज को लेकर सरकार और विपक्ष लगभग एक ही धुन पर बात करते दिखे। सांसद राघव चड्ढा ने दो प्रमुख मुद्दे उठाए। पहला- लोगों के मासिक प्लान में मिलने वाला डेली डेटा रात 12 बजे खत्म ना हो, बल्कि अगले दिनों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाए। दूसरा मुद्दा-28 दिनों में रिचार्ज खत्म होने का था। सांसद राघव चड्ढा ने मांग की कि कंपनियां पूरे महीने की वैलिडिटी दें। जवाब में दूरसंचार मंत्री ज्योतरादित्य सिंधिया ने कहा कि महीने भर वाले रिचार्ज पहले से उपलब्ध हैं और कंपनियों से उन्हें प्रमोट करने के लिए कहा गया है। जब सरकार और विपक्ष दोनों इस बदलाव को चाहते हैं तो फिर दिक्कत कहां है? इसका जवाब है टेलिकॉम कंपनियां। जियो, एयरटेल और वोडा-आइडिया कंपनियां जितनी वैरायटी 28 दिनों के प्लान में देती हैं, वह 30 दिन या 1 महीने वाले रिचार्ज में नहीं मिलती। यही वजह है कि लोग 28, 56 या 84 दिनों वाले प्लान को प्राथमिकता देते हैं और 12 के बजाए साल में 13 बार रिचार्ज का पैसा चुकाते हैं। 1 साल में 365 दिन होते हैं। 28 दिनों के हिसाब से ग्राहक 336 दिन का रिचार्ज 12 बार में कराते हैं। यानी पूरे साल में उनके पास 29 दिनों की वैलिडिटी कम पड़ जाती है। इस तरह उन्हें एक साल के अंदर 12 के बजाए 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता है। ऐसा ही 56 और 84 दिनों की वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान में भी होता है। आम आदमी पार्टी के विपक्ष के सांसद राघव चड्ढा ने मांग की थी कि, मोबाइल कंपनियां अपने ग्राहकों को पूरे महीने की वैलिडिटी दें। वहीं सरकार का कहना है कि 30 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान पहले से ही उपलब्ध हैं। टेलिकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया यानी ट्राई का भी नियम है कि सभी टेलिकॉम कंपनियों को 30 दिनों वाला प्लान देना जरूरी है। कंपनियां तीन तरह के वाउचर देती हैं- इनमें प्लान वाउचर, कॉम्बो वाउचर और स्पेशल टैरिफ वाउचर, उसमें 30 दिन वाला एक प्लान देना आवश्यक है। बड़ी समस्या 30 दिनों के प्लान में वैरायटी की है। आम ग्राहक फोन रिचार्ज कराते समय सिर्फ वैलिडिटी ही नहीं देखता। वह अनलिमिटेड कॉल्स, डेली डेटा पर भी ध्यान देता है। मोबाइल कंपनियां जो वैरायटी 28 दिनों के प्लान में देती हैं, वह 30 दिन वैलिडिटी वाले प्लान में नहीं होती। उदाहरण के लिए-एयरटेल की वेबसाइट पर एक महीने की वैलिडिटी वाले सिर्फ 4 प्लान लिस्ट हैं। वहीं 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ कंपनी ने 7 प्रीपेड प्लान लिस्ट किए हैं। 30 दिनों की वैलिडिटी में कंपनी कोई ऐसा रिचार्ज नहीं ऑफर करती जो सिर्फ वैलिडिटी पर फोकस करे और कम कीमत में मिल जाए। यही वजह है कि जिन यूजर्स को डेटा नहीं, सिर्फ वैलिडिटी चाहिए, उन्हें 28 दिनों का रिचार्ज कराना पड़ता है। एक महीने वाले रिचार्ज में सबसे बड़ी दिक्कत वैरायटी की है। मोबाइल कंपनियों को ऐसे रिचार्ज प्लान पेश करने होंगे जो 1 महीने की वैलिडिटी कम कीमत में दें, भले उनमें डेटा कम हो। इससे गरीब लोगों को रिचार्ज का सस्ता ऑप्शन मिलेगा और वह एक साल में 13 बार रिचार्ज कराने के लिए मजबूर नहीं होंगे। हालांकि सवाल है, क्या कंपनियां इसके लिए तैयार होंगी, क्योंकि यह सीधे उनकी कमाई को प्रभावित करेगा?

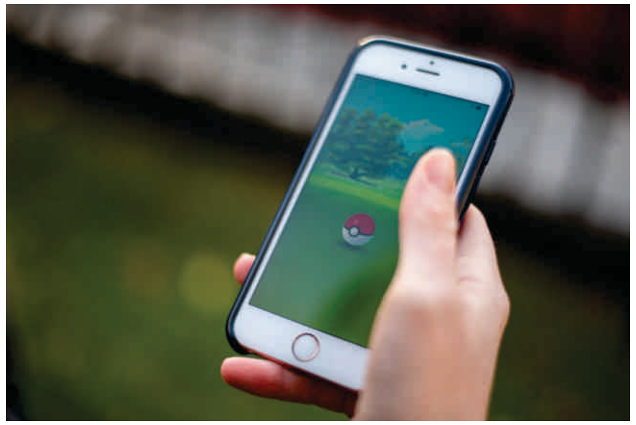

मोदी, योगी, धामी का रिकार्ड

पीएम नरेंद्र मोदी ने ही नहीं बल्कि उनकी टीम के दो और लीडरों योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी ने भी रिकार्ड बनाए हैं, योगी जहां 2017 से यूपी के सीएम बने हुए हैं वहीं धामी उत्तराखंड के वो लीडर हैं जो लगातार दो बार सीएम बने और नारायण दत्त तिवारी के बाद 4 साल का कार्यकाल पूरा किया है।

केके चौहान

राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च 2026 को बतौर पीएम 4340 दिन पूरे कर लिए इसके साथ ही मोदी सबसे ज्यादा लगातार 8940 दिन सरकार में सीएम और पीएम (हेड ऑफ गवर्नमेंट) बने रहने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने सिक्किम के पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ दिया है। चामलिंग का 8,930 दिनों तक लगातार सीएम बने रहने का रिकॉर्ड था। हालांकि चामलिंग का सिर्फ मुख्यमंत्री के रूप में रिकार्ड है जबकि नरेंद्र का मोदी का रिकार्ड सीएम और पीएम के पदों को जोड़कर है। नरेंद्र मोदी का बतौर प्रधानमंत्री का कार्यकाल कड़े और बड़े फैसलों के लिए जाना जाता है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करना हो, नोटबंदी या कोरोना महामारी में पहली बार स्वदेशी वैक्सीन बनाकर कई देशों की मदद करना हो अथवा आतंकवाद के खिलाफ आपरेशन सिंदूर के साथ वैश्विक कूटनीति। मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें दुनिया के 29 देश अपने देश का सर्वश्रेठ सम्मान दे चुके हैं। ये रिकार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही नहीं बल्कि उनकी टीम के दो और लीडरों ने भी रिकार्ड बनाया है। इनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां लगातार दूसरी बार सीएम बने वहीं मार्च 2026 तक लगातार 9 साल तक यूपी के सीएम पद पर बने रहने का रिकार्ड कायम किया है। योगी आदित्यनाथ की पहचान बुल्डोजर बाबा के रूप में बनी हुई है। उनका बुल्डोजर मॉडल पाकिस्तान तक में फेमस है। दूसरी यूपी की कानून व्यवस्था और आपरेशन लंगड़ा बहुत चर्चा में रहता है। इसी तरह पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के वो लीडर हैं जो लगातार दूसरी बार सीएम बने और नारायण दत्त तिवारी के बाद न सिर्फ मार्च 2026 में चार साल का कार्यकाल पूरा किया बल्कि उत्तराखंड के सीएम के रूप में वो भाजपा के 4 साल 9 महीने तक लगातार सीएम बने रहने वाले पहले लीडर बन गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अपने चार वर्षों (2022-2026) के कार्यकाल में समान नागरिक संहिता (यूसीसी), सख्त नकल विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून सहित कई प्रमुख ऐतिहासिक कानून और नीतियां लागू की हैं। उन्होंने राज्य में 12,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ ही 30,000 से अधिक सरकारी नौकरियां भी दी हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज होने से भी चिंतित है, लिहाजा इसके लिए आपरेशन कालनेमि चलाया जा रहा है। अवैध मजारों, मदरसों और मस्जिदों पर बुल्डोजर एक्शन हो रहा है।

मोदी के कड़े व बड़े फैसले

17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी 6 साल की उम्र में ही कांग्रेस की ओर से महागुजरात आंदोलन का हिस्सा बने। फिर 8 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए थे। 7 अक्टूबर 2001 को 51 साल की उम्र में बिना विधायक बने ही नरेंद्र मोदी गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वे 2002 में, 2007 में और फिर 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। अपने राजनीतिक सफर के 25 सालों में से नरेंद्र मोदी 14 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। पिछले 11 साल से वे देश के प्रधानमंत्री हैं। पीएम के रूप में यह उनका तीसरा कार्यकाल है। 2025 में मोदी ने बतौर पीएम इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन नेहरू से अब भी पीछे हैं। यानी नरेंद्र मोदी भारत के लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने वाले दूसरे लीडर हैं। लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम है। वे 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक यानी लगातार कुल 6126 दिन तक इस पद पर रहे। लेकिन लेकिन 1947 में वो जनता द्वारा चुने हुए पीएम नहीं थे। फिर भी पीएम मोदी, नेहरू के रिकॉर्ड से 1812 दिन पीछे हैं। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 2029 के बाद भी उन्हें पीएम बने रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल 2014 से अब तक कई ऐतिहासिक और साहसिक फैसले लिए गए, जिन्होंने भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और कूटनीति ने समाज को गहराई से प्रभावित किया है। प्रमुख फैसलों में अनुच्छेद 370 का खात्मा, नोटबंदी, जीएसटी, तीन तलाक पर रोक, सर्जिकल स्ट्राइक, विधायिका में महिलाओं का 33 प्रतिशत आरक्षण और सीएए जैसे निर्णय शामिल हैं, जिन्हें नया भारत बनाने की दिशा में कड़े कदम माना जाता है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थ व्यवस्था बनकर उभरा है। देश की सुरक्षा की बात करें तो मोदी के कार्यकाल में सेना को खुली छूट मिली जिसकी वजह से पड़ोसी मुल्क चीन हो या पाकिस्तान अब भारत को आंख नहीं दिखाते हैं।

यूपी में चुस्त कानून-व्यवस्था और यूपी से माफिया राज को मिट्टी में मिलाने का श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ को जाता है, योगी ने मुख्तार अंसारी और अतीक के आतंक से यूपी को मुक्त कराने का काम किया है, 8 पुलिस वालों का हत्यारा गैंगस्टर विकास दुबे 10 जुलाई 2020 को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।

योगी का कार्यकाल

उत्तर प्रदेश में चुस्त कानून-व्यवस्था और यूपी से माफिया राज को मिट्टी में मिलाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। योगी ने मुख्तार अंसारी और अतीक के आतंक से यूपी को मुक्त कराने का काम किया है। विकास दुबे उत्तर प्रदेश के कानपुर का कुख्यात गैंगस्टर और माफिया सरगना था, जिसने जुलाई 2020 में बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर योगी को चुनौती दी थी। फिर क्या था हत्या, अपहरण और जबरन वसूली करने वाला विकास दुबे 10 जुलाई 2020 को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। योगी सरकार ने न सिर्फ बड़े गैंगस्टरों का सफाया किया बल्कि किसी हद तक अपराध पर रोक भी लगाई है। योगी सरकार ने कृषि और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया है। प्रमुख निर्णयों में अवैध बूचड़खानों पर रोक, एंटी-रोमियो स्क्वाड का गठन, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई (एनकाउंटर व बुलडोजर नीति), छोटे किसानों के एक लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ और एक्सप्रेसवे व औद्योगिक विकास जिसमें नोएडा फिल्म सिटी भी शामिल हैं। सीएम योगी ने मार्च 2025 में राज्य के प्रत्येक जिले में सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों को उत्सव के साथ जनता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। इन उत्सवों में बताया गया था कि जहां पहले यूपी का निवासी बताने का संकट था, क्योंकि यूपी की पहचान दंगाई, कातिल, डकैत, माफिया के रूप में होती थी। किसान आत्महत्या करता था, युवा बेरोजगार था, बेटी असुरक्षित थी, दंगों से लोग परेशान थे। लेकिन सरकार बदलने के बाद भाजपा के शासन में बदलाव हुआ, उसे सबने महसूस किया। योगी सरकार का उत्तर प्रदेश में समग्र विकास पर जोर है। अब यूपी कृषि प्रधान राज्य है। यूपी में अब 20 प्रतिशत अधिक खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। पीएम किसान निधि के तहत यूपी में 2.61 लाख किसानों को धनराशी मिली है। कृषि से जुड़ी कई लंबित योजनाओं को सरकार ने पूरा किया। यूपी में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई। अब यूपी में अराजकता नहीं है। बल्कि यूपी की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाई पर है। यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में काम किया है।

धामी ने दी स्थिर सरकार

उत्तराखंड राज्य के गठन के 25 वर्षों का राजनीतिक इतिहास एक ऐसे दौर की कहानी है, जहां सत्ता की निरंतरता से ज्यादा नेतृत्व परिवर्तन हावी रहा है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बनने के बाद से उत्तराखंड में कई मुख्यमंत्री बने, लेकिन नारायण दत्त तिवारी को छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। 2017 में चुनी गई भाजपा सरकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत इस उपबल्धि को छूते, उससे पहले ही 2021 में उनके कार्यकाल को चार साल पूरे होते उससे पहले ही नेतृत्व परिवर्तन हो गया। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां इशारा कर रही हैं कि एनडी तिवारी के बाद पुष्कर सिंह धामी ऐसे दूसरे लीडर होंगे, जो बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। वैसे देखा जाए तो पूर्व सीएम दिवंगत एनडी तिवारी के बाद उत्तराखंड में किसी सीएम का सबसे लंबा कार्यकाल अगर रहा है तो वो सीएम पुष्कर सिंह धामी का ही है। सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे ऐतिहासिक और सशक्त फैसले लिए, जिनसे राज्य की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है। सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, जहां यूसीसी लागू की गई। इसके साथ ही राज्य में सशक्त भू-कानून, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगारोधी कानून लागू कर कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया गया। सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। इसका परिणाम यह रहा कि बीते चार वर्षों में 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलीं, जिससे पारदर्शिता और भरोसा दोनों बढ़े हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया।अब यही प्राधिकरण पाठ्यक्रम और शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करेगा। धामी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण व्यवस्था लागू की। वहीं सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की गई। प्रदेश में 2.54 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का संकेत है। स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का बिना ब्याज ऋण देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। राज्य आंदोलनकारियों के योगदान को सम्मान देते हुए सरकारी नौकरियों में उन्हें 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। इसके साथ ही उनके आश्रितों की पेंशन 3000 से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। राज्य आंदोलन के दौरान 7 दिन जेल गए अथवा घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन 6000 से बढ़ाकर 7000 रुपये प्रतिमाह कर दी है, जो उनके संघर्ष के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। सैनिकों के सम्मान में भी बड़े फैसले लिए गए हैं। शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। वहीं परमवीर चक्र विजेताओं के लिए यह राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसके अलावा राज्य में अग्निवीर योजना के अंतर्गत सेवा देने वाले युवाओं को भी सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 चाल पूरा होने पर हल्द्वानी में रैली को संबोधिक करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल का कार्यकाल शानदार बताया। उन्होंने सीएम धामी को 'धुरंधर' और 'धाकड़' बताते हुए कहा कि धामी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जिससे भाजपा प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाने की ओर अग्रसर है। यानी साफ-साफ संकेत हैं कि धामी के चेहरे पर ही 2027 का चुनाव होने जा रहा है। ये संकेत भाजपा के उन नेताओं के लिए किसी सदमे से कम नहीं है जो पिछले चार वर्षों में यही नैरेटिव सेट करते रहे हैं कि धामी बस कुछ दिन के मेहमान है। धामी से केंद्रीय नेतृत्व नाराज है या धामी बस इस माह हटने वाले हैं। यही सुनते सुनते धामी के चार साल पूरे हो गए और अगला चुनाव भी उनके नेतृत्व में होने वाला है ऐसे संकेत भी हैं।

- **धामी के चेहरे पर ही 2027 का चुनाव होने जा रहा है, ये संकेत उन भाजपाइयों के लिए सदमा हो सतका है जो पिछले 4 वर्षों में यही नैरेटिव सेट करते रहे हैं कि धामी बस कुछ दिन के मेहमान है, धामी से हाईकमान नाराज है या धामी बस इस माह हटने वाले हैं।**
- **नरेंद्र मोदी का बतौर पीएम कार्यकाल कड़े और बड़े फैसलों के लिए जाना जाता है, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करना हो, नोटबंदी या कोरोना महामारी में स्वदेशी वैक्सीन बनाकर कई देशों की मदद करना हो, आतंकवाद के खिलाफ आपरेशन सिंदूर के साथ वैश्विक कूटनीति में मोदी का जवाब नहीं है।**

भारत में पैनिक बाइंग आम है

कोरोना काल में लॉकडाउन में लोगों ने ज्यादा से ज्यादा राशन खरीदा, नतीजा दुकानों में राशन की कमी हो गई जबकि बाद में दुकानों में पर्याप्त सामान उपलब्ध था, कोरोना काल में ही ऑक्सिजन गैस की भी जमाखोरी हुई, जिसे जरूरत नहीं थी उसके पास ऑक्सिजन गैस सिलेंडर था और जिसे जरूरत थी उसे ऑक्सिजन नसीब नहीं हुई, इसी को पैनिक बाइंग कहते हैं।

डा.वीरेंद्र पुष्पक
वरिष्ठ पत्रकार

ये भारत है जनाब यहां एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, राशन, ऑक्सिजन गैस क्या नमक तक ब्लैक में बिक जाता है। बात नवंबर 2016 की है जब एक दिन शाम को अफवाह फैली कि नमक कि शार्टेज हो गई है। बस फिर क्या था नमक खरीदने के लिए दुकानों पर भीड़ लगने लगी। हर गली मोहल्ले की दुकान के बाहर भीड़ थी। लोग नमक लेने के लिए धक्का मुक्की तक कर रहे थे। दुकानदार के बार-बार रिक्वेस्ट करने पर लोग लाइन में लगे। हर कोई अधिक से अधिक नमक खरीद कर घर में स्टॉक कर लेना चाहता था। जिनके घर पूरे महीने भर में एक पैकेट नमक का नहीं लगता था वह भी 10-20 पैकेट खरीदने के लिए उतावला था। मुनाफाखोर व्यापारियों को और क्या चाहिए? जिसके पास नमक का स्टॉक था उसने दबा लिया और लोगों के डर का फायदा उठाया। नतीजा नमक का 10 रुपये वाला का पैकेट 100 रुपये तक में बिक गया। जबकि यह स्थिति दो-तीन दिन में ही ठीक हो गई थी और सामान्य कीमत में नमक मिलना भी आरंभ हो गया था। पता चला कहीं कोई शॉर्टेज नहीं थी। ऐसे ही कोरोना महामारी के समय जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई सरकार समझाती रह गई कि सभी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें लॉकडाउन में खुली रहेंगी। सभी आवश्यक वस्तुएं दुकानों में उपलब्ध रहेंगी परंतु लोगों ने भीड़ लगाकर अधिक से अधिक राशन खरीदना शुरू कर दिया। उस समय दुकानों की भीड़ देखकर लग ही नहीं रहा था कि कहीं कोई महामारी भी है या लोगों में कोरोना का डर है। नतीजा दुकानों में सचमुच आटा चीनी इत्यादि की कमी हो गई जबकि बाद में कोरोना काल में दुकानों में पूरा समय पर्याप्त सामान उपलब्ध था। कोरोना काल में राशन ही नहीं ऑक्सिजन गैस की भी जमाखोरी हुई। जिसे जरूरत नहीं थी उसके पास ऑक्सिजन गैस का सिलेंडर था और जिसे जरूरत थी उसे ऑक्सिजन नसीब नहीं हुई। इसी को पैनिक बाइंग कहते हैं।

सपा के मुखिया अखिलेश रसोई गैस सिलेंडर को लेकर सरकार की नीति पर सवाल उठाते हैं, तो दूसरी तरफ हापुड़ में उनकी पार्टी के नेता अब्दुल रहमान के घर में 55 भरे हुए व कुछ खाली रसोई सिलेंडर पकड़े जाते हैं, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस नेता के घर से 822 सिलेंडर मिलते और एलओपी राहुल एंड कंपनी जिन्हें घर चलाने की नीति नहीं पता वो सरकार को विदेश नीति समझा रहे थे।

सरकार के कदमों से पैनिक

इस तरह की अफवाहें कौन फैलाता है जिससे ऐसी घटनाएं सामने आती है। जाहिर है मुनाफाखोर और मुनाफाखोरों के संरक्षक नेता अफवाहों को हवा देते हैं। लेकिन हर अफवाह का सच सामने आने के बाद भी लोग कुछ नहीं सीखते। 28 फरवरी को जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया कुछविपक्षी नेताओं ने अफवाह उड़ाई कि युद्ध के कारण तेल व गैस की समस्या होगी। इस अफवाह को सरकार के रसोई गैस सिलेंडर पर 60 रुपये बढ़ाने और बुकिंग की अवधि 25 दिन करने के साथ व्यावसायिक गैस पर रोक लगाने से और हवा मिली। हर किसी को लगा कि सरकार ने दाम बढ़ाने के साथ ही बुकिंग की अवधि भी बढ़ा दी है, लिहाजा अफवाह पर लोगों को यकीन होने लगा और गैस एजेंसियों के आफिस तथा गोदामों पर भीड़ उमड़ने लगी। देश में रोजाना 55 लाख रसोई गैस सिलेंडर बुक होते थे, लेकिन अफवाह के बाद यह आकंड़ा 75 लाख पहुंच गया। यानी 20 लाख सिलेंडर की अतिरिक्त बुकिंग होने लगी। इससे विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। सरकार को संदेह के घेरे में खड़ा किया जाने लगा। आशंका जताई जाने लगी कि अगर रसोई गैस की कमी नहीं है तो फिर बुकिंग की अवधि 25 दिन क्यों की गई? सिलेंडर की कीमत में एक साथ 60 रुपये की वृद्धि क्यों की गई? व्यावसायिक गैस की सप्लाई क्यों रोकी गई? इन सवालों का ठोस जबाव सरकार के पास भी नहीं था। सरकार सिर्फ यही दावा करती रही कि एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है। सरकार ने युद्ध के तुरंत बाद यह एक्शन न लिया होता तो संभव था कि पैनिक की स्थिति नहीं होती और सब सामान्य रहता। लेकिन सरकार के एक साथ तीन कदम उठाने से जमाखोरों, मुनाफाखोरों ने गैस का संकट पैदा कर उपभोक्ताओं में अफरा-तफरी मचा दी और 14 किलो गैस का सिलेंडर 1500 से 2000 रुपये तक ब्लैक में बिकने लगा।

कौन फैलाता है अफवाह

ये भी सच है कि मुनाफाखोर और कालाबाजारी करने वाले ऐसी अफवाहें अपने निजी लाभ के लिए फैलाते हैं। दसरा सच यह है कि ऐसी अफवाहें विपक्षी नेताओं द्वारा सरकार को बदनाम करने के लिए उड़ाई जाती हैं। युद्ध की स्थिति में भी लोगों को डराने और भविष्य में गैस न मिलने का डर दिखा कर कालाबाजारी करने वाले ही फायदा उठा रहे हैं। आम जनता को रसोई गैस नहीं मिल रही है, लेकिन नेताओं के ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं तो गैस सिलेंडरों का भंडार मिल रहा है। एक तरफ सपा के मुखिया रसोई गैस सिलेंडर को लेकर सरकार की नीति पर सवाल उठाते हैं, तो दूसरी तरफ हापुड़ में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल रहमान के घर में 55 भरे हुए व कुछ खाली रसोई सिलेंडर पकड़े जाते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक कांग्रेस नेता के घर से 822 एलपीजी सिलेंडर मिलने का दावा किया गया। जबकि कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एंड कंपनी सरकार पर हमलावर थी। जिन कांग्रेसियों को घर चलाने की नीति नहीं पता वो सरकार को विदेश नीति समझा रहे थे। दक्षिण दिल्ली के राजपुर खुर्द गांव में पुलिस ने छापा मारकर अवैध गैस गोदाम से 223 सिलेंडर बरामद किए। इनमें 16 भरे हुए घरेलू सिलेंडर, 45 खाली घरेलू सिलेंडर और 162 खाली कमर्शियल सिलेंडर थे। इस मामले में हितेश राठी और अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के बुलंदशहर में प्रशासन और आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने इंडेन ग्रामीण गैस एजेंसी पर छापा मारकर रसोई गैस की कालाबाजारी पकड़ी। 14 किलोग्राम के 291 और पांच किग्रा के 49 गैस सिलिंडर स्टाक में कम मिले। पूर्ति निरीक्षक एजेंसी संचालकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।

15,000 एलपीजी सिलेंडर जब्त

इसी तरह देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में कालाबाजारी और अवैध बिक्री के मामले पकड़े गए। आंकड़ों पर नजर डालें तो जमाखोरी और कालाबाजारी पर 12,000 से ज्यादा छापे मारे गए। जिसमें 15,000 से अधिक एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं। यह जानकारी पेट्रोलियम, शिपिंग और विदेश मंत्रालयों ने साझा रूप से दी। दिल्ली में करीब 600 सिलेंडर जब्त किए गए। इसी तरह,उत्तर प्रदेश में 450 इंस्पेक्शन और रेड हुई जिसमें 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू-कश्मीर में 564 रेड की गई हैं, केरल में करीब 1000 रेड और इंस्पेक्शन के दौरान डोमेस्टिक और कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश में 1200 रेड की गई हैं और करीब 1800 सिलेंडर जब्त किए गए। झारखंड के पलामू जिले में एक इमारत के बेसमेंट में विस्फोट हो जाने के बाद वहां से रसोई गैस के 43 सिलेंडर गायब होने के मामले में नौ पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। पुलिस ने बताया कि यह विस्फोट बैरिया चौक स्थित इमारत के उस बेसमेंट में हुआ, जहां रसोई गैस के 61 सिलेंडर अवैध रूप से रखे हुए थे। उत्तर प्रदेश सरकार एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए 4,816 स्थानों पर छापे मार कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी व अवैध बिक्री के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया और रसोई गैस वितरकों के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जबकि गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ 60 एफआईआर दर्ज कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

2016 में नमक ब्लैक में बिक गया, एक अफवाह के बाद जिनके घर में पूरे महीने भर में एक पैकेट नमक का नहीं लगता था वो भी 10-20 पैकेट खरीदने के लिए उतावला था, मुनाफाखोरों को और क्या चाहिए? जिसके पास नमक का स्टॉक था उसने दबा लिया और लोगों के डर का फायदा उठाया, नतीजा नमक का 10 रुपये वाला का पैकेट 100 रुपये तक में बिक गया।

उत्तराखंड में रसोई गैस की जमाखोरी, कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 78 स्थानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में चार मुकदमे दर्ज किए गए हैं और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर और अवैध रिफिलिंग से जुड़ा सामान जब्त किया गया है। गैस की किल्लत होने पर प्रमुख सचिव खाद्य एल. फैनई ने प्रदेश के सभी डीएम, जिला पूर्ति अधिकारियों और तीनों प्रमुख ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर रसोई गैस की जमाखोरी, कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके बाद राज्य में अभियान चलाकर 460 स्थानों का निरीक्षण किया। 78 स्थानों पर छापे मारे गए। छापों के दौरान 74 गैस सिलेंडर, एक कांटा और दो अवैध रिफिलिंग किट बरामद किए। एलपीजी गैस की किल्लत से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को दो हिस्सों में बांट दिया है। यानी डोमेस्टिक व कॉमर्शियल सिलेंडर। व्यावसायिक सिलेंडरों की बात करें उत्तराखंड में 1400 सिलेंडर ही होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को दिए जाएंगे। हालांकि आयल कंपनियों को 2650 सिलेंडरों की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। ताकि इमरजेंसी में अतिरिक्त सप्लाई की जा सके। कॉमर्शियल सिलेंडरों का वितरण एक साथ नहीं किया जाएगा। बल्कि जरूरत के अनुसार सप्लाई की जाएगी। ये सप्लाई सिर्फ उन्हीं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को होगी जो रजिस्टर्ड ग्राहक हैं और नियमित रूप से गैस एजेंसियों से सिलेंडर लेते रहे हैं। अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को इस प्रतिबंध से पूरी तरह बाहर रखा गया है। अस्पतालों व शैक्षणिक संस्थानों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडरों की 100 प्रतिशत सप्लाई होगी। ताकि स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा व्यवस्था पर किसी भी तरह का कुप्रभाव न हो। वहीं घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की स्थिति पर नजर डालें तो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बैकलॉग की समस्या सामने आई है। उत्तराखंड में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के वितरण को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के लागू होने के बाद तेल कंपनियों ने नई व्यवस्था के तहत जिलेवार आवंटन शुरू कर दिया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन अब शासन की एसओपी के अनुसार गैस एजेंसियों को एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करा रही हैं।

उत्तराखंड की सीक्रेट वैली

हिमालय की गोद में बसी उरगम घाटी उत्तराखंड के सबसे छिपे हुए रत्नों में से एक है, चोपटा और औली की भीड़-भाड़ तथा चार धाम यात्रा पर जाने वालों के लिए बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा से दूर, यह शांत घाटी सुंदरता, हरे-भरे घास के मैदान, घने जंगल और बर्फ से ढकी चोटियों के मनमोहक दृश्यों का दीदार कराती है।

हरिश भट्ट
रामनगर

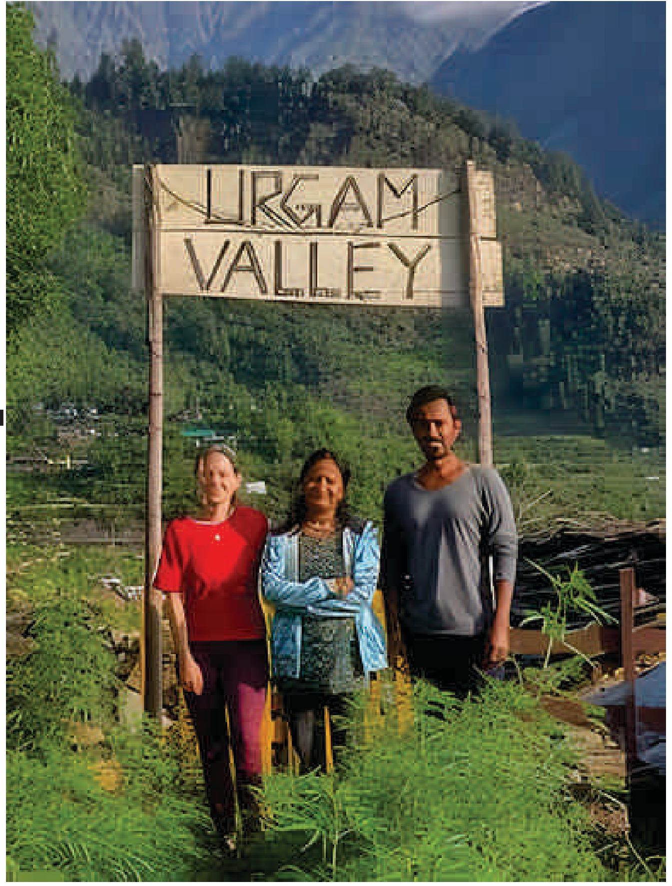

पहाड़ों की अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। पहाड़ों में रहने वाले लोगों की जिंदगी भी पहाड़ की तरह कठोर होती है। इसी पहाड़ी दुनिया की खूबसूरती को देखने के लिए देशी और विदेशी टूरिस्ट दौड़े चले आते हैं। ये पहाड़ हमें बहुत कुछ सिखाते भी हैं यानी बड़ा होने पर हमें सरल रहना चाहिए। उत्तराखंड ऐसे ही सरल और खूबसूरत पहाड़ों के लिए जाना जाता है। पर्यटक हर मौसम में उत्तराखंड की सुंदरता में कुछ दिन बिताने के लिए आते रहते हैं। इसी उत्तराखंड में ऐसे कई सीक्रेट डेस्टिनेशन हैं जिनके बारे में कम लोगों को पता है। शायद इसलिए अनजान डेस्टिनेशन अक्सर खूबसूरत होते हैं। ऐसी ही बेहद खूबसूरती वाली जगह है, उरगम वैली। हिमालय की गोद में बसी उरगम घाटी उत्तराखंड के सबसे छिपे हुए रत्नों में से एक है। चोपटा और औली की भीड़-भाड़ तथा चार धाम यात्रा पर जाने वालों के लिए बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा से दूर, यह शांत घाटी सुंदरता, हरे-भरे घास के मैदान, घने जंगल और बर्फ से ढकी चोटियों के मनमोहक दृश्यों का दीदार कराती है। नैसर्गिक सौंदर्य और शांति की तलाश करने वाले सैलानियों को इस गुमनाम उरगम घाटी में कुछ दिन बिताने चाहिए। यहां शहर के भागदौड़ वाले जीवन, शोर शराबे से दूर प्रकृति की गोद में सुकून मिलेगा। कुछ साल पहले तक उरगम घाटी की खूबसूरती सिर्फ स्थानीय लोगों और कुछ गिने-चुने ट्रेकर्स को ही पता थी। लेकिन हाल ही में यह ऑफबीट यात्रियों के ध्यान में आने लगी है। यहां की अछूती सुंदरता व्यवसायीकरण से प्रभावित पहाड़ी स्टेशनों के विपरीत, उरगम घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। यहां सैलानियों को आसानी से होमस्टे मिल जाते हैं। लेकिन यहां कोई स्टार-रेटेड होटल या रिसॉर्ट नहीं हैं। इसी वजह से घाटी की प्राकृतिक सुंदरता बरकरार है और यह जगह अपने मूल स्वरूप को बनाए हुए है।

परफेक्ट डेस्टिनेशन

साहसिक ट्रेकिंग का प्रवेश द्वार उरगम घाटी कालगंगा खाल, चंद्रशिला और तुंगनाथ की ट्रेकिंग के लिए बेस का काम करती है। उरगम घाटी में सैलानी जहां भी ठहरें, वहां से बर्फ से ढकी चोटियों वाले पहाड़ों के दर्शन कर सकते हैं। यहां से बद्रीनाथ और केदारनाथ की ट्रेकिंग भी संभव है। हिमालय की यह घाटी पारंपरिक गढ़वाली गांवों से भरी हुई है, यहां के स्थानीय निवासी मेहमानों का गर्मजोशी से आतिथ्य सत्कार करते हैं। यहां के लोग एक साधारण ग्रामीण जीवन जीते हुए मिलेंगे, जिनमें से अधिकांश स्थानीय लोग आजीविका के स्रोत के रूप में खेती पर निर्भर है। सीमित नेटवर्क कनेक्टिविटी भी इसे शांतिपूर्ण आराम के लिए आदर्श डेस्टिनेशन बनाती है। उरगम में अधिकांश होमस्टे में वाईफाई की सुविधा नहीं है, जो अपने आप में एक सुखद और दुखद दोनों ही है। यानी सैलानी यहां आकर शोर शराबे से अलग एक नई दुनिया में खुद को पाता है। यदि एकांत, प्रकृति और धीमी गति से यात्रा करना पसंद करते हैं, तो उरगम सैलानियों के लिए एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन है।

शांत जीवनशैली का आनंद ले

गढ़वाल जिले के दिल में बसा उरगम गांव, सीढ़ीदार खेतों से घिरे पारंपरिक लकड़ी के घरों का एक समूह है। यहां घूमें और स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए पहाड़ी जीवन का अनुभव करें तथा शांत जीवनशैली का आनंद लें। गांव की संकरी गलियां सदियों पुराने स्लेट की छतों वाले लकड़ी के घरों के पास से होकर गुजरती हैं। गांव छोटा है, इसलिए आप इस पूरे गांव को 1 से 2 घंटे में ही घूम सकते हैं। पर्यटन स्थलों से भरे हिमालयी गांवों के विपरीत उरगम गांव में पारंपरिक गढ़वाली वास्तुकला, सीढ़ीदार खेतों और मिलनसार स्थानीय लोगों के साथ एक अलग तरह का प्रामाणिक और अछूता आकर्षण मिलेगा। जंगलों से घिरा एक छोटा, निर्मल प्राकृतिक तालाब, उरगम कुंड स्थानीय लोगों द्वारा पवित्र माना जाता है। यह ध्यान, मेडिटेशन और फोटोग्राफी के लिए एक शांत स्थान है। स्थानीय लोगों का मानना है कि कुंड के पानी में उपचार के गुण हैं और यह भीड़-भाड़ से दूर एक शांत जगह है। उनके अनुसार यह कुंड पंच केदार कथाओं से जुड़ा हुआ है। श्रद्धालु कभी-कभी शुद्धि के लिए इसमें स्नान करते हैं। उरगम घाटी से ही उत्तराखंड के सबसे कम आंके जाने वाले ट्रेकों में से एक कालगंगा खाल ट्रेक (5-6 घंटे की राउंड ट्रिप) आपको घने जंगलों से होते हुए ले जाता है और अंत में हिमालय के मनोरम दृश्यों वाले एक शानदार घास के मैदान में पहुंचा देता है। उरगम गांव से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर यह ट्रेक मध्यम कठिनाई वाला है। जो ओक, देवदार के घने जंगलों से होकर एक खड़ी चढ़ाई के साथ शुरू होता है, फिर अल्पाइन घास के मैदानों (बुग्याल) में खुलता है। यदि मौसम साफ है तो फिर यहीं से सैलानियों को नंदा देवी, चौखंबा और केदारनाथ की चोटियों के दर्शन कराता है। तुंगनाथ-चंद्रशिला ट्रेक का बेस पॉइंट चोपटा से उरगम घाटी 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर सैलानी चुनौती के लिए तैयार हो तो यह भारत के सबसे बेहतरीन सूर्योदय ट्रेक में से एक है।

- **उरगम घाटी में सैलानी जहां भी ठहरें, वहां से बर्फ से ढकी चोटियों वाले पहाड़ों के दर्शन कर सकते हैं, यहां से बद्रीनाथ और केदारनाथ की ट्रेकिंग भी संभव है, हिमालय की यह घाटी पारंपरिक गढ़वाली गांवों से भरी हुई है, यहां के स्थानीय निवासी मेहमानों का गर्मजोशी से आतिथ्य सत्कार करते हैं।**
- **गांव की संकरी गलियां सदियों पुराने स्लेट की छतों वाले लकड़ी के घरों के पास से होकर गुजरती हैं, गांव छोटा है, इसलिए इस पूरे गांव को 1 से 2 घंटे में ही घूमा जा सकता है, पर्यटन स्थलों से भरे हिमालयी गांवों के विपरीत उरगम गांव में पारंपरिक गढ़वाली वास्तुकला, सीढ़ीदार खेतों और मिलनसार स्थानीय लोगों के साथ एक अलग तरह का आकर्षण मिलेगा।**

उरगम घाटी घूमने का अच्छा समय

हालांकि उरगम घाटी साल भर घूमने लायक जगह है, लेकिन घूमने के लिए सबसे अच्छे मौसम की या समय की बात करें तो अप्रैल से जून तक यहां का सुहावना मौसम रहता है। साफ आसमान और खिलते हुए रोडोडेंड्रोन आकर्षित करते हैं। सितंबर से नवंबर में मानसून के बाद की ताजगी, हरी-भरी हरियाली और ट्रेकिंग के लिए बेहतरीन परिस्थितियां होती हैं। दिसंबर से मार्च के बीच बर्फबारी उरगम को एक शीतकालीन वंडरलैंड में बदल देती है। जुलाई-अगस्त मानसून का मौसम होता है लिहाजा इन महीनों में यात्रा करने से बचें क्योंकि भूस्खलन से यात्रा बाधित हो सकती है। हालांकि इस दौरान आपको प्राकृतिक रंग और अकल्पनीय हरियाली देखने को मिलती है। उरगम घाटी चमोली जिले के जोशीमठ के पास में है। समुद्र तल से 2,100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस घाटी से बर्फ से ढकी हुई चोटियां साफ दिखाई देती हैं। उरगम वैली में ही कल्प गंगा नदी बहती है जो इस जगह को और भी खूबसूरत बनाती है। ये घाटी अंग्रेजी के वी के आकार की है। यहां पर कल्पेश्र मंदिर समेत कई धार्मिक स्थल भी हैं जिनको आप देख सकते हैं। उरगम घाटी से दिखाई देने वाला नजारा अमूल्य है, यहां के लोग भी बहुत प्यारे हैं जो इस जगह को सुंदर बना देते हैं। अगर आप मुसाफिर हैं तो आपको उतराखंड की उरगम घाटी जरूर जाना चाहिए। क्योंकि उरगम वैली में कई गांव आते हैं जिनमें दुमक, सलनाम, ल्यारी और देवग्राम शामिल हैं। उरगम वैली आज भी मॉडर्न लाइफ स्टाइल से कोसों दूर हैं। यहां असली पहाड़ी गांव और लोग मिलेंगे। जिनकी अपनी अलग दुनिया है। पैदल चलते हुए आपको उरगम वैली के ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिले होंगे। यहीं से हाथी पहाड़ औली के पहाड़ भी दिखाई देंगे। पहाड़ी गांवों को समझने और जानने के लिए उरगम वैली एकदम परफेक्ट जगह है। उरगम घाटी में पंच बद्री और पंच केदार दोनों के मंदिर हैं। कहा जाता है कि ध्यान बद्री में भगवान विष्णु ध्यान किया करते थे। यहीं पर पंच केदार में से एक कल्पेश्वर महादेव मंदिर है। देवों के देव महादेव शिव को समर्पित कल्पेश्वर मंदिर उरगम वैली के देवग्राम में स्थित है। पैदल ही इस जगह तक आराम से पहुंचा जा सकता है। इसी उरगम वैली में हजार साल पुराना पेड़ है। यहां के स्थानीय लोग इसे क्षेत्रपाल और भूमि रक्षक के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि जिस जगह पर नदी होती है, वहां पर देखने के लिए बहुत कुछ होता है। उरगम वैली में पहाड़ और नदी दोनों हैं तो सोचिए, ये जगह कितनी खूबसूरत होगी। पहाड़ों के बीच नदी का होना खूबसूरत होता है। आप कल्प गंगा के किनारे जाकर इस खूबसूरत नजारों को निहार सकते हैं। यहां घंटों बैठ सकते हैं या फिर पैदल-पैदल नदी किनारे चल सकते हैं। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो इसके लिए उरगम घाटी एकदम सही जगह है। यहां पर हाइकिंग, कैंपिंग और ट्रेकिंग कर सकते हैं। उरगम वैली से कई ट्रेक शुरू होते हैं। जिसमें उरगम वैली से सोना शिखर का 6 दिन का ट्रेक, पंच केदार ट्रेक और रूद्रनाथ समेत कई ट्रेक शामिल हैं। ट्रेकिंग के दौरान आपको उरगम वैली के खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। आप इनमें से किसी एक ट्रेक को अपनी क्षमता और अनुभव के हिसाब से कर सकते हैं।

उरगम वैली में कई गांव आते हैं जिनमें दुमक, सलनाम, ल्यारी और देवग्राम शामिल हैं, उरगम वैली आज भी मॉडर्न लाइफ स्टाइल से कोसों दूर है, यहां असली पहाड़ी गांव और लोग मिलेंगे, जिनकी अपनी अलग दुनिया है, पैदल चलते हुए उरगम वैली में ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिले होंगे, यहीं से हाथी पहाड़ औली के पहाड़ भी दिखाई देंगे।

गौरा देवी के याद में मेला

पहाड़ों के कल्चर और परंपरा को जानना और समझना है तो यहां के फेस्टिवल्स में शामिल होना चाहिए। पहाड़ी फेस्टिवल्स में स्थानीय लोककला, लोकनृत्य, लोकगीत, लोकवाद्य देखने को मिलेंगे। उरगम वैली में 11 दिनों को शिव पार्वती विवाह मेला होता है। इसके अलावा बंसीनारायण मेला, शिवरात्रि मेला, फालुनारायण मेला और मुखोटा डांस जैसे मेले होते हैं। इस दौरान स्थानीय लोग पहाड़ी वेशभूषा में रहते हैं जो उन पर खूब जचती है। सैलानियों को इनमें से किसी एक फेस्टिवल में जरूर शामिल होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर उरगम घाटी में चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाली गौरा देवी के नाम पर पर्यावरण एवं प्रकृति-पर्यटन मेले का आयोजन किया जाता है। गौरा देवी की स्मृति में इस मेले की शुरुआत 1998 में हुई। जून के प्रथम सप्ताह में लगने वाले मेले में हजारों महिलाएं एकत्रित होकर वन एवं पर्यावरण की रक्षा का संदेश देती हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं पर्यावरण के विषय पर प्रतियोगिताएं करते हैं, स्थानीय गढ़वाली और हिंदी भाषा में लिखे अनेक लोकगीत, लोकनृत्य, संगीत व नाटक आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। मेले में लोगों द्वारा अपने वन एवं कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। इसके अलावा घर-घर पकने वाली खाद्य सामग्री के स्टॉल भी मेले में सजते हैं। घाटी नौजवानों ने गौरा देवी के काम को जमीन पर उतारने के 'जनदेश' नाम से संगठन बनाया, जिसमें बहुत से नौजवान शामिल हैं। इन्होंने मिलकर पिलखी गांव में गौरा देवी के नाम पर एक वन तैयार किया है। जिसमें दर्जन भर प्रजातियों के वृक्ष फल-फूल हैं। इससे सीख लेकर आस-पास के आधा दर्जन गांवों में महिला संगठनों ने भी अपना जंगल लगाया है। पर्यावरण सुधार और आजीविका संरक्षण के काम में लगे हुए इन युवकों में अधिकांश गांव के प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के सदस्य भी निर्वाचित हुए हैं, ये युवा जन-प्रतिनिधि उरगम घाटी में रोड, नेटवर्क, बिजली, पानी की आपूर्ति और इको टूरिज्म के विषय पर मिलकर काम कर रहे हैं। ●

इंडिया में ईद खाड़ी में धमाके

मुस्लिम देशों ईरान, गाजा, लेबनान, संयुक्त अरब अमीरात सऊदी अरब, कतर, ओमान और बहरीन के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ईद खौफ के साये में मनाई गई, भारत में ईद का जश्न उत्साह से मनाया गया, इसलिए पाकिस्तानी भी कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ भारत में मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन कट्टरपंथी यही कहते हैं कि भारत में मुसलमान असुरिक्षत है।

उत्तरांचल दीप डेस्क

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस को दिन-रात गाली देने वाले, मुस्लिम विरोधी बताने वालों को अब समझ आ जाना चाहिए कि मुस्लिम देशों ईरान, गाजा, लेबनान, संयुक्त अरब अमीरात सऊदी अरब, कतर, ओमान और बहरीन के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बारुद बरस रहा जिससे मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार ईद-उल-फितर खौफ और डर के साये में मनाया गया। जबकि भारत में ईद का जश्न बेखौफ होकर उत्साह के साथ मनाया गया। इसलिए बहुत से भारतीय ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी मुसलमान भी कहते हैं कि दुनिया में मुसलमान जितना सुरक्षित भारत में है उतना इस्लामिक देशों में भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन चरमपंथी और कट्टरपंथी तथा वामपंथी यही कहते हैं कि भारत में मुसलमान असुरिक्षत है। हालांकि भारत में सभी प्रकार के मुसलमानों को समान और कुछ मामलों में अधिक संवैधानिक अधिकार हासिल हैं। हिंदुस्तान में 22 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। पिछले सात दशक में उनकी आबादी सर्वाधिक सात गुना से अधिक बढ़ चुकी है। ऐसे में एक अहम सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में भारतीय मुसलमान सताए जा रहे हैं? क्या वे स्वयं को 'असुरक्षित' महसूस करते हैं? इतिहास का वह कौन-सा दौर था, जब इस भारत के मुसलमानों ने खुद को पूरी तरह 'सुरक्षित' माना था? क्या गांधी और नेहरू के समय हालात अलग थे? आखिर इस 'असुरक्षा' की जड़ें कहां है? क्या 'मुस्लिम असुरक्षा' का नैरेटिव कट्टरपंथियों ने मुसलमानों के जहन में भरने का काम किया है? क्या विभाजनकारी नहीं चाहते कि भारत में मुसलमान सुरक्षित रहे? इसलिए कई बार सोशल मीडिया और जलसों में कट्टपंथी मोदी सरकार तथा भाजपा का खौफ दिखाकर विपक्षी दलों कांग्रेस, सपा और टीएमसी जैसे राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक तैयार करते हैं।

मिडिल ईस्ट में खौफ में मनी ईद

भारत में ईद-उल-फितर यानी मीठी ईद जोश-ओ-खरोश के साथ मनाई गई। यहां इस्लाम को मानने वालों ने ईदगाह में बेखौफ होकर खुले आसमान के नीचे ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की। जबकि खाड़ी के मुस्लिम देशों में युद्ध के कारण ईद-उल-फितर का त्योहार खौफ के साये में सादगी से मनाया गया। सुरक्षा कारणों से कई देशों सऊदी, यूएई, कुवैत और कतर की सरकारों ने खुले मैदानों या सार्वजनिक स्थानों पर जमावड़े और नमाज अदा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ईद की नमाज मस्जिदों में अदा करने की सलाह दी गई। इन देशों को हवाई हमलों का डर था। क्योंकि ईरान बिना रुके मिडिल ईस्ट में ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहा था। लिहाजा ईद पर संभावित हमलों की आशंका से लोगों में दहशत थी। हमलों की धमकियों के बीच लोगों ने बारूदी माहौल में ईद की नमाज पढ़ी। सऊदी अरब में तो ईद के आसपास 26 से अधिक ड्रोन नष्ट करने का दावा भी किया गया। खाड़ी देशों में दहशत के कारण बाजारों तक में सन्नाटा पसरा रहा। सरकार की तरफ से पारंपरिक आतिशबाजी व जश्न रद्द कर दिए गए। सबसे ज्यादा हालात खराब लेबनान में थे, जहां लोगों ने शिविरों में ईद मनाई। इन परिस्थितियों की तुलना भारत से की जाए तो यहां अमन चैन और उत्साह के साथ ईद-उल-फितर की नमाज हुई। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि भारत में बहुसंख्यक हिंदू है और हिंदू 'वसुधैव कुटुम्बकम' में विश्वास रखता है। यह भारत की प्राचीन संस्कृति है जिसका अर्थ है 'पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है।' इसलिए भारत में जहां उत्साह के साथ ईद का जश्न मनाया गया वहीं खाड़ी देशों में ड्रोन और मिसाइल से धमाके हो रहे थे। मिडिल ईस्ट में ईद की पूर्व संध्या यानी 19 मार्च से ही मिसाइल और ड्रोन हमलों से लोगों में दहशत थी।

सुरक्षा कारणों से सऊदी, यूएई, कुवैत और कतर की सरकारों ने खुले मैदानों या सार्वजनिक स्थानों पर जमावड़े और नमाज अदा करने पर प्रतिबंध लगा दिया, ईद की नमाज मस्जिदों में अदा करने की सलाह दी गई, इन देशों को हवाई हमलों का डर था, क्योंकि ईरान बिना रुके मिडिल ईस्ट में ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहा था।

पाकिस्तान को ईद मनाने की छूट मिली

गाजा और लेबनान में भी लोगों ने खौफ और अनिश्चितता के माहौल में ईद मनाई। संयुक्त अरब अमीरात में ईद की नमाज खुले मैदानों के बजाय मस्जिदों के अंदर सीमित कर दी गई। कतर और अन्य देशों में भी ईद की नमाज मस्जिदों में ही हुई। युद्ध के कारण गाजा में जरूरी सामान की भारी कमी थी। लिहाजा कई इलाकों में ईद के पारंपरिक जश्न की जगह विस्थापन और शोक का माहौल था। हालांकि सऊदी अरब, कतर और तुर्की के अनुरोध पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने ईद के अवसर पर कुछ दिनों के लिए सीज फायर की घोषणा अवश्य की। ताकि लोग शांति से ईद का त्योहार मना सकें। फिर भी अफगानिस्तान में लोग ईद के दिन भी आशंकित रहे, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ईद पर खतरा मंडराता रहा। कुल मिलाकर युद्ध के कारण इस साल मुस्लिम देशों में ईद सुरक्षा, मानवीय संकट और अनिश्चितता के बीच चुनौतीपूर्ण बन गई। ईद पर खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन दुनिया गम में है। खासकर खाड़ी के मुस्लिम देशों में कोहराम मचा हुआ है। पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है। मुस्लिम देश ही एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। पवित्र स्थलों पर भी हमले हो रहे हैं। ईरान पर अमेरिका और इजरायल लगातार बारुद बरसा रहा है। बदले में ईरान भी मुंह तोड़ जबाव दे रहा है। युद्ध लंबा खिंच रहा है और तबाही बदस्तूर जारी है। ईरान बिना रुके कतर, सऊदी, ओमान, कतर, यूएई आदि पर विध्वंसक हमले कर रहा है।

शिया समुदाय ने शोक मनाया

ईरान के कुम में अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी के स्कॉलर मौलाना जमीर जाफरी कहते हैं कि नमाज पढ़ना, लोगों से मिलना, दुआ करना ये सब जरूर करें, लेकिन इतनी शहादतों के बीच ईद पर खुशी नहीं मना सकते। जब गाजा में बच्चे मर रहे थे तब भी ईद मनाई गई, लेकिन खुशी नहीं मनाई गई थी। मुस्लिम अगर परेशान है, उन पर जुल्म हो रहे तो कैसे हम ईद की खुशी मना सकते हैं, कैसे जश्न मना सकते हैं? एहकम के मुताबिक ईद मनानी चाहिए लेकिन खुशी नहीं। इजराइल व अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने के बाद भारत में शिया समुदाय ने ईद सादगी के साथ ही मनाई। शिया धर्मगुरुओं ने इसके लिए शिया समाज को सलाह दी थी कि ईद पर गम का इजहार जरूर करें और शांति के साथ ईद मनाए। ईद मिलन जैसे कार्यक्रमों से बचा जाए, लेकिन नमाज-ए-दुआ जरूर करें। धर्मगुरुओं का कहना था कि घर में जब कोई अपना बड़ा दुनिया से चला जाता है तो ईद बस मर्जी ए मौला के लिए मनाई जाती है। ईद के दो मतलब है एक समाजी ईद और एक मजहबी ईद। समाजी ईद में नए कपड़े रोशनी, खुशियां, पकवान बनाए, शॉपिंग आदि की जाती है। वहीं मजहबी ईद में जियारत-ए-आशूरा पढ़ें, दूसरे के लिए दुआ करें, कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ें, लोगों की मदद करें, यानी इस बार सिर्फ मजहबी ईद मनाएं। अजमेर से सटे दौराई गांव में इस बार ईद-उल-फितर की रौनक नहीं, बल्कि गम का माहौल था। शिया समाज ने अपने धर्मगुरु अयातुल्ला अली खामेनेई की युद्ध में मौत की खबरों के बाद ईद न मनाने का फैसला किया था। लिहाजा ईद पर गांव में बाजार सूने रहे, लोग शोक की तैयारी में काली पट्टी बांधे रहे, रोजा मस्जिद में शोक सभा की गई। शिया समाज का कहना है कि यह समय जश्न का नहीं, बल्कि दुख और गम का है। जब खाड़ी के इस्लामी देशों में खून बह रहा है तो ईद कैसे मना सकते हैं? मुस्लिम उम्माह का अस्तित्व खतरे में है। पहला किबला यानी बैतूल मुकद्दस बंद है। दूसरा किबला भी सुरक्षित नहीं है। अमेरिका, इजरायल और सऊदी अरब इस्लाम को चुनौती दे रहे हैं। ईरान में निर्दोष मासूम बच्चियां इजरायली आक्रमण का शिकार हो गई हैं। अफगानिस्तान में अस्पताल नष्ट हो गए हैं, जिनमें निर्दोष बच्चों की भी मौत हुई हैं। इन सबके ऊपर, सर्वोच्च शिया नेता की शहादत से हर किसी के दिल में गम है। हालांकि ये गम शायद सोशल मीडिया पर ही झलक रहा था क्योंकि शिया समुदाय को छोड़ दें तो भारत में ईद का जश्न धूमधाम उत्साह और जोश-ओ-खरोश के साथ मनाया गया। केरल और तमिलनाडु में तो 20 मार्च को ही ईद का जश्न मना लिया गया था। जबकि बाकी भारत में 21 मार्च को ईद की नमाज हुई।

- **सऊदी अरब, कतर और तुर्की के अनुरोध पर पाकिस्तान व अफगानिस्तान ने ईद पर कुछ दिनों के लिए सीज फायर की घोषणा की, ताकि लोग शांति से ईद मना सकें, फिर भी अफगानिस्तान में लोग ईद के दिन भी आशंकित रहे, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ईद पर खतरा मंडराता रहा।**
- **रुद्रपुर नगर निगम और पुलिस ने ईदगाह के पास करीब 8 एकड़ सरकारी (नजूल) भूमि को दिसंबर 2025 में अतिक्रमण मुक्त कराया था, लिहाजा प्रशासन ने इस खाली कराई गई जमीन पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी, इससे पहले इस भूमि पर नमाज होती रही है, इससे नाराज नमाजियों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया।**

ऊधमसिंह नगर में ईद पर विवाद

रमजान के मुकद्दस महीने के बाद उत्तराखंड के हर कोने में ईद-उल-फितर का त्योहार अकीदत के साथ मनाया गया। सुबह से ईदगाहों में नमाज के लिए लोग पहुंचने लगे थे। ईद की नमाज के बाद देश और दुनिया में अमन चैन के लिए दुआ की गई। खासकर मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के जल्दी बंद होने की दुआ की गई। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और अमन-चैन, भाईचारे और देश की तरक्की के लिए दुआएं मांगीं। ईद पर ऊधमसिंह नगर जिले का रुद्रपुर सुर्खियों में रहा क्योंकि यहां खुशियों के त्योहार ईद पर लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। रुद्रपुर में ईदगाह खेड़ा मोहल्ले में है। 21 मार्च को ईद की नमाज के दौरान उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब मुस्लिम समुदाय ने प्रशासन के फैसले के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर ईदगाह के पास करीब 8 एकड़ सरकारी (नजूल) भूमि को दिसंबर 2025 में अतिक्रमण मुक्त कराया था। लिहाजा प्रशासन ने इस खाली कराई गई जमीन पर नमाज पढ़ने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। इससे पहले इस भूमि पर नमाज होती रही है। इससे नाराज नमाजियों ने हाथों पर काली पट्टी बांधी और काले झंडे दिखाकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि वे पिछले 50-60 वर्षों से यहां सामूहिक नमाज पढ़ते आए हैं, लेकिन प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है और अब यह नगर निगम के कब्जे में है। लिहाजा किसी को यहां नमाज की अनुमति नहीं दी जाएगा। प्रशासन ने नमाजियों को विकल्प के रूप में शहर की अन्य मस्जिदों में नमाज पढ़ने का सुझाव देकर मामले को शांत किया। ●

स्पीकर ने एलओपी की हेकड़ी निकाली

12 मार्च को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी की सारी हेकड़ी निकाल दी और उन्हें बता दिया कि संसद नियमों से चलेगी, एलओपी को भी नियमों और प्रक्रियाओं के तहत ही चलना होगा, संसद में जो विषय होगा उसी पर बोलना होगा, दांय-बांये भागने नहीं दिया जाएगा।

शालिनी चौहान
नई दिल्ली

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 11 मार्च को हंगामे के दौरान ध्वनि मत से खारिज हो गया। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद बजट सत्र के दूसरे सत्र में 12 मार्च को ओम बिरला ने आसन संभाला और लोकसभा की कार्रवाई कैसे चलेगी ये सभी सांसदों को बता और जता दिया। लेकिन राहुल गांधी हैं कि वो न तो नियम मानते हैं, न प्रक्रियाओं व परंपराओं का सम्मान करते हैं। एक तरह से राहुल गांधी बेलगाम नेता जैसा व्यवहार संसद के अंदर और बाहर करते हैं। वो लोकसभा स्पीकर पर आरोप लगाते रहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। लेकिन 12 मार्च को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी की सारी हेकड़ी निकाल दी और उन्हें बता दिया कि संसद नियमों से चलेगी। एलओपी को भी नियमों और प्रक्रियाओं के तहत ही चलना होगा। संसद में जो विषय होगा उसी पर बोलना होगा, दांय-बांये भागने नहीं दिया जाएगा। बजट सत्र में बजट पर बहस होनी थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने 'रसोई गैस की कमी' विषय पर सदन में बोलने की इच्छा जाहिर करते हुए नोटिस दिया था। लिहाजा वो उसी विषय पर बोल सकते थे। स्पीकर साफ कर चुके थे कि विषय से अलग नहीं बोलने दिया जाएगा। लेकिन खुद को सुपर पावर समझने वाले राहुल गांधी जब बोलने लगे तो एलपीजी विषय से भटक गए और अपने पसंददीदा एप्स्टीन पर आ गए। लिहाजा लोकसभा स्पीकर ने विषय से बाहर 'एप्स्टीन' पर बोलने ही नहीं दिया। यानी उनका माइक बंद कर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने स्पष्ट किया कि एलपीजी की कमी पर नोटिस के बावजूद, अन्य मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संसद में 12 मार्च की यह घटना राहुल गांधी की बेलगाम बहस पर रोक लगाने के रूप में देखी जा रही है। हालांकि राहुल गांधी मानते हैं कि वो उस परिवार से आते हैं जिसने तीन प्रधानमंत्री दिए हैं। इसलिए उन्हें कहीं भी कभी भी कुछ भी कहने बोलने का विशेषाधिकार है। इसलिए वो संसद में हमेशा विषयों से हटकर ही बोलते रहे हैं। लेकिन 12 मार्च को स्पष्ट हो गया कि अब बेलगाम नेता की नकेल कसी जा रही है। लिहाजा अब राहुल गांधी को अपने जहन से तीन प्रधानमंत्री के परिवार से आने वाले राजकुमार का भ्रम निकाल देना होगा। क्योंकि जो लोकसभा स्पीकर अभी तक विपक्षी सांसदों के साथ साहनुभूति रखते थे, वो शायद भविष्य में न रखे। यानी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अथवा विपक्षी सांसद यदि विषय से भटकेंगे तो उनका माइक बंद हो ही जाएगा।

स्पीकार ने क्यों रोका एलओपी को

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण देश में ईंधन की कथित कमी का मुद्दा उठाना चाहते थे। इसके लिए बाकायदा संसद में नोटिस भी दिया गया था। 12 मार्च को शाम करीब चार बजे राहुल गांधी चर्चा के लिए खड़े हुए और देश में एलपीजी संकट का हवाला देते हुए कहा, 'तकलीफ की शुरुआत हुई है, रेस्तरां बंद हो रहे हैं और एलपीजी की कमी हो रही है...यह तो शुरुआत है।' उन्होंने कहा कि किसी भी देश की बुनियाद ऊर्जा सुरक्षा है। भारत जैसा देश किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को यह तय करने की इजाजत कैसे दे सकता है कि 'हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं।' इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल का हवाला देते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का उल्लेख किया, जिस पर सत्तापक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई, तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि 'आपने जिस विषय पर नोटिस दिया है, उस पर बोलिए। अगर इस विषय पर बोलना है तो इसके लिए नोटिस दीजिए।' इसका विरोध करते हुए कांग्रेस सदस्यों ने सदन में 'एप्स्टीन-एप्स्टीन' और 'मंत्री इस्तीफा दो' के नारे लगाए। विपक्ष खासकर कांग्रेस सांसदों का संसद में जिस तरह का व्यवहार रहता है वो एक जनप्रतिनिधि की गरिमा को कलंकित करने वाला होता है। जिस तरह संसद में शोर शराबा किया जाता है स्पीकर के आग्रह को ठुकराया जाता है उससे लगता है कि ये संसद नहीं बल्कि किसी नौटंकी का मंच है। खैर राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं वो संसद से बाहर आए तो मीडिया ने घेर लिया। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने अपना पुराना टेप चला दिया। उन्होंने कहा कि सदन में एलपीजी का मुद्दा उठाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि आम तौर पर बोलने की अनुमति मांगने की एक प्रक्रिया होती है... मैंने तेल और एलपीजी की स्थिति के बारे में बयान देने की अनुमति मांगी थी। यह शुरुआत है, मैं इस बारे में बोलना चाहता था, लेकिन लगता है कि एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई है-पहले मंत्री निर्णय लेंगे, फिर मैं बोलूंगा और उसके बाद मंत्री जवाब देंगे।

राहुल गांधी मानते हैं कि वो उस परिवार से आते हैं जिसने तीन प्रधानमंत्री दिए हैं, इसलिए उन्हें कहीं भी कभी भी कुछ भी कहने बोलने का विशेषाधिकार है, इसलिए वो संसद में हमेशा विषयों से हटकर ही बोलते रहे हैं, लेकिन 12 मार्च को स्पष्ट हो गया कि अब बेलगाम नेता की नकेल कसी जा रही है।

पैनिक फैलाना चाहते हैं राहुल

राहुल गांधी ने ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती अनिश्चितता पर चिंता जताते हुए चेतावनी दी कि ईंधन की आपूर्ति एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। उन्होंने कहा कि असल में मुख्य बात यह है कि पेट्रोल और गैस एक बड़ी समस्या बनने वाली है। क्योंकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है। गलत विदेश नीति ने यह समस्या पैदा की है। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर नहीं की तो इसका असर देश के करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। राहुल गांधी ने यह भी सुझाव दिया कि यह मुद्दा सिर्फ इस बात से कहीं बड़ा है कि कुछ देश ईंधन की आपूर्ति की अनुमति देते हैं या प्रतिबंधित करते हैं। यह युद्ध मूल रूप से मौजूदा विश्व व्यवस्था के बारे में है। उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक भू-राजनीतिक परिवर्तन अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं, जिससे ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि ईरान ईंधन की अनुमति देगा या नहीं, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है... हम एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर रहे हैं। जब आप अस्थिर दौर में प्रवेश करते हैं, तो आपको मानसिकता बदलनी पड़ती है। मैं सरकार को यही सुझाव दे रहा हूं कि वे संभावनाओं पर विचार करें और यह सुनिश्चित करें कि हमारे लोगों को कोई परेशानी न हो। कुल मिलाकर कांग्रेस और राहुल गांधी देश में पैनिक फैलाना चाहते हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर, कंप्रोमाज, पीएम साबित किया जा सके।

संसद नियमों से चलेगी

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह संसद के बाहर कहा कि एक फिल्म आई थी जिसका नाम था 'हम नहीं सुधरेंग'। राहुल गांधी उस फिल्म के कैरेक्टर लगते हैं। 12 मार्च की सुबह स्पीकर ने 32 मिनट तक नियमों का हवाला दिया था यह कहते हुए कि सदन में हर कोई नियमों से बंधा हुआ है। एलओपी राहुल गांधी ने एलपीजी पर बोलने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने स्पीकर के निर्देशों का उल्लंघन किया। उन्हें किसानों या गांवों के लोगों के लिए एलपीजी की कोई चिंता जाहिर नहीं की। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर वे सीरियस होते, तो वे एपलीजी पर बोलते। बाद में वे दावा करेंगे कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। यह संसद है जो नियमों से चलती है। यह कांग्रेस पार्टी का ऑफिस या कैंटीन नहीं है जहां कुछ भी चलता है? आप आम जनता की बातें उठा रहे हैं, एपीजी की किल्लत की समस्या उठा रहे हैं। सरकार उसका जवाब देगी। दुबे ने कहा कि संसद अलग है, सड़क अलग है। संसद का आंदोलन अलग होता है, सड़क का आंदोलन अलग होता है। जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं उससे दिखता है कि 2047 तककांग्रेस सत्ता में वापस नहीं आने वाली है। आम जनता को कांग्रेस बेवकूफ बनाती है वह बेनकाब हो गई। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी जार्ज सोरोस का एजेंडा चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पीएम मोदी सुबह उठकर पहले ट्रंप को गाली दे, दोपहर को पुतिन को और शाम को चीन के सी जिंपिंग को गाली दे। ताकि जार्ज सोरोस का मोदी विरोधी एजेंडा कामयाब हो जाए। लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद रवि किशन का कहना था कि राहुल को वही बोलना था जो लिखकर दिया गया था, लेकिन वो भूल गए कि उन्होंने नोटिस किस विषय पर दिया है। कांग्रेस का काम देश और संसद को कन्फ्यूज करना है। जो राहुल गांधी ने समय समय पर साबित भी किया है। वो देश को बांटने, देश को कमजोर करने की कोशिश करते रहते हैं। स्कैंडल बनाने की उनकी आदत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सीनियर विपक्षी नेता होने के नाते वह किस लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं ये शायद राहुल गांधी खुद भी नहीं समझते होंगे। मिडिल ईस्ट में जब युद्ध चल रहा है दुनिया में खलबली मची है तब एलओपी को प्रधानमंत्री मोदी और देश के साथ खड़ा होना चाहिए था।

- **भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यह संसद है जो नियमों से चलती है, यह कांग्रेस पार्टी का दफ्तर या कोई कैंटीन नहीं है जहां कुछ भी चलता है? यदि आप आम जनता के लिए एपीजी की किल्लत की समस्या उठा रहे हैं तो सरकार उसका जवाब देगी, दुबे का कहना था कि संसद का आंदोलन अलग होता है, सड़क का आंदोलन अलग होता है।**
- **विपक्ष खासकर कांग्रेस सांसदों का संसद में जिस तरह का व्यवहार रहता है वो एक जनप्रतिनिधि की गरिमा को कलंकित करने वाला होता है, जिस तरह संसद में शोर शराबा और हंगामा किया जाता है स्पीकर के आग्रह को ठुकराया जाता है उससे लगता है कि ये संसद नहीं बल्कि किसी नौटंकी का मंच है।**

कांग्रेस का नैरेटिव

12 मार्च को लोकसभा अध्यक ओम बिरला के तीखे तेवर और आक्रामक कार्यशैली देखने के बाद कांग्रेस झूठा नैरेटिव गढ़ने में लग गई। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश के आर्थिक फैसले वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लिए जा रहे हैं। यह हमारा देश क्यों स्वीकार कर रहा है, हिंदुस्तान के हक की रक्षा करने के लिए कौन है? हुड्डा ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी हमारे देश की सरकार की थी और आज वो ट्रंप के सभी फैसलों को कैसे स्वीकार कर रही है जिन फैसलों से नुकसान हो रहा है। देश की तेल सुरक्षा पर प्रश्न चिह्न लग गए हैं। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि यही वह बात है जो बार-बार उठाई गई है कि एलओपी को बोलने नहीं दिया जाता। जब भी वह कुछ कहने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। उन्हें हमेशा टोका जाता है। हमेशा यही होता है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि राहुल गांधी कायदे-कानून, नियम के अनुसार गैस की कमी के मुद्दे को उठाना चाहते थे। वो उस मुद्दे को ही उठा रहे थे और अपनी बात कहना चाह रहे थे। लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया, बीच में ही रोक दिया गया। अगर वो भी अपनी बात पूरी तरह से नहीं रख सकते हैं तो आखिर फिर कौन बोलेगा? लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि देश में एनर्जी का संकट है। हमारे पेट्रोलियम मंत्री पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड हैं। यही बात राहुल गांधी ने सबूतों के साथ कही है। राहुल गांधी को सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। वह लोगों को सच बताएंगे। कांग्रेस के ये वो नेता है जो राहुल के झूठे नैरेटिव को विस्तार देते हैं।

भाजपा का फोकस मालवा निमाड़ पर ?

मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में निमाड़ के बड़वानी जिले की नागलवाड़ी में कैबिनेट बैठक का आयोजन करके राजनीतिक गलियारों में एक बार पुनः निमाड़ मालवा को सुर्खियों में ला दिया है, लिहाजा इसके राजनीतिक निहितार्थ भी तलाशे जाने लगे हैं।

आलोक एम इंदौरिया
विश्लेषक एंव स्तंभकार

आला कमान समेत मध्य प्रदेश भाजपा का पूरा फोकस इन दोनों निमाड़ मालवा अंचल पर ही क्यों है? इसे लेकर राजनीतिक हल्कों में सरगर्मियां तेज है। भाजपा की प्रतिद्वंदी कांग्रेस न केवल इस पर पैनी नजर रख रही है बल्कि वह भी मालवा निमाड़ को रिझाने में कोई कोर कसर बाकी इसलिए नहीं रख रही क्योंकि एक समय यह क्षेत्र उसका गढ़ हुआ करता था। भाजपा समेत लगभग सभी पार्टियां इस बात को बखूबी जानती है कि भोपाल की सत्ता का रास्ता निमाड़ मालवा से होकर ही जाता है और विधायक संख्या बल के साथ आर्थिक संसाधनों में यह इलाका मध्य प्रदेश का सबसे सशक्त इलाका है, इसमें दो मत नहीं है। शायद यही वह बड़ा कारण है जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केवल अपनी पूरी कैबिनेट को निमाड़ के बडबानी में पहुंचाया बल्कि निमाड़ मालवा की जनता जनार्दन को भरोसे में लेने का जोर का दम लगाकर प्रयास भी किया। यह इस कारण भी महत्वपूर्ण है क्योंकि निमाड़ मालवा की मध्य प्रदेश विधानसभा में लगभग 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

राजनीति का इतिहास गवाह है

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में निमाड़ के बड़वानी जिले की नागलवाड़ी में कैबिनेट बैठक का आयोजन करके एक बार पुनः निमाड़ मालवा को सुर्खियों में ला दिया है, लिहाजा इसके राजनीतिक निहितार्थ भी तलाशे जाने लगे हैं। दरअसल निमाड़ मालवा वह अंचल है जो मध्य प्रदेश में सत्ता की तकदीर लिखने का सामर्थ रखता है और अब तक का विभाजित मध्य प्रदेश का राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है की मालवा ने जिस पर मोहर लगाई है सत्ता का ताज उसी पार्टी के सर पर सजा है। यूं तो मध्य प्रदेश में सत्ता के 6 केंद्र हैं, जो निमाड़ मालवा, मध्य भारत, बुंदेलखंड, बिंध्य, महाकौशल और ग्वालियर चंबल के नाम से जाने जाते हैं। इसमें यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों का इन्हीं 6 जोन में बंटवारा होता है। जहां तक मालवा निमाड़ का प्रश्न है तो इस क्षेत्र में दो संभाग आते हैं। इस संभाग में कुल 66 विधानसभा सीटें हैं जो कुल विधानसभा सीटों का लगभग 30 प्रतिशत बैठता है। अब जाहिर सी बात है कि यह अकेला अंचल सत्ता के लिहाज से कितना ताकतवर है। मध्य भारत के सियासी गणित को देखें तो यह भी दो संभागों के तहत आता है और कल 36 विधानसभा सीट इसमें आती हैं। महाकौशल क्षेत्र में लगभग 38 सीट आती है और जबलपुर इसका एक तरह से राजनीतिक केंद्र माना जाता है। ठीक इसी तरह विंध्य क्षेत्र में करीब 30 सीट आती है और इसकी सत्ता का केंद्र बिंदु रीवा सतना है। बुंदेलखंड में लगभग 26 विधानसभा सीट आती है और सागर इसका केंद्र है इसी तरह ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति का केंद्र बिंदु ग्वालियर है जहां कुल 34 विधानसभा सीट हैं।

मध्य प्रदेश में सत्ता के 6 केंद्र हैं, जो निमाड़ मालवा, मध्य भारत, बुंदेलखंड, बिंध्य, महाकौशल और ग्वालियर चंबल के नाम से जाने जाते हैं, मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों का इन्हीं 6 जोन में बंटवारा होता है, जहां तक मालवा निमाड़ का प्रश्न है तो इस क्षेत्र में दो संभाग आते हैं, इस संभाग में कुल 66 विधानसभा सीटें हैं।

कांग्रेस व भाजपा के लिए महत्वपूर्ण

मध्य प्रदेश विधानसभा के राजनीतिक भूगोल को समझने के बाद यह स्पष्ट होता है की मालवा निमाड़ भाजपा के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यदि 2013 और 2018 के विधानसभा चुनावों के नतीजे को टटोलें तो जहां 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मालवा निमाड़ में एक तरफ खेलते हुए 66 में से 57 सीटों पर कब्जा जमाया था वहीं कांग्रेस के खाते में सिर्फ 9 सीट आई थी, नतीजा भारतीय जनता पार्टी ने बपंर बहुमत से सरकार बनाई थी। मगर 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सत्ता से बाहर होने का सबसे बड़ा कारण मालवा निमाड़ ही रहा था, क्योंकि यहां पर कांग्रेस ने 35 सीटों पर जीत दर्ज की थी और भाजपा के खाते में केवल 28 सीट आई थीं लिहाजा 15 साल बाद कांग्रेस प्रदेश की सत्ता में वापसी करने में सफल रही थी। भाजपा आला कमान और नेतृत्व ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया जिसके चलते एक खास रणनीति बनाई गई और 2023 के चुनाव में मालवा निमाड़ की 66 सीटों में से 48 सीटों पर भाजपा कब्जा जमाने में सफल रही। नतीजा मध्य प्रदेश में भाजपा ने मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार बना ली वह भी बंपर बहुमत से। मालवा निमाड़ का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मालवा-निमाड़ से आते हैं वही कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी इसी क्षेत्र से आते हैं, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मालवा निमाड़ से ही आते हैं। खास बात तो यह भी है कि मालवा निमाड़ का मुख्य स्थान माना जाने वाला इंदौर महानगर के प्रभारी मंत्री भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ही है। यानी मालवा निमाड़ भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है इसे सहज ही समझा जा सकता है।

आदिवासी निर्णायक भूमिका में

दरअसल मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लिए कुल 47 सीट आरक्षित हैं जिसमें अधिकतर मालवा निमाड़ में आती है और 2018 में राज्य की इन 47 आरक्षित सीटों में से भाजपा के हिस्से में केवल 16 सीट आई थी। जबकि कांग्रेस ने 30 सीटों पर कब्जा किया था। मगर 2023 में अपनी बदली रणनीति के कारण भाजपा ने आरक्षित एसटी सीटों पर अपनी संख्या बढ़ा ली थीं। वैसे भी जनजाति (आदिवासी) वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों में से 22 सीटें मालवा निमाड़ में आती है जो कुल विधानसभा सीटों का लगभग 47 प्रतिशत होता है। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक लगभग 19 से 20 प्रतिशत है जो सत्ता के लिए निर्णायक की पोजीशन में होता है। भाजपा इस

- **मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लिए कुल 47 सीट आरक्षित हैं जिसमें अधिकतर मालवा निमाड़ में आती है और 2018 में राज्य की इन 47 आरक्षित सीटों में से भाजपा के हिस्से में केवल 16 सीट आई थी, जबकि कांग्रेस ने 30 सीटों पर कब्जा किया था, मगर 2023 में अपनी बदली रणनीति के कारण भाजपा ने इन आरक्षित सीटों पर बाजी पलट दी थी।**
- **भाजपा और कांग्रेस में क्या अंतर है? कांग्रेस चुनाव से पांच-छह महीने पहले सक्रिय होती है जबकि मध्य प्रदेश भाजपा ने तो 2026 में ही 2028 की तैयारी शुरू कर दी है, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव एक-एक सीट का गणित बैठाने में लगे हैं, इसलिए विपक्षी भी मानते हैं कि भाजपा रणनीति बनाकर चुनाव की तैयारी करती है, इसलिए जीतती है।**
- **कांग्रेस की बड़ी कमजोरी नेतृत्व है, यानी नेतृत्व कर कौन रहा है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन वो हर फैसला कांग्रेस हाईकमान से पूछ कर लेते हैं, अब हाईकमान कौन है, क्या गांधी परिवार है तो फिर गांधी परिवार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा में से कौन हाईकमान है? यही भ्रम कांग्रेस की कमजारी है।**

वोट बैंक को साधने का जी तोड़ प्रयास कर रही है। हालांकि सभी राजनीतिक दल इस बात को बखूबी समझते और जानते हैं कि बिना आदिवासी वर्ग की सपोर्ट के सरकार बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। बरहाल भाजपा ने मध्य प्रदेश में मिशन 2028 पर काम शुरू कर दिया है। इसका आरंभ मालवा निमाड़ से करके इसे एक तरह से सत्ता का केंद्र बिंदु बना दिया है। इस क्षेत्र में जहां कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है वहीं जयस नामक आदिवासी संगठन ने भी मालवा में अपनी जबरदस्त पकड़ बना ली है। इन हालातों में भाजपा को चुनौती नहीं होगी ऐसा सोचना शायद गलत होगा। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में वनवासी कल्याण परिषद और सेवा भारती ने ग्राउंड लेवल पर बहुत काम किया है जिसका परिणाम 2023 में भाजपा को मिला इसमें जहां शिवराज का योगदान रहा था तो वही ज्योतिरादित्य सिंधिया के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि मालवा पर सिंधिया राजघराने की आज भी पकड़ है। मध्य प्रदेश की सत्ता की कुर्सी पर बारास्ते मालवा निमाड़ ही कब्जा जमाया था सकता है यह सोलह आने सच है और शायद इसलिए मोहन यादव ने मालवा निमाड़ पर जबरदस्त फोकस करके इसे अपना अभेद्य गढ़ बनाने और 2013 वाले नतीजों को दोहराने पर काम शुरू कर दिया है। ताकि बहुमत की आधी सीटें अकेले निमाड़ मालवा से हासिल करके भाजपा 2028 की फतेह सुनिश्चित कर सके।

भाजपा का मिशन 2028 शुरू

भाजपा और कांग्रेस में क्या अंतर है? कांग्रेस चुनाव से पांच-छह महीने पहले सक्रिय होती है। जबकि मध्य प्रदेश भाजपा ने तो 2026 में ही 2028 की तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव एक-एक सीट का गणित बैठाने में लगे हैं। इसलिए विपक्षी भी मानते हैं कि भाजपा रणनीति बनाकर चुनाव की तैयारी करती है, इसलिए जीत हासिल करती है। वहीं कांग्रेस चुनाव से कुछ महीने पहले चुनावी मैदान में उतरती है, उसके पास न तो कोई रणनीति होती और न ही चुनावी गणित होता है। कांग्रेस राजनीति में अपनी लकीर बड़ी करने के बजाए भाजपा की लाकीर छोटी करना चाहती है, यही उसकी सबसे बड़ी नाकामी होती है। वैसे भी बाकी साढ़े चार साल कांग्रेस और जनता के बीच नाम मात्र का रिश्ता रहता है। लिहाज चुनाव में जब शर्मनाक हार का मुंह देखते हैं तो यही कांग्रेसी चिल्लाते हैं वोट चोरी हो गया। ईवीएम, चुनाव आयोग पर भेदभाव का आरोप लगाते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभी सोई हुई है जब तक उठेगी भाजपा अपना काम कर चुकी होगी। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस का नेतृत्व बहुत बड़ा लापरवाह है? क्या जिस पार्टी का नेतृत्व लापरवाह होता है उस दल के कार्यकर्ता भ्रमित नहीं रहते हैं? क्योंकि नेतृत्व का काम होता है कि वो पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश भरे, उन्हें जनता से संवाद करने के लिए तैयार करे। नेतृत्व का काम होता है कि वो साझा लक्ष्य निर्धारित कर उसे हासिल करने के लिए टीम को प्रेरित, उसका मार्गदर्शन करे, संगठित करे। नेतृत्व अपनी दूर दृष्टि से भविष्य की योजना निर्धारित करे, प्रभावी संचार के माध्यम से टीम से लगातार संपर्क में रहे, चुनौतीपूर्ण समय में निर्णय लेकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए, नेतृत्व का उद्देश्य सिर्फ आदेश देना नहीं, बल्कि सशक्त टीम बनाकर उसे लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करना भी होता है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व के पास यह सब करने का समय नहीं है। पहले तो कांग्रेस में यही नहीं पता कि नेतृत्व कर कौन रहा है। क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन वो हर फैसला कांग्रेस हाईकमान से पूछ कर लेते हैं। अब हाईकमान कौन है, क्या गांधी परिवार है तो फिर गांधी परिवार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा में से कौन हाईकमान है? यही भ्रम कांग्रेस की कमजारी है।

अब क्या होगा मोनालिसा का ?

मोनालिसा पहली महिला नहीं है जिसे रातों रात प्रसिद्धि मिली और वो उसे संभाल नहीं पाई, इससे पहले रेलवे स्टेशन पर गीत गा कर भीख मांगने वाली रानू मंडल भी अचानक रातों रात सेलिब्रिटी बन गईं थी, लेकिन, प्रसिद्धि के दबाव, व्यवहार में बदलाव और मीडिया की चकाचौंध को संभाल नहीं पाई और जल्द ही गुमनामी के अंधेरे में लौट गईं।

डा.भारत भूषण
आईएफटीएम्यू

प्रयागराज महाकुंभ-2025 में रुद्राक्ष की माला बेचते वायरल हुई मध्य प्रदेश की मोनालिसा भोसले की शादी की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। मोनालिसा भोसले ने केरल में अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान से पहले कोर्ट मैरिज की और फिर हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार केरल के तिरुवनंतपुरम के पास पूवर क्षेत्र में अरुमानूर श्री नैनार देवा मंदिर में एक-दूसरे को माला पहनाकर शादी कर ली। अचानक हुई इस शादी ने हर किसी को चौंका दिया है। सबसे बड़ा झटका उस फिल्म के निर्देशक सनोज मिश्रा को लगा है, जो मोनालिसा भोसले को अपनी फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' के जरिए बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। एक झटका मोनालिसा के परिवार को भी लगा है। जिन्हें बेटी से ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं थी। मोनालिसा भोसले मध्य प्रदेश के खरगोन की रहने वाली है और बंजारा समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। जबकि फरमान खान यूपी के बागपत का रहने वाला है, दोनों के धर्म अलग है, इसलिए दोनों परिवारों ने इस शादी का कड़ा विरोध किया फिर भी दोनों ने अपने-अपने परिवारों के खिलाफ जाकर शादी की और साथ रहने का फैसला किया। फरमान महाराष्ट्र में एक्टिंग और मॉडलिंग करता है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में छोटे-छोटे रोल किए हैं। तमिल और हिंदी फिल्मों में काम किया है। उसकी एक मलयालम फिल्म आने वाली है, जिसके डायरेक्टर जोशुआ हैं। हालांकि फरमान कोई बड़ा या चर्चित नाम नहीं है। मोनालिसा पहली महिला नहीं है जिसे रातों रात प्रसिद्धि मिली और वो उसे संभाल नहीं पाई। इससे पहले रेलवे स्टेशन पर गीत गा कर भीख मांगने वाली रानू मंडल भी अचानक रातों रात सेलिब्रिटी बन गईं थी। लेकिन, प्रसिद्धि के दबाव, व्यवहार में बदलाव और मीडिया की चकाचौंध को संभाल नहीं पाई और जल्द ही गुमनामी के अंधेरे में लौट गईं। अंजलि अरोड़ा यानी कच्चा बादाम गर्ल को सोशल मीडिया को स्टार बनाया, लेकिन इनमें से अधिकांश की प्रसिद्धि बहुत अल्पकालिक रही। बाबा का ढाबा कांता प्रसाद- हालांकि यह महिला नहीं, लेकिन एक प्रमुख उदाहरण है जहां रातों-रात मिली प्रसिद्धि और भारी दान को संभालने में वे असमर्थ रहे और जल्द ही वापस पहले जैसी आर्थिक स्थिति में चले गए। मोनालिसा की तरह ही, रानू मंडल और कच्चा बादाम गर्ल जैसे मामलों ने यह साबित किया है कि इंटरनेट पर मिली प्रसिद्धि बहुत अस्थिर और अल्पकालीन होती है।

प्रयागराज महाकुंभ मेले में मोनालिसा से जब शादी के बारे में पूछा गया था तो वह वीडियो में कह रही थीं कि मम्मी-पापा ने जो पसंद से ढूंढा होगा वही अच्छा होगा। क्योंकि मम्मी पापा की पसंद का ज्यादा अच्छा रहेगा, अपनी पसंद से शादी करना अच्छा नहीं है, हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है।

दौलत और शोहरत नहीं पची

महाकुंभ मेले में वायरल हुई मोनालिसा को कोई नागिन कहता था तो कोई नीली आंखों वाली बंजारन। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा की इस प्रसिद्धि में संभावनाएं खोजी और दस करोड़ का लोन लेकर निकल पड़े मणिपुर डायरी फिल्म बनाने। एक साधारण बंजारन जिसे न बोलना आता था, न पढ़ना लिखना, न ही कपड़े पहनने का सलीका था...। उसके लिए सनोज मिश्रा ने टीचर्स बुलाए, बॉलीवुड का रहन सहन सिखाया, जगह-जगह फीता काटने, जगरातों, शादी पार्टी में ले जाकर बदली हुई मोनालिसा को सबसे मिलवाना पर ये सब कुछ इतना सरल नहीं था। क्योंकि रानू मंडल और कच्चा बादाम गर्ल के साथ भी यही रातों रात प्रसिद्धि मिलने जैसा हादसा हो चुका था। जिसने कभी दो रोटी ठीक से नहीं खाई हो वो प्रसिद्धि को कैसे पचा सकता है। कोई व्यक्ति जो हजार ठोकरें खाने के बाद जब किसी मुकाम पर पहुंचता है तो वहां टिके रहने का हुनर सीख चुका होता है लेकिन एक रात में बने स्टार में आप चाहकर भी यह हुनर नहीं भर सकते। हां मोनालिसा थोड़ा लम्बा चल गई और पिछले एक साल में 5 लाख फॉलोअर्स कमा लिए, तारीफें बटोर लीं, बॉलीवुड की पार्टियों की चकाचौंध देख ली, पर हाल ही में केरल में एक मुसलमान लड़के से शादी कर के अपने ही परिवार, धर्म और लोगों के खिलाफ पुलिस प्रोटेक्शन मांग रही है। असल में इंसान की महत्वकांक्षाएं और सफलता की भूख इस बात पर भी निर्भर करती है कि जीवन में उसने कितना और क्या देखा है। क्योंकि एक करोड़पति व्यक्ति अरबपति बनने के सपने देखता है और अपना धन, समय, हुनर सोच समझकर खर्च करता है जबकि एक दिहाड़ी के श्रमिक को आप एक लाख रुपये दे दो तो वो उन्हें बस कुछ दिन में अच्छे कपड़े, खाना, घूमना फिरना और अमीर दिखने के शौक पर खर्च करके वापस सड़क पर आ जाता है। ऐसा ही पहले रानू मंडल के साथ हुआ था और अब मोनालिसा भोसले के साथ हो रहा है। निश्चित ही ये दौलत और शोहरत को संभाल नहीं पाई। उसका भविष्य क्या होगा? क्या वो बॉलीवुड में टिक पाएगी या फिर से रुद्राक्ष की माला बेचने के लिए मेलों में भटकती मिलेगी? क्योंकि सनोज मिश्रा तो अपनी फिल्म के लिए विकल्प तलाश लेंगे, लेकिन मोनालिसा के पास क्या विकल्प होगा?

फिल्म निर्देशक कर्ज में फंसा

मोनालिसा की शादी की खबर सामने आने के बाद फिल्म के निर्देशक सनोज मिश्रा लगातार सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने पहले एक पोस्ट के जरिए इस पूरे मामले को 'बगावत नहीं बल्कि लव जिहाद' बताया और आरोप लगाया कि मोनालिसा के मैनेजर ने उसका सौदा किया है। फिल्म निर्देशक ने नया वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। 'सिर तन से जुदा' करने की धमकी दी जा रही है। कुछ कट्टरपंथी लोग उन्हें चुप रहने का दबाव बना रहे हैं। वीडियो में वे कहते हैं कि अगर उन्हें आवाज दबानी होती तो वे धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर फिल्म बनाने का फैसला ही नहीं करते? उनकी फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में मोनालिसा को मुख्य भूमिका के लिए चुना था। निर्देशक ने यह भी दावा किया कि इस फिल्म को रोकने के लिए पहले भी कई साजिशें रची गईं। कुछ लोगों ने उन्हें झूठे मामले में जेल भिजवाने की कोशिश भी की थी। लेकिन वे जेल से बाहर आने के बाद फिल्म को पूरा करने में जुटे रहे। अब मोनालिसा की शादी के बाद पैदा हुए विवाद ने फिल्म के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सनोज मिश्रा का कहना है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए करीब 10 करोड़ रुपये का कर्ज लिया हुआ है। अगर फिल्म पर इस विवाद का नकारात्मक असर पड़ा तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने चिंता जताई कि कहीं यह कर्ज उनकी जिंदगी को संकट में न डाल दे। वहीं निर्देशक ने मोनालिसा की शादी को लेकर कई सवाल भी उठाए। उनका कहना है कि अगर यह प्रेम संबंध होता तो उसके परिवार या आसपास के लोगों को पहले से इसकी जानकारी होती।

मोनालिसा का पुराना वीडियो वायरल

मोनालिसा भोसले का एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी शादी को लेकर कहती हैं कि वो परिवार की मर्जी से ही शादी करेंगी। महाकुंभ मेले में मोनालिसा से जब शादी के बारे में पूछा गया था तो वह कह रही थी कि मम्मी-पापा ने जो पसंद से ढूंढा, वही अच्छा है। क्योंकि मम्मी पापा की पसंद का ज्यादा अच्छा रहेगा। अपनी पसंद से शादी करना अच्छा नहीं है। हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है। वहीं शादी कब करने के सवाल पर मोनालिसा ने कहा था कि 21 साल की उम्र में। इस वीडियो पर लोगों ने खूब मजाक उड़ाया है। एक यूजर ने कमेंट में लिखा, फिल्म इंडस्ट्री में एक ही जमात के लोग हैं उनसे ही शादी करेगी। दूसरे यूजर ने लिखा, इसने तो मम्मी पापा के बिना सहमति से कर ली शादी। तीसरे यूजर ने लिखा, ये गरीब ही अच्छी थी। मोनालिसा और फरमान की बातचीत करीब डेढ़ साल पहले फेसबुक से शुरू हुई थी। धीरे-धीरे दोस्ती रोमांटिक रिश्ते में बदली। फरमान का दावा है कि पहले मोनालिसा ने प्रपोज किया, जिसे उन्होंने शुरुआत में ठुकरा दिया, लेकिन छह महीने बाद वह रिश्ते के लिए मान गए। इसके बाद दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। हालांकि दोनों की उम्र में आठ साल का अंतर है। मैरिज सर्टिफिकेट के मुताबिक, मोनालिसा का जन्म 01 जनवरी 2008 को हुआ है। इस हिसाब से वह 18 साल की हो गई हैं। वहीं सिर्टिफिकेट में फरहान के जन्म की तारीख 11 जून 2000 लिखी है। इस हिसाब से उनकी उम्र करीब 26 साल होने वाली है। दोनों की उम्र में 8 साल का एक बड़ा अंतर है। मैरिज सर्टिफिकेट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर दोनों की उम्र को लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। एक बहस मोनालिसा के नाबालिग होने पर भी छिड़ी है। क्योंकि 2025 के महाकुंभ में खुद मोनालिसा ने अपनी उम्र 16 साल बताई थी। सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि मोनालिसा के दो आधार कार्ड हैं इसमें से एक में उसकी उम्र 18 साल है। जबकि दूसरे आधार कार्ड के मुताबिक वो नाबालिग है।

नीली आंखों वाली वायरल गर्ल मोनालिसा दौलत और शोहरत को संभाल नहीं पाई, अब उसका भविष्य क्या होगा? क्या वो बॉलीवुड में टिक पाएगी या फिर से रुद्राक्ष की माला बेचने के लिए मेलों में भटकती नजर आएगी? क्योंकि सनोज मिश्रा तो अपनी फिल्म के लिए विकल्प तलाश लेंगे, लेकिन मोनालिसा के पास क्या विकल्प होगा?

बेटी के साथ लव जिहाद हुआ

मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले का दावा है कि वो अपनी पसंद के लड़के से मोनालिसा की शादी करना चाहते थे, लेकिन बेटी ने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद फरमान और मोनालिसा केरल चले गए और वहां शादी कर ली। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले काफी भावुक नजर आ रहे हैं उनका कहना है कि प्रयागराज महाकुंभ के बाद जब कुछ लोग उनकी बेटी के पास आए थे तो उन्होंने एक्टिंग और काम के मौके की बात की थी। उन्हें लगा था कि इससे उनकी बेटी को पहचान मिलेगी और परिवार व समाज का नाम भी रोशन होगा। वीडियो में वह कह रहे हैं, मुझे लगा था कि वो लोग उसे एक्टिंग के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि उसने मुस्लिम से शादी कर ली। पिता की आवाज में दुख और हैरानी साफ झलक रही है। उनका कहना था कि मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि बेटी इस तरह अचानक शादी कर लेगी। जयसिंह भोसले ने अपनी बेटी को सुरक्षित वापस लाने की मांग करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ लव-जिहाद हुआ है। जय सिंह भोसले का कहना है कि वो केरल में बेटी के साथ था, लेकिन शादी से पहले ही कुछ लोगों ने उसे वहां से भगा दिया। मोनालिसा खुद अपने प्रेमी फरमान के साथ तिरुवनंतपुरम के थंपानूर पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस अधिकारी से पिता की शिकायत करते हुए कहा कि वो अपने पिता के साथ नहीं जाएगी और अपने बॉयफ्रेंड से शादी करेगी। ●

दुनिया के लिए ट्रंप खतरा

युद्ध छेड़कर ट्रंप ने हासिल क्या किया? क्या ट्रंप ने दुनिया को संकट में नहीं डाल दिया? ट्रंप की वजह से दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है, महंगाई आसमान छूने को तैयार है, इससे साबित होता है कि ट्रंप दुनिया के लिए खतरा बन गए हैं, वो जब चाहते हैं युद्ध शुरू कर दुनिया को संकट में डाल देते हैं और जब चाहते हैं युद्ध से पीठ दिखाकर भाग जाते हैं।

अतुल सिन्हा
टीवी जर्नलिस्ट

ईरान के साथ युद्ध छेड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे फंसे कि पहले एक तरफा सीज फायर की घोषणा की और अगले दिन जीत का ऐलान कर दिया। लेकिन न तो सीज फायर हुआ और न ही अमेरिका की युद्ध में जीत हुई। बल्कि अमेरिका युद्ध का मैदान छोड़ कर भाग गया और ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बैस तथा इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि युद्ध छेड़कर डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल क्या किया? क्या ट्रंप ने दुनिया को संकट में नहीं डाल दिया? ट्रंप की वजह से दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है, महंगाई आसमान छूने को तैयार है। ये सारे हालात साबित करते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के लिए क्या खतरा नहीं बन गए हैं? क्योंकि वो जब चाहते हैं युद्ध शुरू कर दुनिया को संकट में डाल देते हैं और जब चाहते हैं युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। इसलिए दुनिया अब अमेरिका को भरोसा करने लायक देश नहीं मान रही है। 23 मार्च को ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि वो ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले करेगा, बदले में ईरान ने ट्रंप को चेतावनी दी कि यदि उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो वो खाड़ी देशों को बिजली और पानी के लिए तरसा देगा। ईरान की चेतावनी के बाद, युद्ध के 24वें दिन ट्रंप ने ऐलान किया कि वो 5 दिन तक ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं करेगा। यही नहीं ट्रंप ने दावा किया कि ईरान से शांति बहाली के लिए सकारात्म बात हो रही है। लेकिन ईरान में किससे बात हो रही है कहां हो रही है इसका जवाब ट्रंप मिडिया को नहीं दे पाए। बस आदतन एक ओर दावा किया कि जल्दी ही अच्छे नतीजे सामने आएंगे। लेकिन ईरान संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए किसी से कोई बात नहीं हो रही है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया कि उनके दूत चुपचाप ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ को संभावित पार्टनर बनाने पर काम कर रहे हैं और उन्हें भविष्य के नेता के रूप में देख रहे हैं। जबकि ईरान पहले दिन से ही दो टूक कह रहा है कि युद्ध अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया है लेकिन खत्म ईरान की शर्तो पर होगा। फिर भी ट्रंप ने 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिये ईरान पहुंचाया। पहले युद्ध रुकवाने की सुपारी ट्रंप लेते थे लेकिन अब भिखारी पाकिस्तान भी युद्ध में मध्यस्थता की सुपारी लेने लगा है। पाकिस्तान ने ही युद्ध खत्म कराने की पेशकश की थी। ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है।

शांति बहाली के बीच शर्तें

अमेरिका ने शांति के लिए 15 शर्तें रखी है। इनमें पहली ईरान को अपनी सभी परमाणु क्षमताओं को नष्ट करना होगा। ईरान अपनी धरती पर यूरेनियम संवर्धन का काम पूरी तरह बंद करेगा। ईरान को लिखित और स्थाई प्रतिबद्धता देनी होगी कि वह कभी भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह फ्री मैरीटाइम जोन घोषित करना होगा। बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज और स्टॉक पर सख्त सीमाएं तय होंगी। ईरान को मिडिल ईस्ट में सक्रिय अपने सहयोगी गुटों हिजबुल्लाह, हूती और हमास को हथियार और पैसा देना बंद करना होगा। इस पूरे समझौते पर विस्तार से बात करने के लिए अमेरिका ने 30 दिनों के सीज फायर का प्रस्ताव दिया है। अगर ईरान ये शर्तें मानता है, तो अमेरिका उस पर लगे सभी परमाणु प्रतिबंध हटा लेगा। ईरान को बुशहर रिएक्टर जैसे शांतिपूर्ण कार्यों के लिए सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम चलाने में मदद दी जाएगी। स्नैपबैक मैकेनिज्म को हटा दिया जाएगा, जिससे प्रतिबंध दोबारा अपने आप लागू नहीं होंगे। अमेरिकी शर्तो के बदले में ईरान ने साफ साफ कहा कि सीज फायर तो ईरान की शर्तो पर ही होगा। ईरान की पहले तीन शर्त थी, लेकिन ट्रंप के प्रस्ताव के बाद उसने इसे दोगुना कर 6 कर दी है। इनमें भविष्य में ईरान पर कोई सैन्य हमला नहीं होगा। युद्ध के कारण ईरान को जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई अमेरिका को करनी होगी। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का पूरा कंट्रोल रहेगा। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर कोई भी प्रतिबंध मंजूर नहीं होगा। पूर्व में ईरान पर लगाए गए सभी प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटाने होंगे। छठी शर्त है कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका को अपने सभी सैन्य बेस बंद करने होंगे। 28 फरवरी को शुरू हुई जंग के बाद ये तो साफ है कि ईरान ऐसे ही अमेरिका और इजरायल पर यकीन करने की गलती तो नहीं करेगा। तभी उसने दोनों से लिखित गारंटी मांगी है कि वे भविष्य में कभी ईरान पर सैन्य कार्रवाई या हमले नहीं करेंगे। ईरान अपने क्षेत्रीय सहयोगियों और मिलिशियाओं खासकर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमलों को बंद करने की मांग भी कर रहा है।

दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच होने वाली बातें बहुत गोपनीय रहती है, लेकिन बहुत से लोग अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगाना शुरु कर देते हैं, ऐसे ही मोदी और ट्रंप की बातचीत के बाद कहा जा रहा है कि आपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर का श्रेय लेने वाले ट्रंप क्या अब पीएम मोदी के सामने ईरान युद्ध में सीज फायर के लिए मदद मांग रहे हैं?

ट्रंप ने मोदी से मदद मांगी?

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं ने मध्य-पूर्व की स्थिति पर चर्चा की और होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने की अहमियत पर जोर दिया। यह जानकारी भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप का कॉल आया था। फोन पर पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। भारत क्षेत्र में तनाव घटाने और जल्द से जल्द शांति बहाली का समर्थन करता है। दुनिया के लिए यह जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे, सुरक्षित रहे और सभी के लिए सुलभ रहे। ट्रंप से बातचीत में दोनों नेता इस बात पर सहमत थे कि शांति और स्थिरता बनाए रखने की कोशिशों के लिए लगातार संपर्क बनाए रखेंगे। मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू होने बाद राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच यह पहली बातचीत बताई जा रही है। हालांकि दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच होने वाली बातें बहुत गोपनीय रहती है, लेकिन बहुत से लोग अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही मोदी और ट्रंप की बातचीत के बाद कहा जा रहा है कि आपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर कराने का श्रेय लेने वाले ट्रंप क्या अब पीएम मोदी के सामने ईरान युद्ध में सीज फायर के लिए मदद मांग रहे हैं? क्योंकि अकेला भारत है जिसके जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना किसी रुकावट के निकल रहे हैं। ट्रंप भी जानते और मानते हैं कि पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है। भारत ही अकेला ऐसा देश है जिसके संबंध दुनिया के सबसे ज्यादा देशों से हैं। युद्ध से प्रभावित सभी देशों से भारत के पीएम और विदेश मंत्री लगातार संपर्क में है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि मोदी अगर प्रयास करेंगे तो मिडिल ईस्ट में शांति बहाल हो सकती है। हालांकि ये कयास ही हो सकते हैं। ये बातचीत ऐसे समय हुई है, जब एक दिन पहले ही ट्रंप ने ईरान के साथ बेहतर और सार्थक बातचीत का दावा करते हुए उसके ऊर्जा ठिकानों पर पांच दिनों तक हमले टालने की घोषणा की थी। हालांकि इसके बावजूद ईरान और इजरायल ने एक-दूसरे पर भीषण हमले जारी रखे। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान से बातचीत के लिए अमेरिका एक अज्ञात ईरानी नेता के साथ संपर्क में है। ट्रंप ने इस नेता को बेहद सम्मानित और समझदार बताया। साथ ही ये भी साफ किया कि ये नेता ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई नहीं हैं।

ईरानी सेना ने ट्रंप का मजाक उड़ाया

ईरानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जोल्फागारी ने 25 मार्च को अमेरिका द्वारा सीज फायर की कोशिशों का मजाक उड़ाया और जोर देकर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपने आप से ही बात कर रहे हैं। ईरानी सेना के खातम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जोल्फागारी ने ईरान के सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक पूर्व-रिकॉर्डेड वीडियो में जमकर राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका का मखौल उड़ाया। उन्होंने कहा जिस रणनीतिक शक्ति की आप

- **ईरानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जोल्फागारी ने 25 मार्च को अमेरिका द्वारा सीज फायर की कोशिशों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपने आप से बात कर रहे हैं ईरान के सरकारी टेलीविजन पर पूर्व-रिकॉर्डेड वीडियो में राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका का मखौल उड़ते हुए कहा महाशक्ति की रणनीति विफलता में बदल चुकी है।**
- **28 फरवरी को शुरू हुई जंग के बाद ये तो साफ है कि ईरान ऐसे ही अमेरिका और इजरायल पर यकीन करने की गलती तो नहीं करेगा, तभी उसने दोनों से लिखित गारंटी मांगी है कि वे भविष्य में कभी ईरान पर सैन्य कार्रवाई या हमले नहीं करेंगे, ईरान अपने क्षेत्रीय सहयोगियों, मिलिशियाओं खासकर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमलों को बंद करने की मांग भी कर रहा है।**

बात करते थे, वह अब रणनीति विफलता में बदल चुकी है। ईरानी सेना ने आगे कहा कि जो खुद को वैश्विक महाशक्ति बताता है, अगर वह इस उलझन से बाहर निकल सकता तो अब तक निकल चुका होता। लेकिन ईरान की सेना ने सुपर पावर के पसीने छुड़ा रखे हैं और अमेरिका प्रोपेगेंडा फैलाकर युद्ध से भाग रहा है। ईरान सेना के प्रवक्ता ने कहा कि अपनी हार को समझौते का रूप न दें। आपके खोखले वादों का दौर अब खत्म हो चुका है। ईरानी सेना ने आगे कहा क्या ट्रंप के आंतरिक विवाद इतने बढ़ गए हैं कि वो अब अपने आप से ही वार्ता कर रहे हैं? जोल्फागारी का यह बयान ट्रंप प्रशासन द्वारा पाकिस्तान के माध्यम से ईरान को भेजे गए 15 सूत्री सीज फायर प्रस्ताव के कुछ ही देर बाद आया है। उन्होंने कहा हमारा पहला और आखिरी शब्द शुरू से एक ही रहा है और आगे भी वैसा ही रहेगा। हमारे जैसे लोग आपके जैसे लोगों से कभी समझौता नहीं करेंगे। न अब, न भविष्य में कभी। युद्ध विराम होगा तो वो ईरान की शर्तो पर होगा।

ट्रंप के बयान पर इजराइल का रिएक्शन

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में तीन सीनियर इजरायली अधिकारियों ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर इस पहल पर संदेह जताया और कहा कि तेहरान के लिए अमेरिकी शर्तें मानना आसान नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन और तेहरान के बीच 28 फरवरी को बातचीत टूट गई थी, जिसके बाद अमेरिका-इजरायल ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था। इस संघर्ष में ईरान में अब तक करीब 1,500 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और 50 से अधिक लीडर व कमांडर मारे जा चुके हैं। यह टकराव ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर बढ़ा था। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि नई बातचीत में अमेरिका, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल क्षमता पर रोक की मांग करेगा, जो दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद का विषय रहे हैं। हालांकि ट्रंप बातचीत को लेकर आशावान हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बेहद अच्छे और सकारात्मक संवाद हुए हैं, जिनका मकसद मिडिल ईस्ट में तनाव का पूर्ण समाधान निकालना है, लेकिन ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। इससे दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास और संभावित समझौते को लेकर अनिश्चितता नजर आती है। ट्रंप की इस घोषणा पर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित ईरानी दूतावास ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसे 'पीछे हटना' यानी पीठ दिखाकर रण छोड़ना बताया है। ईरानी दूतावास ने कहा कि खाड़ी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की तेहरान की चेतावनी के बाद अमेरिका को कदम पीछे खींचना पड़ा। ट्रंप ने पहले धमकी दी थी कि अगर ईरान ने होर्मुज को 48 घंटे के अंदर पूरी तरह नहीं खोला, तो अमेरिका उसके बिजली संयंत्रों को नष्ट कर देगा। इस पर ईरान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अगर उसके बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया गया, तो वह गल्फ तक जाने वाले हर रास्ते को बारूद से भर देगा। शायद इसके बाद ही ट्रंप ने यूटर्न लिया और एक तरफा सीज फायर कर दिया।

पाकिस्तान चला युद्ध रुकवाने

पाकिस्तानी शहबाज और आसिम मुनीर की मजाक बना रहे हैं, पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर और ट्रंप कब पाकिस्तान आ रहे हैं? पाकिस्तान में उनके लिए बनी बिरयानी ठंडी हो रही है, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच सुलह कराने वाले पाकिस्तान ने तो इजराइल को आज तक एक देश के रूप में मान्यता भी नहीं दी है।

सुहैल जैदी
रामपुर

मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को रुकवाने की सुपारी लेने वाला पाकिस्तान बेनकाब हो गया। पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका का नौकर बना हुआ है। यानी वो ट्रंप की चिट्ठी ईरान पहुंचाता है और ईरान की चेतावनी अमेरिका तक पहुंचाने का काम कर इतरा रहा है। पाकिस्तान हुकमरान इसे ही मध्यस्थता और मेजबानी के रूप में प्रचारित कर रहे है। जबकि पाकिस्तानी अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मजाक बना रहे हैं। पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर और ट्रंप कब पाकिस्तान आ रहे हैं? पाकिस्तान में उनके लिए बनी बिरयानी भी ठंडी हो गई है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच सुलह कराने वाले पाकिस्तान ने तो इजराइल को आज तक एक देश के रूप में मान्यता ही नहीं दी है। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर भी इजराइल की यात्रा बैन है। ईरान के निशाने पर पाकिस्तान भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ पिछले साल ही रक्षा समझौता किया था। इसलिए पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि हमारे हुकमरान पाकिस्तानियों को मध्यस्थता और मेजबानी का चूरन बेच रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान न तो ईरान का है और न ही सऊदी अरब का है। मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू होने पर पाकिस्तान को रक्षा समझौते के अनुसार सऊदी अरब की तरफ से ईरान पर हमला करना चाहिए था, लेकिन मुनीर और शहबाज ने सऊदी को अकेला छोड़ दिया। पाकिस्तानी यूट्यूबर रोज नई नई विडियो पोस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज व आर्मी चीफ मुनीर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जिनकी दुनिया में कोई पहचान नहीं इज्जत नहीं, जिन्हें दुनिया भिखारी के रूप में जानती है, जिन्हें पाकिस्तान को बर्बाद करने का जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिन्होंने भारत के आपरेशन सिंदूर के दो ही दिनों में घुटने टेक दिए थे वो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रुकवाने चले हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि शहबाज और मुनीर तो अमेरिका के मोहरा हैं जिन्हें जहां चाहे ट्रंप सेट करता है। यही नहीं पाकिस्तानी मूल के प्रमुख अमेरिकी बिजनेसमैन साजिद तरार तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत नेता बताते है। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत को नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं और वह तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता में लौटे हैं। बाल्टीमोर निवासी बिजनेसमैन साजिद तरार का कहना है कि मोदी न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और दुनिया के लिए अच्छे हैं। तरार ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा, मोदी एक अद्भुत नेता हैं। वह एक जन्मजात नेता हैं। वह एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी राजनीति को जोखिम में डालकर विपरीत परिस्थितियों में पाकिस्तान का दौरा किया था। एक तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सफल राजनेता मान रहे हैं।

सरकार का स्टैंड

भारत की कूटनीति पर उठते सवालों के बीच लोकसभा में बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को कहा था कि भारत का इस मुद्दे पर स्टैंड बिलकुल साफ है। हमने शुरुआत से ही इस लड़ाई पर अपनी चिंता जाहिर की है। मैंने पश्चिम एशिया के सभी नेताओं से बात की और सबसे तनाव कम करने की अपील की है। हमने आम लोगों और ट्रांसपोर्ट तथा एनर्जी फील्ड पर हमलों का विरोध किया है। पीएम ये जानकारी भी दी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन किया और दोनों ने खाड़ी में चल रहे तनाव के बारे में विचार साझा किए। यह भारत की कूटनीति ही है जो होर्मुज से भारत के जहाज सुरक्षित निकल रहे हैं। हालांकि 25 मार्च को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी स्पष्ट किया कि यह होर्मुज जल मार्ग सिर्फ मित्र देशों के जहाजों के लिए खुला है। अराघची ने कहा कि भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान जैसे 'दोस्त देशों' के जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज से गुजर सकते हैं, जबकि दुश्मनों और उनके सहयोगियों के लिए यह मार्ग पूरी तरह बंद है।

- **सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज व आर्मी चीफ मुनीर की मजाक उड़ाई जा रही है, कहा जा रहा है कि जिनकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं, जिन्हें दुनिया भिखारी के रूप में जानती है, जिन्हें पाकिस्तान को बर्बाद करने का जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिन्होंने भारत के आपरेशन सिंदूर के दो दिनों में घुटने टेक दिए थे वो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रुकवाने चले हैं।**
- **पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को कहा था कि भारत का इस मुद्दे पर स्टैंड बिलकुल साफ है, हमने शुरुआत से ही इस लड़ाई पर अपनी चिंता जाहिर की है, मैंने पश्चिम एशिया के सभी नेताओं से बात की और सबसे तनाव कम करने की अपील की है, हमने आम लोगों और ट्रांसपोर्ट तथा एनर्जी फील्ड पर हमलों का विरोध भी किया है।**

विपक्ष के लिए सरकार की कूटनीतिक हार

पाकिस्तानी मध्यस्थता और मेजबानी पाकिस्तानी ही मजाक उड़ा रहे हैं वही भारत में मोदी विरोधी इसे भारत का ही नहीं मोदी की भी बेइज्जती बताने का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान युद्ध से पैदा हुए हालातों पर चर्चा के लिए 25 मार्च को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जिसमें विपक्ष ने सरकार से अपनी स्थिति साफ करने की मांग की। बैठक में विपक्ष ने ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता के ऑफर पर सवाल किया तो विदेश मंत्री डॉ. एस.जयशंकर ने कहा कि हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं हैं। दरअसल, पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने की पेशकश की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि संघर्ष को खत्म करने के लिए सार्थक और निर्णायक वार्ता की मेजबानी करने के लिए उनका देश तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनकी इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया था। इसी बारे में विपक्षी सांसद धर्मेंद्र यादव और मुकुल वासनिक ने सवाल किया था। इस पर जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि पाकिस्तान 1981 से ऐसा करता आ रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने मीडिया से कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के रोल का जिक्र करते हुए जो बातें कहीं उनसे हम संतुष्ट नहीं हैं। पाकिस्तान के संभावित पीस टॉक की मेजबानी का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 24 मार्च को कहा था कि देश की विदेश नीति कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि पीएम खुद कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। मोदी की विदेश नीति व्यक्तिगत है। मोदी सिर्फ वही करते हैं जो अमेरिका और इजराइल उनसे करवाना चाहते हैं। मोदी कभी भारत के हित के फैसले नहीं ले सकते और ये साफ दिख रहा है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से मोदी सरकार की विदेश नीति का बचाव करने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस बार सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान में पीस टॉक होती हैं तो भारत का इससे क्या लेना-देना। लेकिन मैं काफी दिनों से कह रहा हूं कि भारत को अमेरिका और ईरान से अच्छे रिश्तों का फायदा उठाकर इस मामले में लीडिंग स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने ये कर दिखाया। उनको गुड लक, क्योंकि हम सब शांति चाहते हैं, लेकिन भारत को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा जबकि पाकिस्तान सारा क्रेडिट ले जाएगा।

विश्लेषक भी प्रोपेगेंडा चला रहे

सामरिक मामलों के जाने-माने विश्लेषक ब्रह्मा चेलानी ने डोनाल्ड ट्रंप के पीएम मोदी को फोन करने को डैमेज कंट्रोल की कोशिश बताया। उनका कहना था कि सच्चाई यही है कि अहम अंतरराष्ट्रीय मामलों में ट्रंप ने पाकिस्तान को चुना। फिर पीएम नरेंद्र मोदी से बात करके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि मोदी इसे व्यक्तिगत ना लें। ये एक और मौका है जब ट्रंप ने अपने गुड फ्रेंड मोदी को कमतर आंका है। कांग्रेसी नेताओं की

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 24 मार्च को कहा कि देश की विदेश नीति कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि पीएम खुद कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, मोदी की विदेश नीति व्यक्तिगत है, मोदी सिर्फ वही करते हैं जो अमेरिका और इजराइल उनसे करवाना चाहते हैं, मोदी कभी भारत के हित के फैसले नहीं ले सकते।

बात छोड़िए हम सामरिक मामलों के जाने-माने विश्लेषक ब्रह्मा चेलानी की बात करते हैं जो डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे हैं। ये कैसे विश्लेषक है जो कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में ट्रंप ने पाकिस्तान को चुना। पाकिस्तान की भूमिका सिर्फ एक पोस्टमैन की है, जो संदेशों का आदान-प्रदान कर रहा। क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिसे ईरान ने ही उसकी औकात बता दी। पाकिस्तान के मध्यस्थता के दावों के बीच ही ईरान ने पाकिस्तानी शिप को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलने नहीं दिया। यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर (आईआरजीसी) ने पाकिस्तानी जहाज को कराची की ओर जाने की अनुमति नहीं दी। ईरान ने उसे वापस लौटा दिया। जिस पाकिस्तान की औकात अपना एक जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलवाने की नहीं है वो क्या मध्यस्थता करेगा? जबकि भारत सहित पांच देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रखने की ईरान अधिकारिक घोषणा कर चुका है। जो पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर ईरान-अमेरिका में मध्यस्थता करा रहा है उसकी औकात तो ईरान ही बता चुका है। ऐसे सामरिक मामलों के विश्लेषक ब्रह्मा चेलानी का विश्लेषण कैसे सही मान लिया जाए? क्या सामरिक मामलों के विश्लेषक ब्रह्मा चेलानी भी मोदी विरोधी नैरेटिव सेट करने वालों की जमात का हिस्सा हैं। क्योंकि नेताओं का काम तो राजनीति करना होता है। एक दूसरे पर कीचड़ उछालना होता, कमजोर बताना होता है, लेकिन जब कोई ब्रह्मा चेलानी जैसा विश्लेषक मोदी की ताकत को कम आकंता है और पाकिस्तानी पीएम की तारीफ करता है तो महसूस होता है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा ही है।

उमर अब्दुल्ला का पाक पर तंज

पाकिस्तान के ईरान अमेरिका युद्ध रुकवाने में मेजबानी करने वाले प्रोपेगेंडे पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने पाकिस्तान के हुकमरानों पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान अगर कोई रोल अदा करे जिससे कि जंग खत्म हो तो आपको और मुझे इसमें ऐतराज क्यों होना चाहिए? अगर पाकिस्तान के ईरान और इजरायल के साथ अच्छे रिश्ते हैं, अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति वहां जाकर इन लोगों के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, अगर इनकी बातचीत के जरिए जंग रुकेगी तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के इजराइल से संबंध कैसे हैं यही पाकिस्तान के दावे की हवा निकालने के लिए काफी है।

चारधाम में गैर हिंदू की नो इंट्री

क्या कोई गैर हिंदू गंगोत्री व यमनोत्री में स्नान करता है? क्या हिंदुओं के धार्मिक स्थलों में जाने से इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता? क्योंकि दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन एक बालक के गुब्बारे के पानी की छीट मुस्लिम महिला पर पड़ी तो वो नापाक हो गई और बदले में 26 साल के तरुण की हत्या कर दी गई, जिस कौम को होली के पानी से नफरत है तो फिर उस कौम का हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर क्या काम है?

दिनेश मानसेरा
वरिष्ठ पत्रकार

देवभूमि उत्तराखंड में तीर्थ नगरी हरिद्वार के बाद अब 19 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ और बदरीनाथ धाम परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। इसके साथ ही बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अधीन आने वाले 45 अन्य मंदिरों में भी गैर हिंदुओं की इंट्री बैन रहेगी। बदरी-केदार मंदिर समिति ने चारों धामों में गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित किए जाने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट खुलेंगे। चारधाम यात्रा के मद्देनजर श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होली के बाद 6 मार्च से शुरू हो गई है। शासन और प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं पूरी कराई जा रही हैं, ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। चारों धामों में मोबाइल बैन का फैसला उत्तराखंड सरकार पहले ही ले चुकी है। उत्तराखंड की तीर्थ नगरी में इसी साल जनवरी में गंगा सभा ने हरकी पौड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग उठाई थी। इसके लिए गंगा सभा ने हर की पौड़ी क्षेत्र में जगह-जगह गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित के बोर्ड भी लगा दिए थे। हालांकि बाद में यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था। क्योंकि देश विदेश से सालाना करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार हर की पौड़ी पर स्नान और अन्य धार्मिक अनुष्ठान के लिए पहुंचते हैं। गंगा सभा की हर की पौड़ी क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग के बाद चारधाम में भी गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने की मांग उठने लगी थी। उस समय बदरी-केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा था कि वो आगामी बोर्ड की बैठक के दौरान बीकेटीसी के अधीन आने वाले सभी 47 मंदिर परिसरों व गर्भगृह में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने के प्रस्ताव पारित कराएंगे।

कट्टपंथी बौखलाए

बदरीनाथ-केदारनाथ धाम सहित देवभूमि उत्तराखंड के 47 मंदिर परिसरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने की मांग के साथ 10 मार्च को देहरादून में बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में बजट बैठक हुई। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 121.7 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव गैर हिंदुओं के उत्तराखंड के 47 मंदिर परिसरों में प्रवेश वर्जित के प्रस्ताव पर भी मोहर लगा दी गई। इस प्रस्ताव को आम सहमति से पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव पर देशभर की निगाहें टिकी हुई थी। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के परिसरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के पीछे तर्क है कि जो धर्म बुत पूजा का विरोधी है, जो सनातन धर्म का विरोधी है उस गैर हिंदू समुदाय को खुद ही सनातनी धार्मिक स्थलों अथवा धार्मिक नगरी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया गया तो तमाम कट्टरपंथी संगठनों ने इस मुद्दे पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि ऐसे प्रतिबंध समाज में विभाजन की भावना को बढ़ा सकते हैं। यह भारत की साझा संस्कृति और आपसी भाईचारे की भावना के विपरीत है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में कहा कि हरिद्वार में गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित के पोस्टर लगाना संविधान का मखौल उड़ाने जैसा है। यह छुआछूत है और समानता के अधिकार का सीधा-सीधा उल्लंघन है। अगर आप इस तरह की विचारधारा रखते हैं, तो इसका मतलब आप कानून को नहीं मानते हैं। ये वही कट्टपंथी नेता है जो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हिंदुओं के मंदिरों और मंदिर परिसरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित होने से इन नेताओं की दिक्कत क्या है? क्या कोई गैर हिंदू गंगोत्री और यमनोत्री में जाकर स्नान कर सकता है? क्या हिंदुओं के धार्मिक स्थलों में जाने से इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता? क्योंकि दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन एक बालक के गुब्बारे के पानी की कुछ बूंदें मुस्लिम महिला पर पड़ी तो वो नापाक हो गई और बदले में 26 साल के तरुण की हत्या कर दी गई। जिस कौम को होली के पानी से भी नफरत है तो फिर उस कौम का हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर क्या काम है? हालांकि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन के चीफ इमाम डॉ. इमाम उमर अहमद इलियासी ने मंदिरों व मंदिर परिसरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का समर्थन किया है।

हरिद्वारा के बाद चार धाम यात्रा में गैर हिंदुओं की नो इंट्री के बाद अब उत्तराखंड के अन्य पौराणिक व प्राचीन मंदिर में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग उठेगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि राज्य सरकार अभी धार्मिक स्थलों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किए जाने संबंधी मामले में कोई निर्णय नहीं ले पाई है।

उन्होंने कहा था कि यह धर्म का मामला है और धर्म का अपना महत्व है। अगर मंदिर कमेटी यह तय करती है कि गैर-हिंदू चार धाम में नहीं जा सकते, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हर जगह के अपने नियम होते हैं। मुसलमान जब गंगोत्री में स्नान नहीं कर सकता तो फिर गंगोत्री क्यों जाना चाहिए? अगर वे जाते हैं, तो इससे विवाद हो सकता है। दूसरे धर्मों की पवित्र जगहों पर जाने से बचना बेहतर है। मक्का और मदीना में गैर-मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित है, लेकिन कोई हिंदू या हिंदू संगठन इस पर आपत्ति नहीं करता।

पौराणिक मंदिरों में लगेगा बैन?

हरिद्वारा के बाद चार धाम यात्रा में गैर हिंदुओं की नो इंट्री के बाद क्या अब उत्तराखंड के अन्य पौराणिक व प्राचीन मंदिर परिसरों में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग उठ सकती है? यह सवाल इसलिए क्योंकि राज्य सरकार अभी देवभूमि के धार्मिक स्थलों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किए जाने संबंधी मामले में कोई निर्णय नहीं ले पाई है, जबकि इस साल चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने वाली है। इसी बीच बदरी-केदार मंदिर समिति ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बदरीनाथ धाम और केदारनाथ धाम समेत 47 मंदिरों में गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित करने का निर्णय ले लिया है। ऐसे में आगामी चारधाम यात्रा के दौरान बीकेटीसी के अधीन आने वाले बदरीनाथ और केदारनाथ समेत 47 मंदिरों में अब गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बीकेटीसी के इस निर्णय के बाद संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश में मौजूद अन्य पौराणिक एवं धार्मिक मंदिरों में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित की मांग तेज हो सकती है। क्योंकि जो हिंदुत्व एवं सनातन धर्म को मानने वाले हैं और जिनकी बाबा केदारनाथ और बदरी विशाल में आस्था है, वही हिंदू हैं और वही सनातनी हैं। ऐसे में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का देवभूमि में स्वागत है। लेकिन जो सनातन धर्म को नहीं मानते, उनको पूरी तरह से मंदिर क्षेत्र में आने से प्रतिबंधित किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धार्मिक स्थलों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किए जाने की मांग पर कहा कि इस मुद्दे पर धार्मिक स्थलों का संचालन करने वाले लोगों से बातचीत कर ही कोई निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा था कि देवभूमि के जितने भी प्राचीन धार्मिक, पौराणिक स्थल और देवस्थान हैं, उनकी देख रेख करने वालों और उनका संचालन करने वालों, सभी धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी, तीर्थ सभा, गंगा सभा, केदार सभा, बदरी-केदार मंदिर समिति के पदाधिकारी तथा पूज्य संत समाज की जो

गंगा सभा की हर की पौड़ी क्षेत्र में गैर हिंदुओं की नो इंट्री के बाद चारधाम में भी गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने की मांग उठने लगी थी, उस समय बदरी-केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा था कि वो आगामी बोर्ड की बैठक के दौरान बीकेटीसी के अधीन आने वाले सभी 47 मंदिर परिसरों व गर्भगृह में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने के प्रस्ताव पारित कराएंगे, जो अब हो चुका है।

राय और मत होगा उसी के अनुसार सरकार आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये स्थान बहुत ही प्राचीन व पौराणिक महत्व के स्थान हैं।

किन मंदिरों में नो इंट्री होगी

बदरी-केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि उत्तराखंड में अवैध मजारों का निर्माण हुआ है, धर्म विशेष के लोगों ने धार्मिक आस्था के नाम पर लैंड जिहाद किया और यहां का माहौल खराब करने की कोशिश की है. उत्तराखंड में मौजूद धार्मिक स्थलों में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश दुनिया से आ रहे हैं। ऐसे में तीर्थ स्थलों की धार्मिक और पौराणिक आस्था एवं पवित्रता को किस तरह से कायम रखा जाए, इस पर जोर दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालु सिर्फ तीर्थाटन के लिए ही वहां पहुंचे। लिहाजा इस तरह का निर्णय लेना पड़ा है। केदारनाथ समेत 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित के बाद क्या राज्य के अन्य प्राचीन व पौराणिक धार्मिक स्थलों में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित किया जा सकता है? इस पर हेमंत द्विवेदी का कहना था कि सबकी अपने-अपने धर्म के प्रति आस्था है। सबको अपने धर्म को किस तरह से चलाना है, उसकी व्यवस्था संविधान में भी है। ऐसे में जितने भी धर्म हैं, उनकी अपनी परंपराएं हैं और उस तरह से उनकी व्यवस्थाओं को देखा जाता है। ऐसे में जितने भी सनातन धर्म और हिंदुओं के धार्मिक स्थल हैं वो भारत की आत्मा हैं। जहां पर देश दुनिया से लाखों तीर्थ यात्री आस्था और भाव के लिए हर साल पहुंचते हैं? ऐसे में उसकी पवित्रता, पौराणिकता और पहचान को बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है। यहां ज्यादातर मंदिर पहाड़ियों पर स्थित हैं। लिहाजा मंदिर तक पहुंचने के लिए डोली, कंडी और घोड़े खच्चर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका संचालन गैर हिंदुओं द्वारा भी किया जाता है। बदरी-केदार मंदिर समिति ने 47 मंदिर परिसरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर जो प्रतिबंध लगाया है, उसका इन लोगों के रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रवेश पर रोक मंदिर परिसर और मंदिर के गर्भगृह पर लागू होगी। बाकी डोली, कंडी और घोड़े खच्चर के संचालक मंदिर परिसर के बाहर तक जा सकते हैं। उनका कहना है कि जिन 47 मंदिर परिसरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश बैन हुआ है उनमें बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के साथ ही त्रियुगीनारायण मंदिर, नरसिंह मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, ओंकारश्वर मंदिर, कालीमठ मंदिर, ब्रह्मकपाल शिला एवं परिक्रमा-बदरीनाथ, तप्त कुंड, शंकराचार्य समाधि, मद्महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, योगध्यान बदरी, भविष्य बदरी, आदि बदरी, वृद्ध बदरी, माता मूर्ति मंदिर, वासुदेव मंदिर, गौरी कुंड मंदिर, आदिकेदारेश्वेर मंदिर, पांच शिला बदरीनाथ (नारद शिला, नृसिंह शिला, बाराही शिला, गरुड़ शिला और मार्कण्डेय शिला), पांच धाराएं (प्रह्लाद धारा, कूर्मा धारा, भृगु धारा, उर्वशी धारा और इंदिरा धारा), ऊखीमठ में उषा का मंदिर, कालिशिला और वसुधारा शामिल हैं। बीकेटीसी इन मंदिरों की व्यवस्था देखती है। इसमें मंदिरों का प्रबंधन, सुरक्षा और रखरखाव शामिल हैं। लेकिन बीकेटीसी और गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर समितियां पहले ही साफ कर चुकी हैं कि गैर हिंदू का मतलब जो सनातन धर्म को नहीं मानते उनका प्रवेश मंदिर में प्रवेश वर्जित किया गया है। हिंदू सनातन धर्म से निकले सिख, जैन और बौद्धों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा। ऐसे में इन तीनों धर्मों के लोग मंदिरों में बिना किसी रोकटोक के जा सकेंगे। उनका कहना था कि बीकेटीसी 1939 के अधिनियम के तहत काम करती है। बदरी-केदार मंदिर समिति बदरीनाथ और केदारनाथ समेत अन्य मंदिरों के कपाट खोलने और बंद करने की व्यवस्था करती है। इसके साथ ही इन मंदिरों के विकास और तीर्थयात्रियों की सुख सुविधा के लिए बजट पास करना भी समिति का जिम्मा है। ●

भाभा का सपना भारत की शक्ति

भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉ.होमी जहांगीर भाभा ने बहुत पहले यह समझ लिया था कि ऊर्जा ही आधुनिक राष्ट्र निर्माण की असली शक्ति होगी, उन्होंने देखा कि भारत के पास यूरेनियम सीमित है, लेकिन थोरियम के विशाल भंडार मौजूद हैं, इसी आधार पर उन्होंने भारत के लिए तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया।

उत्तरांचल दीप डेस्क

स्वतंत्रता के बाद का भारत ऊर्जा की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा था। उद्योगों को बिजली चाहिए थी, शहरों को रोशनी चाहिए थी और विकास के लिए स्थाई ऊर्जा स्रोत की तलाश जारी थी। उसी दौर में एक वैज्ञानिक ने भविष्य को दशकों आगे देखकर एक ऐसी योजना बनाई, जिसने भारत की ऊर्जा नीति की दिशा तय कर दी। तमिलनाडु के समुद्र तट पर स्थित कलपक्कम परमाणु परिसर में विकसित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) की सफलता उस दूरदर्शी सोच की ऐतिहासिक परिणति है। यह उपलब्धि केवल एक परमाणु रिएक्टर के संचालन की तकनीकी खबर नहीं है, यह भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक क्षमता और दीर्घकालिक राष्ट्रीय दृष्टि का प्रतीक है। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉ.होमी जहांगीर भाभा ने बहुत पहले यह समझ लिया था कि ऊर्जा ही आधुनिक राष्ट्र निर्माण की असली शक्ति होगी। उन्होंने देखा कि भारत के पास यूरेनियम सीमित है, लेकिन थोरियम के विशाल भंडार मौजूद हैं। इसी आधार पर उन्होंने भारत के लिए तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया। एक ऐसी रणनीति, जिसका लक्ष्य तत्काल ऊर्जा उत्पादन ही नहीं, बल्कि सदियों तक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना था। पहले चरण में यूरेनियम आधारित रिएक्टर, दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और तीसरे चरण में थोरियम आधारित ऊर्जा व्यवस्था की परिकल्पना की गई। कलपक्कम का पीएफबीआर इसी दूसरे चरण का वास्तविक और निर्णायक रूप है। 500 मेगावाट क्षमता वाला पीएफबीआर पारंपरिक परमाणु संयंत्रों से अलग है। सामान्य रिएक्टर केवल ईंधन का उपयोग करते हैं, जबकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर उपयोग किए गए ईंधन से नया परमाणु ईंधन भी उत्पन्न करता है। रिएक्टर द्वारा क्रिटिकलिटी प्राप्त करना इस बात का संकेत है कि नियंत्रित परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया सफलता पूर्वक प्रारंभ हो चुकी है। यह वह चरण है जहां वैज्ञानिक प्रयोग वास्तविक ऊर्जा उत्पादन की दिशा में बदल जाता है। इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता है, ईंधन दक्षता। यह रिएक्टर दीर्घकाल में भारत को सीमित संसाधनों के बावजूद ऊर्जा समृद्ध राष्ट्र बना सकता है।

ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आवश्यक

पश्चिम एशिया संघर्ष ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि रणनीतिक अनिवार्यता भी है। ऊर्जा आयात पर निर्भरता किसी भी वैश्विक संकट के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। वर्तमान में भारत की ऊर्जा व्यवस्था में कोयले की हिस्सेदारी अब भी प्रमुख बनी हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा, विशेषकर सौर और पवन तेजी से विस्तार कर रही है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती है निरंतरता। ऐसे परिदृश्य में परमाणु ऊर्जा एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभरती है। पीएफबीआर जैसी उन्नत परियोजनाएं भारत की दीर्घ कालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत आधार प्रदान करती हैं और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की दिशा तय करती हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन आज वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौती बन चुका है। कार्बन उत्सर्जन घटाने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर में स्वच्छ एवं भरोसेमंद ऊर्जा स्रोतों की तलाश तेज हो गई है। ऐसे समय में परमाणु ऊर्जा एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में सामने आती है, क्योंकि यह लगभग शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन करने में सक्षम है।

> **भारत की ऊर्जा व्यवस्था में कोयले की हिस्सेदारी अब भी प्रमुख बनी हुई है, नवीकरणीय ऊर्जा, विशेषकर सौर और पवन तेजी से विस्तार कर रही है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती है निरंतरता, ऐसे परिदृश्य में परमाणु ऊर्जा एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभरती है।**

शांति अधिनियम, 2025

शांति अधिनियम, 2025 के माध्यम से परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों की दिशा में निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। शांति अधिनियम, 2025 के पारित होने के साथ दशकों पुराने विधिक अवरोधों को समाप्त करते हुए इस क्षेत्र को निजी एवं विदेशी निवेश के लिए अधिक खुला और आकर्षक बनाया गया है। इसका उद्देश्य वर्तमान लगभग 8,780 मेगावाट परमाणु क्षमता को वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट तक विस्तारित करना है, जो 'विकसित भारत' के लक्ष्य और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्रतिबद्धता से सीधे जुड़ा हुआ है। केंद्रीय बजट 2025-26 में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान इस परिवर्तन की दिशा को स्पष्ट करता है। कलपक्कम में 500 मेगावाट पीएफबीआर परियोजना तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण के क्रियान्वयन का प्रतीक बन चुकी है, जो भविष्य में भारत के थोरियम संसाधनों के उपयोग का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसके साथ ही एनपीसीआईएल-एनटीपीसी संयुक्त उद्यम, 700 मेगावाट पीएचडब्लूआर रिएक्टरों की फ्लीट-मोड तैनाती, स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा तथा रूस सहित वैश्विक सहयोग के माध्यम से ईंधन सुरक्षा को मजबूत किया गया है।

होमी भाभा की दूरदर्शिता

अपशिष्ट प्रबंधन में उन्नत 'पार्टिशनिंग' तकनीक अपनाकर भारत चक्रीय परमाणु अर्थव्यवस्था की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है, जिससे परमाणु ऊर्जा भविष्य के स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत के रूप में स्थापित हो रही है। ऊर्जा संक्रमण के दौर में परमाणु ऊर्जा फिर से वैश्विक रणनीति का हिस्सा बन रही है। ऐसे समय में भारत की यह उपलब्धि उसे तकनीकी रूप से आत्मविश्वासी और रणनीतिक रूप से सक्षम राष्ट्र के रूप में स्थापित करती है। भविष्य में भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतें खुद पूरी कर सकता है, बल्कि उन्नत परमाणु तकनीकों में वैश्विक साझेदार भी बन सकता है। होमी भाभा ने जिस ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की थी, कलपक्कम की उपलब्धि उसी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। पीएफबीआर केवल एक परमाणु रिएक्टर नहीं, बल्कि यह संदेश है कि दीर्घकालिक वैज्ञानिक सोच और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता मिलकर इतिहास रच सकती है। भारत की परमाणु यात्रा अब प्रयोगशाला से आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण की केंद्रीय धुरी बन चुकी है और आने वाले वर्षों में यही ऊर्जा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की आधारशिला साबित हो सकती है।

ब्रिटेन में हुई भाभा की उच्च शिक्षा

डॉ. होमी जहांगीर भाभा का जन्म मुंबई में 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। उनका परिवार पारसी था। पिता होर्मुसजी भाभा उस समय के मशहूर वकील थे। उनकी मां जाने-माने बिजनेसमैन रतनजी दादाभाई टाटा की बेटी मेहरबाई टाटा थीं। संपन्न परिवार में जन्मे डॉ. होमी भाभा ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई में की, उसके बाद उच्च शिक्षा के के लिए 1930 में ब्रिटेन चले गए। वहां कैंब्रिज विश्वविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। इसके लिए डॉ. होमी भाभा को पिता और चाचा ने प्रोत्साहित किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही उनका रुझान फिजिक्स की ओर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। नतीजा उन्होंने कैंब्रिज विश्वविद्यालय से ही एटॉमिक फिजिक्स में पीएचडी कर ली था। होमी भाभा के पिता और चाचा समेत परिवार के लोग चाहते थे कि ब्रिटेन से पढ़ कर लौटने के बाद वह टाटा स्टील या टाटा मिल्स में मेटलर्जिस्ट बन जाएंगे। 1940 में डॉ. होमी जहांगीर भाभा भारत लौटे। गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। उसी दौरान दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटेन उसकी जद में था। इस पर उन्हें भारत में ही रुकना पड़ा। यहां उन्होंने घर वालों के बताए रास्ते पर चलने के बजाय बेंगलुरु में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में रीडर के पद पर ज्वाइन कर लिया, यह बात 1944 की है। डॉ. भाभा ने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के सामने एक प्रस्ताव रखा कि एक ऐसा संस्थान बनाया जाए, जिसमें फिजिक्स से जुड़ी रिसर्च की जा सके। डॉ. होमी भाभा का यह प्रस्ताव रंग लाया और दिसंबर 1945 में भारतीय परमाणु अनुसंधान संस्थान यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की शुरुआत हो गई। डॉ. भाभा ने बाद में प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को इस बात के लिए राजी कर लिया कि देश में परमाणु कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। उनकी अगुवाई में अप्रैल 1948 में ही एटॉमिक एनर्जी एक्ट संसद से पास हो गया। इसके बाद डॉ. भाभा को न्यूक्लियर प्रोग्राम का निदेशक बनाया गया। साथ ही एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी बनाया गया।

> - **शांति अधिनियम, 2025 के पारित होने के साथ दशकों पुराने विधिक अवरोधों को समाप्त करते हुए इस क्षेत्र को निजी एवं विदेशी निवेश के लिए अधिक खुला और आकर्षक बनाया गया है, इसका उद्देश्य वर्तमान लगभग 8,780 मेगावाट परमाणु क्षमता को वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट तक विस्तारित करना है, जो 'विकसित भारत' के लक्ष्य और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्रतिबद्धता से सीधे जुड़ा हुआ है।**
> - **जेनेवा में 24 जनवरी 1966 को एक प्लेन क्रैश हुआ, इस विमान में क्रू सदस्यों, डॉ. होमी भाभा सहित 117 लोगों की मृत्यु हो गई, हैरानी की बात ये है कि लाख कोशिशों के बावजूद विमान में सवार लोगों का कोई निशान तक नहीं मिला, यहां तक कि विमान का ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिल पाया।**

साजिश का शिकार हुए डॉ. भाभा?

परमाणु ऊर्जा आयोग के निदेशक के रूप में डॉ. भाभा की अगुवाई में 1956 में देश में पहला परमाणु रिएक्टर विकसित किया गया, जिसका नाम था अप्सरा। हालांकि पंडित जवाहर लाल नेहरू के बाद लालबहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो डॉ.होमी भाभा को थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। क्योंकि गांधीवादी प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री परमाणु बम बनाने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि बाद में डॉ. भाभा ने लालबहादुर शास्त्री को एटॉमिक एनर्जी के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए मना लिया था। 1961 में डॉ. होमी भाभा और अमेरिकी सेना के जनरल केनेथ निकोल्स के बीच बैठक हुई। इसमें डॉ. भाभा ने दावा किया कि भारत चाहे तो डेढ़ साल के भीतर परमाणु बम बना सकता है। ऑल इंडिया रेडियो के साथ बातचीत में 1965 में डॉ. भाभा ने एक बार फिर दावा किया कि अगर उन्हें अनुमति दी जाए तो सिर्फ डेढ़ साल यानी 18 महीने में एटम बम बना देंगे। इससे प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के साथ ही पूरी दुनिया चौंक गई थी। डॉ. होमी भाभा अपनी इस घोषणा के तीन महीने बाद जेनेवा जा रहे थे। उनका विमान जेनेवा में उतरता उससे पहले ही 24 जनवरी 1966 को प्लेन क्रैश हो गया और विमान में क्रू सदस्यों, डॉ. होमी भाभा सहित 117 लोगों की मृत्यु हो गई। लाख कोशिशों के बावजूद विमान में सवार लोगों का कोई निशान नहीं मिला। यहां तक कि विमान का ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिल पाया। इससे साबित होता है कि प्लेन क्रैश हुआ नहीं बल्कि साजिश के तहत क्रैश कराया गया।

क्या राहुल कंफ्यूज है ?

राहुल से नाराज हेमंता बिस्व सरमा ने 2015 में कांग्रेस छोड़ी और भाजपा ज्वाइन कर ली, हेमंता को राहुल नहीं समझ पाए पर भाजपा ने हेमंता का जूनून देख लिया, इसके बाद से वो असम के सीएम हैं, उनकी गिनती ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में होती है जिनके चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ने और जीतने पर कोई संदेह तक नहीं करती।

उदयभान सिंह
लेखक

भारत की सबसे पुरानी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी को क्या राजनीतिक समझ नहीं है? क्या वो कांग्रेस में जनाधार वाले नेताओं को पहचान नहीं पाए या जानबूझ कर जनाधार वाले नेताओं को पार्टी छोड़ने के लिए विवश करते हैं? क्योंकि जनाधार वाले नेता राहुल गांधी के लिए भविष्य में चुनौती बन सकते हैं। तो क्या राहुल गांधी ने चुनौतियों से घबराकर कांग्रेस को कमजोर किया है? जबकि असम में हिमंत बिस्वा सरमा जैसे जनाधार वाले लोकप्रिय नेता पहले कांग्रेस में ही थे। हेमंता बिस्वा सरमा 2011 तक कांग्रेस के बहुत प्रभावशाली नेता माने जाते थे, जिन्होंने 2011 के असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के साथ मतभेद और राहुल गांधी व कांग्रेस द्वारा उनके काम की अनदेखी करने तथा गौरव गोगोई को तवज्जों देने से नाराज हेमंता ने 2015 में कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। यानी हेमंता को राहुल गांधी नहीं समझ पाए पर भाजपा ने हेमंता में राजनीतिक जूनून समझ भी लिया। इसके बाद से वो असम के मुख्यमंत्री हैं। वो भाजपा के चर्चित नेताओं में से एक हैं। उनकी गिनती ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में होती है जिनके चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ने और जीतने पर कोई संदेह तक नहीं करती। हेमंता को ही नहीं खोया एमपी सिंधिया को भी खो दिया। कांग्रेस में ही शशि थरूर केरलम के प्रभावशाली कांग्रेस लीडर और सांसद हैं, लेकिन आजकल कांग्रेस ने एक तरह से उनका बॉयकाट कर रखा है। मध्य प्रदेश ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी की टीम के सदस्य रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में अपेक्षित सम्मान न मिलने की वजह से उन्होंने राहुल का साथ छोड़ा और अब वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ऐसे ही यूपी में के प्रभावशाली नेता जतिन प्रसाद भी राहुल गांधी की टीम के सदस्य थे, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया। 2015 से कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला शुरू और अभी ये जारी है, बड़े-बड़े नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। इनमें मिलिंद देवड़ा, आरपीएन सिंह, प्रियंका चतुर्वेदी, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल और गुलाम नबी आजाद जैसे राहुल गांधी के कई करीबी और युवा नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है।

कांग्रेस खोखली हो रही है

महाराष्ट्र कुणाल पाटिल का कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना गया क्योंकि उनके परिवार की तीन पीढ़ियों का कांग्रेस से जुड़ाव रहा है। कुणाल दिवंगत रोहिदास पाटिल के बेटे हैं। रोहिदास पाटिल कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व राज्य मंत्री रहे। उन्होंने कांग्रेस सरकारों में प्रमुख विभाग संभाले थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रोहिदास पाटिल के अस्वस्थ होने पर उनके आवास पर मुलाकात की थी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बात कराई थी। कुणाल पाटिल के दादा चूड़ामन पाटिल 1962 और 1971 के बीच धुले लोकसभा क्षेत्र से तीन बार सांसद चुने गए थे। इससे समझा जा सकता है कि जो पीढ़ियों से कांग्रेसी थी वो कैसे केसरिया रंग में अपना भविष्य देख रहे हैं। इनमें सामान्य बात ये है कि ये अधिकांश कांग्रेसी राहुल गांधी के नेतृत्व में अविश्वास, और अपमानित महसूस कर रहे थे। इसलिए भाजपा ज्वॉइन की। क्या ये राहुल की कमजोरी है कि वो कांग्रेस के वफादार लीडरों को शिनाख्त तक नहीं कर पाए और उनसे किनारा कर लिया। क्या इसलिए भाजपा राहुल गांधी को कंफ्यूज नेता की श्रेणी में रखती है। राहुल गांधी और कांग्रेस को कंफ्यूज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण ऊर्जा संकट को लेकर राहुल गांधी सरकार को घेरते रहे। सड़क से लेकर संसद तक रसोई गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, इनमें से किसी एक मुख्यमंत्री ने भी अपने राज्य में रसोई गैस की किल्लत होने का दावा नहीं किया। यही पार्टी में कंफ्यूजन है। दिल्ली के नेता गैस की किल्लत बता रहे हैं और कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम खामौश हैं। यदि किल्लत है तो कांग्रेस के सीएम को खुले मंच से गैस की किल्लत बतानी चाहिए थी।

राहुल पर पब्लिक को भरोसा नहीं

राहुल गांधी जब से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, वो जो कुछ भी बोल रहे हैं जनता उस पर गौर नहीं कर रही है। राजनीतिक गलियारों में राहुल की हर बात पर कांग्रेस को लगता है कि उन्होंने मैदान मार लिया है, लेकिन भाजपा जब पलटवार करती है और यह साबित करने में लग जाती है कि राहुल गांधी अभी अपरिपक्व राजनेता जैसी बातें करते हैं। इससे राहुल गांधी की सारी पोलपट्टी खुल जाती है। इसलिए देश की राजनीति में राहुल गांधी को कम से कम गंभीरता से तो नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि देश के प्रमुख मुद्दों पर राहुल गांधी ऐसे-ऐसे विरोधाभाषी बयान दे देते हैं कि आम आदमी भी कंफ्यूज हो जाता है कि कांग्रेस किस ओर है। हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को फिर से लागू करने का वादा किया था, लेकिन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ओपीएस की चर्चा तक नहीं की। कांग्रेस ने जिस हिमाचल में ओपीएस का वादा किया था वहां चुनाव जीतने के बाद भी ओपीएस लागू नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 'कंफ्यूज्ड नेता' बताते हुए कहा था कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे क्या करना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं और कहां खड़े हैं? यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं जो यूपी में विधानसभा चुनाव करीब आने पर बसपा संस्थापक व दलित नेता कांशीराम की जयंती पर नया दांव खेलते हैं और कांशीराम के बहाने दलितों को लुभाने की कोशिश करते हैं। लखनऊ में कांशीराम की जयंती पर कांशीराम को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित कराते हैं, लेकिन 2004 से 2014 तक इन्होंने कांशीराम को भारत रत्न नहीं दिया। यूपीए सरकार को किसने भारत रत्न देने से रोका था जबकि गांधी परिवार में जो भी पीएम रहा उसे भारत रत्न मिला। एक तरफ राहुल गांधी दलितों को अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ कह देते हैं कि अगर कांग्रेस ने दलितों को लेकर अपना काम ठीक से किया होता, तो कांशीराम को इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 2006 में कांशीराम का निधन हुआ। उनकी मृत्यु के बाद यह पहला मौका है, जब राहुल गांधी कांशीराम जयंती के किसी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके पीछे की वजह साफ समझी गई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों के एक बड़े वर्ग ने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों, कांग्रेस और सपा का साथ दिया था, जिसके चलते उन्हें जबरदस्त सफलता मिली और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 43 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। एक बार फिर दोनों सहयोगी दलों की कोशिश इसी दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने की है। लेकिन काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती लोकसभा चुनाव में आरक्षण को खतरे में बताकर दलितों का साथ ले लिया था, लेकिन कांग्रेस की इस चालाकी को अब दलित भी समझ चुका है।

कांग्रेस में ही शशि थरूर केरलम के प्रभावशाली लीडर हैं, लेकिन आजकल कांग्रेस ने एक तरह से उनका बॉयकाट कर रखा है, लिहाजा वो कांग्रेस की कमजोर नसों को दबाकर उसकी मुश्किल बढ़ाते रहते हैं, कांग्रेस उन्हें भाजपा के करीब मान रही है।

टाइम पास नेता की इमेज

राहुल गांधी की इमेज एक पार्ट टाइम राजनेता की बनी हुई है। क्योंकि वो चुनाव करीब आने पर ही देश और राज्यों में सक्रिय होते हैं। देश के वरिष्ट राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि किसी भी राजनेता का मूल्यांकन आमतौर पर विचारधारा, रणनीति और चुनावी सफलता के आधार पर किया जाता है। लेकिन कभी-कभी इससे भी गहरा सवाल मनोवैज्ञानिक होता है। एक नेता सहज रूप से राजनीति को कैसे समझता है? राहुल गांधी के मामले में इसका उत्तर उनके सार्वजनिक जीवन में व्याप्त एक विरोधाभास में निहित हो सकता है। राहुल गांधी की राजनीति अक्सर व्यक्तिगत लहजे में बेहद निजी लगती है, लेकिन मूल रूप से उसका उद्देश्य राजनीतिक ही होता है। नरेंद्र मोदी के प्रति उनका विरोध अक्सर भावनात्मक रूप से आवेशित और कभी-कभी तो आरोपात्मक भी लगता है। या फिर क्या उनकी आलोचना मोदी पर कम और उस राजनीतिक व्यवस्था पर अधिक केंद्रित होती है जिसका प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी करते हैं? राहुल गांधी के विरोधाभास को समझने के लिए उनकी राजनीतिक टिप्पणियों का विश्लेषण करना जरूरी है। जिससे पता चलता है कि राहुल गांधी की राजनीति की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करना है। भारत जोड़ो यात्रा को महज एक अभियान के रूप में नहीं, बल्कि घृणा की राजनीति का मुकाबला प्रेम की राजनीति से करने के प्रयास के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस तरह की भाषा निश्चित रूप से सियासत को निजी बना देती है। जब कोई नेता राजनीतिक संघर्ष को प्रेम और घृणा के बीच संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करता है, तो विरोधी नेता की आलोचना आसानी से पर्सनल लगने लगती है। विदेशी मंचों पर सरकार, भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संविधान या किसी समुदाय के लिए की जाने वाली टिप्पणी भारतीयों को बुरी लगती हैं। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि घरेलू विवाद घरेलू ही रहने चाहिए। उन्हें विदेशों में उठाने से राष्ट्रीय मामलों पर बाहरी निर्णय को न्यौता देना होता है। हालांकि राहुल गांधी विदेशी ताकतों से अपील कर चुके हैं कि भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्हें मदद करनी चाहिए। इसलिए विदेशों में होने वाली आलोचना को सहज ही देश की आलोचना राष्ट्र के प्रति विश्वासघात के रूप के रूप में देखी जाती है।

2015 से कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला शुरू और अभी ये जारी है, बड़े-बड़े नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, इनमें मिलिंद देवड़ा, आरपीएन सिंह, प्रियंका चतुर्वेदी, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद और गुलाम नबी आजाद जैसे राहुल गांधी के कई करीबी और युवा नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है।

आपका अखबार के संपादक प्रदीप सिंह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर विश्लेषण किया था। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि राहुल का मकसद क्या था। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि आप किसी नेता के परिवार में जन्म ले लेने से नेता नहीं बन जाते और यही बात राहुल गांधी पर बिल्कुल खरी उतरती है। राहुल गांधी एक राजनीतिक परिवार में जन्म लेने के कारण ये बात मानकर चल रहे हैं कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी है। यही बात उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि इसकी वजह से वो लीडरशिप क्वालिटी को अपनाना नहीं चाहते, वो उसकी जरूरत नहीं समझते। वरिष्ठ पत्रकार का कहना था कि राहुल गांधी के मन में गलत अवधारणा है और यही उनकी समस्या की जड़ है। जब वो कहते हैं महंगाई पर चर्चा नहीं होती तो इससे साफ है कि उनको न तो इस बात की जानकारी है और ही समझ है। राहुल गांधी की संसद में हाजिरी सबसे कम है। अब आप संसद में जाएंगे नहीं और आप चाहेंगे कि आपकी बात संसद में गूंजे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जब राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने वेदों, उपनिषदों और गीता को पढ़ा है और वो हिंदुत्व के बारे में जानते हैं तो इससे पता लगता है कि वो हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। राहुल ने राफेल और पेगासस के मामले में बहुत कुछ बोला, लेकिन लोगों ने उनकी एक बात नहीं मानी। राहुल गांधी को लगता है सुप्रीम कोर्ट भी डरा हुआ है, सिर्फ अकेले वो हैं जो डरे हुए नहीं हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में यात्रा के प्रवेश करते ही कहा कि उन्होंने ये यात्रा इसलिए शुरू की, क्योंकि मीडिया नरेंद्र मोदी को दिखाता है। यानी साफ है कि राहुल गांधी का टारगेट भारत को जोड़ना नहीं था बल्कि खुद को कांग्रेस से जोड़ना था। प्रदीप सिंह का मानना है कि मीडिया अटेंशन मिलने और वोट मिलने में जमीन आसमान का अंतर है। चुनाव आयोग ने अप्रैल में पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुंडुचेरी विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। सिर्फ पश्चिमी बंगाल में दो फेज में 23 और 29 अप्रैल को मतजान होगा। बाकी चारों राज्यों में एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा जबकि 4 मई को मतगणना होगी। अब देखते हैं राहुल गांधी वोट पाने के लिए कितने गंभीर नजर आते हैं।

युद्ध

सरेंडर करेगा अमेरिका ?

अकेले ईरान ने सुपर पावर अमेरिका सहित 11 देशों को नाको चने चबा रखे हैं, ईरान दोहरा रहा है कि वह सरेंडर नहीं करेगा बल्कि बदला लेगा,जबकि डोनाल्ड ट्रंप नाटो देशों से मदद मांग चुके हैं, युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, क्योंकि ईरान ने दुनिया को दादागिरी दिखाने वाले अमेरिका को घुटनों पर तो ला ही दिया है।

कृष्ण कुमार चौहान

अमेरिका-इजराइल व ईरान युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और भी विध्वसंक होता जा रहा है। न तो ईरान झुकने को तैयार है और न अमेरिका-इजरायल उसे छोड़ने को राजी है। अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करे, जबकि ईरान, अमेरिका को सरेंडर करने के लिए कह रहा है। ऐसे में सवाल ये कि सरेंडर कौन करेगा? क्या मिडल ईस्ट में युद्ध लंबा खिंच सकता है? 28 फरवरी को अयातुल्ला अली खामेनेई के साथ इलीट सेना रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर (आईआरजीसी) के प्रमुख जनरल मोहम्मद पाकपोर और कुछ सीनियर कमांडरों व ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी और रक्षा मंत्री मेजर जनरल अजीज नासिरजादेह, स्टेट आफ होर्मुज बंद कराने वाले नौसेना के कमांडर अलीरेजा तंगसिरी मारे गए। इजराइल ने ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी सहित तीन टॉप कमांडरों को भी मार गिराया है। इसके बाद से ईरान और भी घातक हथियारों से आक्रमण कर रहा है। अकेले ईरान ने सुपर पावर अमेरिका व इजराइल सहित 11 देशों को नाको चने चबा रखे हैं। ईरान बार-बार दोहरा रहा है कि वह सरेंडर नहीं करेगा बल्कि शहादत देने वाले ईरानियों का बदला लेगा। वह 28 फरवरी को स्कूल पर हमले में मारी गई 175 मासूम छात्राओं के खून का बदला लेकर रहेगा। इसलिए ईरान युद्ध नीति बनाकर लड़ रहा है। उसने पहले हवाई हमलों के मिडिल ईस्ट को दहलाया, फिर स्टेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा कर दिया। अब ईरान अपनी रणनीति के तहत अमेरिका को जमीनी जंग के लिए उकसा रहा है। अमेरिका ईरान के जाल में फंसता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ चालाकी कर रहे हैं? ट्रंप ने पहले 48 घंटे की चेतावनी दी, फिर 5 दिन के सीज फायर की एक तरफा घोषणा की। 5 दिन पूरे भी नहीं हुए थे कि ट्रंप ने फिर सीज फायर के 10 दिन और बढ़ा दिए। यानी ट्रंप ईरान को वार्ता के तारीख पर तारीख दे रहे हैं और जमीनी जंग की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान में अपनी थल सेना पहुंचानी भी शुरू कर दी है। लेकिन ईरानी सेना को सरेंडर कराना अमेरिका के लिए आसान नहीं है क्योंकि ईरान की सेना गुरिल्ला युद्ध में माहिर है। फिर ईरान ने बहुत सी सुरंग बना रखी हैं जहां से उसके सैनिक निकलेंगे और अमेरिकी सेना पर हमला कर गायब हो जाएंगे। कुल मिलाकर अमेरिका जमीनी जंग भी लड़ कर देख ले।

ईरान की सैन्य संरचना

ईरान ने ऐसी सैन्य संरचना विकसित की है जहां स्थानीय कमांडर शीर्ष नेतृत्व के बिना भी दुश्मन से लड़ने और हमले करने के लिए सक्षम हैं। जब युद्ध में टॉप कमांडर नहीं रहते तो युद्ध की कमान स्वतः ही स्थानीय कंमाडरों के हाथ में आ जाती है। इसके बाद ईरान की फोर्स पर सिर्फ उसके कमांडर का कंट्रोल रहता है। इस फोर्स के सैनिकों की विचारधारा देश के लिए मर मिटने वाली होती है। कमांडरों की हत्या के बाद भी सेना एकजुट रहती है और अमेरिकी-इजरायली दबाव के बावजूद अपने मिशन पर केंद्रित रहती है। जो आधुनिक व घातक हथियारों से ज्यादा घातक बन जाती है। ऐसे में सवाल पैदा हो रहा है कि ईरान के 50 से ज्यादा टॉप लीडर और टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं, फिर युद्ध की कमान किसके हाथ में है? क्योंकि जैसे-जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है ईरान उतना ही ज्यादा खूंखार होता जा रहा है। इसलिए कभी लगता है कि ट्रंप युद्ध से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगले ही घंटे ट्रंप का सुर बदल जाता है और ईरान को धमकी देने पर उतर आते हैं। जबकि ट्रंप अच्छी तहर जानते हैं कि इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल अकेले हैं। न यूरोपिय देश साथ दे रहे हैं और न ही नाटो देश कोई मदद कर रहे हैं। कभी लगता है कि ईरान ने दुनिया को दादागिरी दिखाने वाले अमेरिका को भले ही सरेंडर न कराया हो, लेकिन घुटनों पर तो ला ही दिया है। फिर भी बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप दावा करते रहते हैं कि हमने ईरान की टॉप लीडरशिप और टॉप कमांडर मारे दिए, गोला बारुद, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार, फाइटर जेट, एयर बेस और नौसेना, वायु सैना खत्म कर दी है। सेना के ठिकाने खत्म कर दिए हैं। 17 बार वो अमेरिका की जीत का दावा भी कर चुके हैं। लिहाजा ट्रंप के दावों में कितना सच है ये शायद खुद ट्रंप भी नहीं जानते। वो तो रोजाना सोशल मीडिया और मीडिया के सामने आकर ईरान युद्ध का अपडेट देते हैं।

अमेरिका के राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी केंद्र (काउंटर टेररिज़्म सेंटर) के निदेशक और ट्रंप के वरिष्ठ सहयोगी जोसेफ क्ले केंट ने ईरान युद्ध के मुद्दे पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से अपना रुख बदलने का आग्रह भी किया है, ट्रंप की पार्टी भी युद्ध के मुद्दे पर दो फाड़ हो गई है।

जब भी ट्रंप जीत का दावा करते हैं ईरान दोगुना ताकत से हमले कर ट्रंप के दावों की हवा निकाल देता है। लिहाजा ट्रंप इतना बोखला गए हैं कि वो यूरोपियन देशों को कायर और अमेरिका के बिना कागजी घोड़ा बता रहे है।

रूस व चीन कर रहे हैं मदद?

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रो, यूएन महासचिव एंटोनियो गुट्रेस, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने चिंता व्यक्त करते हुए मिडिल ईस्ट में शांति की अपील की है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब सहित कई वैश्विक नेताओं ने भारत से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता करने की अपील की है। लेकिन चौकाने वाली बात ये है कि ईरान युद्ध को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का युद्ध को लेकर कोई बड़ा बयान नहीं आया है। चीन ने ईरान पर हमलों की सिर्फ निंदा की है और अस्वीकार्य बताया है। चीनी विदेश मंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि यह युद्ध नहीं होना चाहिए था। चीन ने मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए संघर्ष विराम और बातचीत पर जोर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमलों की निंदा की है और ईरान के प्रति समर्थन भी जताया है। पुतिन ने सीधे तौर पर सैन्य हस्तक्षेप करने से परहेज किया है। लेकिन रूस ने ईरान को खुफिया जानकारी देने की बात कही है, जो अमेरिका-इजरायल के हवाई अभियानों के खिलाफ है। इन दोनों देशों की अमेरिका के साथ पुरानी अदावत हैं। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि जिस तरह रूस-यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने यूक्रेन का साथ दिया है ठीक वैसे ही रूस ईरान की मदद कर रहा। चीन तो मिसाइल और गोला बारूद देने के साथ सेटेलाइट की जानकारी भी ईरान को मुहैया करा रहा है। रूस भी इसी तरह की मदद कर रहा है इसलिए ईरान सुपर पावर अमेरिका के सैन्य बेस को तबाह कर रहा है। अब तक मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 13 सैन्य बेस खंडहर हो चुके हैं। उसके सैनिक होटलों में छिप गए हैं। ईरान जिस तरह से नई नई मिसाइलों से हमले कर रहा है, जिस तरह से अरब देशों में अमेरिकी बेस पर हमले कर रहा है वो बिना किसी मदद के ईरान के लिए असंभव है। वैसे खबर ये भी है कि ईरान के घायल सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को इलाज के लिए रूस शिफ्ट किया गया है। जहां मास्को में कड़ी सुरक्षा में उनका उपचार किया जा रहा है।

ट्रंप फ्रस्ट्रेट हुए

दुनिया का कोई भी देश हो वो दादागीरी, हनक या सनक से नहीं चलता बल्की हर देश

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट ने व्हाइट हाउस और ट्रंप की रातों की नींद हराम कर दी है, ईरान सरकार का तख्ता पलट करने का ख्वाब देखने वाले ट्रंप अब युद्ध से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन खाड़ी देश के साथ इजराइल अब ईरान को निपटाने पर अड़े हैं, इसलिए ट्रंप चाहकर भी युद्ध से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और ईरान का तारीख पर तारीख दे रहे हैं।

कूटनीति, विदेश नीति और रणनीति से चलते है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं कि वो जो मन में आता है वो कर रहे हैं। न तो वो अपनी संसद को विश्वास में लेते हैं और न ही अपनी पार्टी को, जनता की बात तो बहुत दूर की है। शायद यही वजह है कि ट्रंप के सहयोगी भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा बंद किए गए होर्मुज स्टेट खुलवाने के लिए नाटो देशों से मदद मांगी और युद्धपोत भेजने की अपील की, लेकिन उनकी अपील को स्पेन, इटली, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन सहित कई नाटो देशों ने होर्मुज स्टेट में अपने युद्धपोत भेजने से साफ मना कर दिया है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि-हमने ईरान की सेना को पूरी तरह तबाह कर दिया है। उनकी नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है, उनके विमान-रोधी और रडार सिस्टम खत्म हो चुके हैं। सबसे अहम बात यह है कि उनके नेता खत्म हो चुके हैं। अब ईरान हमारे मिडिल ईस्ट सहयोगियों को और पूरी दुनिया को फिर कभी धमका नहीं पाएगा। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मिडिया पर लिखा कि अमेरिका को अब किसी की मदद की जरूरत नहीं है। बड़बोले ट्रंप दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में उनके दावों के गुब्बारे फूट जाते हैं। क्योंकि ईराम में सब कुछ खत्म कर दिया तो ईरान युद्ध कैसे कर रहा है? ट्रंप होर्मुज से अपना एक जहाज तक नहीं निकलवा पा रहे और बात ईरान पर जीत की करते हैं। ट्रंप क्योंकि भरोसेमंद और विश्वास करने योग्य नहीं है इसलिए दुनिया का कोई भी देश युद्ध में मध्यस्थता करने से बच रहा है। ईरान और इजराइल को तो युद्ध विराम के लिए तैयार कर लिया जाएगा, लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

ट्रंप की साख गिरी

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जहां यूरोपीय देशों की नजरों में गिरे हैं वहीं मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के साथ चल रहे युद्ध के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में भी लोकप्रियता लगातार घट रही है। 50 प्रतिशत से अधिक लोग उनकी युद्ध प्रबंधन शैली से असंतुष्ट हैं और स्वतंत्र मतदाता भी उनसे दूर हो रहे हैं। स्वतंत्र मतदाता आशंकित है कि युद्ध के कारण स्थिति और खराब होगी। नाटो सहयोगियों का समर्थन कम होने और जनता में नाराजगी के बीच ट्रंप को घरेलू मोर्चे पर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नाटो के साथ छोड़ने से पश्चिम एशिया संघर्ष में अमेरिका न सिर्फ अकेला पड़ा है बल्कि फंसता हुआ भी नजर आ रहा है। इकोनॉमिक्स यूगो के पोल के अनुसार ट्रंप की रेटिंग गिरकर 37 प्रतिशत पर आ गई है, जबकि 56 प्रतिशत अमेरिकी उनके कामकाज से असंतुष्ट हैं। 64 फीसदी अमेरिकियों का मानना है कि ट्रंप ने युद्ध के लक्ष्यों को स्पष्ट नहीं किया है और आधी आबादी को डर है कि यह युद्ध उनकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिका के राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी केंद्र (काउंटर टेररिज़्म सेंटर) के निदेशक और ट्रंप के वरिष्ठ सहयोगी जोसेफ क्ले केंट ने ईरान युद्ध के मुद्दे पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से अपना रुख बदलने का आग्रह भी किया है। काउंटर टेररिज्म सेंटर के निदेशक जोसेफ क्ले केंट ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए पत्र में कहा है कि ईरान अमेरिका के लिए कोई तत्काल खतरा नहीं था। ट्रंप प्रशासन ने इजराइल और उसकी शक्तिशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव के कारण यह युद्ध शुरू किया। 45 वर्षीय जोसेफ क्ले केंट अमेरिकी विशेष बलों और सीआईए के अनुभवी अधिकारी हैं। उनकी पत्नी शैनन केंट अमेरिकी नौसेना की क्रिप्टोलॉजिक तकनीशियन थीं। 2019 में शैनन केंट की सीरिया में एक आत्मघाती बम विस्फोट में मौत हो गई थी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोसेफ क्ले केंट के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनका पद छोड़ना अच्छा है। नाटो और यूरोपीय देशों के दूरी बनाने और फिर जोसेफ क्ले केंट के त्यागपत्र देने पर ट्रंप ने करीब करीब एक जैसी प्रतिक्रिया दी। ●

बंगाल के अस्तित्व का चुनाव

ममता बनर्जी दो सीटों पर चुनाव लड़ने से क्यों बच रहीं है, इसका सीधा मतलब है कि ममता बनर्जी का दो सीटों से चुनाव न लड़ना उनके नकारात्मक डर का हिस्सा हैं, क्योंकि पंजाब, उत्तराखंड, ओडिशा, हरियाणा और तेलंगाना के उदहारण उनके सामने हैं, यहां जो सीएम दो सीटों से चुनाव लड़ा वो तो हारा ही साथ में पार्टी भी हार गई।

उत्तरांचल दीप डेस्क

पश्चिम बंगाल सहित असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल विधानसभा की हो रही है। इसके बाद चर्चाओं में असम के हैं। भाजपा असम में वापसी की उम्मीद कर रही है तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ने की कोशिश में है। इसलिए भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को अपने जाल में उलझा लिया है। सवाल है कैसे? भाजपा का प्रयास था कि ममता बनर्जी को पूरे राज्य में अंधाधुंध प्रचार से कैसे रोका जाए? कैसे उन्हें भबानीपुर विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा समय देने के लिए मोर्चाबंदी की जाए। भाजपा की यह योजना सफल होती दिख रही है। भाजपा ने इस रणनीति के तहत टीएमसी से पहले अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करके मास्टर स्ट्रोक खेला। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को नंदीगांव के साथ ममता बनर्जी की सीट भबानीपुर से भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। भाजपा की इस घोषणा के दो तात्कालिक राजनीतिक परिणाम देखने को मिले। पहली ममता बनर्जी की भबानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की मजबूरी हो गई। अगर ममता बनर्जी इस सीट को छोड़कर किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ती हैं तो जनता में यह संदेश जाता कि वह सुवेंदु अधिकारी के डर से सीट छोड़कर दूसरी सीट पर चली गई हैं। इससे पार्टी कार्यकर्त्ताओं को मानसिक रूप से काफी क्षति पहुंचती। दूसरा ये कि ममता बनर्जी सिर्फ एक सीट से ही लड़ने के लिए मजबूर हैं। ममता बनर्जी इस बार दो सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थीं। इसका कारण 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की भबानीपुर विधानसभा सीट पर टीएमसी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भबानीपुर सीट पर टीएमसी, भाजपा से केवल 8269 वोटों से आगे थी, वो भी तब जब माकपा को इस सीट पर 14006 वोट मिला थे। भाजपा भबानीपुर विधानसभा सीट पर 2014 के लोकसभा चुनाव से ही काफी मजबूत हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कोलकाता दक्षिण लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली भबानीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा को टीएमसी से अधिक वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण कोलकाता लोकसभा सीट के चुनाव में इस भबानीपुर विधानसभा सीट पर टीएमसी, भाजपा से सिर्फ 3168 वोटों से आगे रही थी।

नकारात्मकता का शिकार ममता

ममता बनर्जी 2021 में नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव हार गई थीं और फिर भबानीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। ममता बनर्जी की राजनीति को इस हार से जोर का झटका लगा था। 2026 में ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर हार स्वीकार नहीं करना चाहती हैं। फिर सवाल ये कि दो सीटों पर चुनाव लड़ने से ममता बनर्जी क्यों बच रहीं है। इसका सीधा मतलब है कि ममता बनर्जी का दो सीटों से चुनाव न लड़ना भी उनकी नकारात्मक घबराहट का हिस्सा हैं। ममता बनर्जी के सामने अनेकों मुख्यमंत्रियों के उदाहरण हैं, जिन्होंने दो सीटों से चुनाव लड़ा मगर वो मुख्यमंत्री अपनी सीटों

भाजपा ने टीएमसी से पहले अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर मास्टर स्ट्रोक खेला, सुवेंदु अधिकारी को नंदीगांव के साथ ममता बनर्जी की सीट भबानीपुर से प्रत्याशी घोषित किया तो ममता बनर्जी भबानीपुर सीट से चुनाव लड़ने को विवश हो गई, यदि ममता किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ती हैं तो जनता मे संदेश जाता कि वो सुवेंदु के डर से दूसरी सीट पर चली गई हैं।

- **असम विधानसभा चुनाव में भाजपा की रणनीति स्पष्ट है, वो हिंदुत्व, डेमाग्राफी चेंज, सांस्कृतिक पहचान और घुसपैठ को मुद्दा बनाएगी, लिहाजा कांग्रेस इसका जवाब कैसे देगी यह कांग्रेस ने सोचा ही नहीं है, कांग्रेस का सीधा फंडा है मुस्लिम बहुल सीटों पर उसे फायदा उसे मिलेगा, बदले में भले ही भाजपा को हिंदु बहुल सीटों का फायदा क्यों हो।**
- **ओवैसी बिहार के सीमांचल में 2020 और 2025 में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करने के बाद पश्चिम बंगाल में खाता खोलना चाहते हैं, बंगाल का सीमांचल का इलाका बांग्लादेश सीमा से सटा है लिहाजा इस इलाके में घुसपैठियों की संख्या भी अधिक है, अगर सीमांचल इस क्षेत्र का वोट बिखरा तो ममता की मुश्किल बढ़ जाएगी।**

से भी हारे और उनकी पार्टी भी चुनाव हार गई। 2024 में पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक दो सीटों से चुनाव लड़े और उनकी पार्टी विधानसभा का चुनाव हार गई साथ ही वो भी एक सीट से चुनाव हार गए। 2023 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव दो सीटों से चुनाव लड़े और एक सीट से चुनाव हारने के साथ उनकी पार्टी भी सत्ता से बेदखल हो गई। 2022 में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दो सीटों से चुनाव लड़े और दोनों सीटों से चुनाव हार गए साथ में उनकी कांग्रेस भी बुरी तरह चुनाव हार गई। एक सीट पर चन्नी मुश्किल से जमानत बचा सके। 2017 में उत्तराखंड में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत दो सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों सीटों से चुनाव हार गए थे। साथ ही कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। 2005 में हरियाणा में तात्कालिन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला दो सीटों नरवाना और रोरी से चुनाव लड़े। चौटाला नरवाना से रणदीप सिंह सुरजेवाला से चुनाव हार गए और चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल भी चुनाव हार गई थी। लिहाजा ममता बनर्जी ने नकारात्मक उदाहरणों को देखते हुए एक सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वो अपनी परंपरागत सीट भबानीपुर से ही चुनाव लड़ रही हैं। मगर इस सीट पर ममता की राह काफी मुश्किलों से भरी है। ममता बनर्जी को अब पूरे राज्य में चुनाव प्रचार करने का कम समय मिलेगा, क्योंकि उन्हें अपने वक्त में से बड़ा हिस्सा अपनी सीट पर चुनाव प्रचार के लिए देना पड़ेगा। भबानीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव दूसरे चरण में हैं, लिहाजा ममता पूरे चुनाव प्रचार के क्रम में अपनी सीट पर ही सीमित रहेंगी। ऐसे में भाजपा अपने मंसूबे में सफल हो सकती है।

बंगाली हिंदुओं की अहम भूमिका

पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासनकाल में तेजी से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जिससे कई जिलों खासकर सीमावर्ती जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक होने की स्थिति में हैं। इससे आने वाले चुनावों में गैर मुस्लिमों या यूं कहें कि हिंदू उम्मीदवारों के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। वहीं भाजपा ने अपने चुनाव अभियान की रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। भाजपा बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, बंगाल-केंद्रित मुद्दों को आगे बढ़ाने और एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची को शुद्ध करने पर जोर देकर जनता को इन मुद्दों पर अपनी ओर कर रही है। इसका असर जमीन पर दिख रहा है। डेमोग्राफी चेंज और घुसपैठ का सियासी मुकाबला तय करेगा कि चुनावी किस दिशा की ओर है। क्योंकि बिना जनगणना के ही ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि राज्य में मुस्लिम आबादी लगभग 33 प्रतिशत है, जबकि यह इससे अधिक भी हो सकती हैं। लिहाजा भविष्य में यदि घुसपैठ इसी तरह जारी रही तो मुस्लिम जनसंख्या और तेजी से बढ़ेगी। लिहाजा भविष्य के चुनावों में गैर मुस्लिमों का चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। इस बार बंगाल की चुनावी दिशा तय करने में बंगाली हिंदू अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि इस बार राज्य में भाजपा की सरकार बने और राज्य से घुसपैठियों को बाहर निकाले। सीमांचल मॉडल और बदली सियासी रणनीति बंगाल में नई हलचल दिखा रही है। क्योंकि भाजपा को छोड़कर बाकी अधिकांश दलों ने मुस्लिम उम्मीदवारों प्राथमिकता दी है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में ममता के वफादार रहे हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी से गठबंधन कर अपनी राजनीति को नई धार देने में लगे हैं। ओवैसी बिहार के सीमांचल में 2020 और 2025 में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करने के बाद पश्चिम बंगाल में खाता खोलना चाहते हैं। बंगाल का सीमांचल का इलाका बांग्लादेश सीमा से सटा है लिहाजा इस इलाके में घुसपैठियों की संख्या भी अधिक है। अगर सीमांचल क्षेत्र का वोट बिखरा तो ममता की मुश्किल बढ़ जाएगी। हालांकि भाजपा घुसपैठ को 2026 के चुनाव में प्रमुख विषय बना रही है। हालांकि मुस्लिम वोट एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ मतदान करता है, इसलिए यह भाजपा के लिए एक संरचनात्मक चुनौती भी है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह चुनाव सिर्फ बंगाली हिंदुओं को बचाने का नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने से रोकने का है। कांग्रेस, वाम दल, हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी सहित अन्य छोटे-छोटे दलों का चुनाव बाद भाजपा को रोकने के लिए टीएमसी के समर्थन में आना तय है, इसलिए यह चुनाव भाजपा बनाम अन्य सभी दलों का हो गया है।

हिमंता के मुकाबले कोई नहीं

असम विधानसभा चुनाव में भी घमासान शुरू हो गया है। यहां एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होना है। लिहाजा असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई के बीच घमासान चरम पर है। 2016 में पहली बार भाजपा ने असम की सत्ता हासिल कर सर्वानंद सोनवाल को सीएम बनाया था। 2021 के चुनाव में भाजपा ने फिर सत्ता हासिल की और हिमंता बिस्वा सरमा को सीएम की गद्दी सौंपी। 2026 का चुनाव हिमंता बिस्वा सरमा के ही चेहरे पर लड़ा जा रहा है। इसलिए कांग्रेस के लिए यह चुनाव महत्वपूर्ण है। कांग्रेस जहां सत्ता में वापसी के लिए बेताब है वहीं भाजपा हैट्रिक लगाने के लिए उत्सुक है। वैसे भी गृह मंत्री अमित शाह साफ कर चुके हैं कि असम में सीएम का चेहरा हिमंता बिस्वा सरमा ही हैं। जबकि असम में कांग्रेस 2014 के बाद से अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। इसके लिए कांग्रेस ने एक प्रयोग मई 2025 में किया। असम के कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा को हटाकर सांसद गौरव गोगोई को असम कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस का तर्क था कि वह युवाओं को नेतृत्व सौंप रही है। लेकिन गौरव गोगोई के ही कालखंड असम कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। क्योंकि गौरव गोगोई को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से असम कांग्रेस के कुछ नेता नाराज थे। लिहाजा प्रियंका गांधी को विधानसभा चुनाव से पहले असम कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाकर संदेश दिया गया कि भले ही प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई हैं, लेकिन फैसले सिर्फ गांधी फैमिली ही लेगी। कांग्रेसियों में बढ़ रहे असंतोष को कम करने के लिए भूपेश बघेल और डीके शिवकुमार को चुनाव प्रभारी बनाया गया। भाजपा ने कांग्रेस को घेरने के लिए गौरव गोगोई की पत्नी पर पाकिस्तान से सैलरी लेने का आरोप लगाया। हिमंता बिस्वा सरमा ने प्रेस कांफ्रेंस कर दावा किया कि गौरव गोगोई ने भी पाकिस्तान का दौरा किया है। 2013 में गौरव गोगोई की पाकिस्तान यात्रा के दौरान आवाजाही से जुड़ी अनुमति पाक गृह मंत्रालय ने बदल दी थी। एक सच ये भी है कि हिमंता बिस्वा सरमा के कद का कोई लीडर असम में कांग्रेस के पास नहीं है। हिमंता की लोकप्रियता सिर्फ असम तक ही नहीं है बल्कि उत्तर भारतीय राज्यों तक में है। वहीं नार्थ ईस्ट में भाजपा की रणनीति हिमंता ही देखते हैं। 2021 में हिमंता के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके नेतृत्व में भाजपा असम में न सिर्फ हर चुनाव जीती बल्कि कांग्रेस पर बहुत भारी पड़ी। विधानसभा चुनाव में भाजपा की रणनीति स्पष्ट है कि वो हिंदुत्व, डेमाग्राफी चेंज, सांस्कृतिक पहचान और घुसपैठ का नैरेटिव बनाएगी। लिहाजा कांग्रेस इसका जवाब कैसे देगी यह कांग्रेस ने सोचा ही नहीं है। कांग्रेस का सीधा फंडा है मुस्लिम बहुल सीटों पर ध्रुवीकरण का फायदा उसे मिल जाए। बदले में भले ही भाजपा को हिंदु बहुल सीटों का फायदा क्यों हो। ●

तकनीक

एआई से चुनौतियां

इलोन मस्क जिस रफ्तार से दुनिया का कायाकल्प होने की कल्पना कर रहे हैं वह दूर की कौड़ी लगती है, अब तक हुई चारों औद्योगिक क्रांतियों में से किसी ने भी रोशनी या ध्वनि की रफ्तार को मात देते हुए ऐसे परिणाम नहीं दिए हैं, जेट और इंटरनेट के दौर में आज भी दक्षिण एशिया तथा अफ्रीका के देशों में किसान जानवरों के साथ हल चलाते दिखाई देते हैं।

बाबू सिंह
वरिष्ठ पत्रकार

भारत में एआई को लेकर बढ़ती बहस के बीच व्हाइट कॉलर नौकरियों, आईटी सेक्टर और बैंकिंग इंडस्ट्री पर इसके असर को लेकर चिंता भी तेज हो गई है। क्या एआई बड़े पैमाने पर रोजगार खत्म कर देगा या यह नई संभावनाएं पैदा करेगा? क्योंकि आज हम एक कमाल की दुविधा से जूझ रहे हैं और वो यह कि एआई का इस्तेमाल करें या न करें! इस्तेमाल न करना कोई विकल्प नहीं रह गया है क्योंकि ऐसा करना आपको डिजिटल डायनोसोर बना देगा। दूसरी तरफ इस्तेमाल करने की अपनी दुविधाएं हैं, कम से कम उन लोगों के लिए जिनके लिए इसका प्रयोग उनके काम तक सीमित है। जो एआई में अपनी दक्षता को बहुत आगे तक ले जाने के इच्छुक नहीं हैं या जिनकी सीमाएं इसमें आड़े आ जाती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की टॉप कंपनियों में से एक सेल्सफोर्स ने ऐलान किया था कि 2025 में वह सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की भर्ती नहीं करेगी। क्योंकि एआई ने इंजीनियरिंग का आउटपुट इतना बढ़ा दिया है कि नए लोगों की जरूरत ही नहीं है। जरा सोचिए, सेल्सफोर्स की एआई इस स्तर तक कैसे पहुंची होगी? भारत का ही उदाहरण देखिए। 'दुकान' नामक स्टार्टअप के सीईओ ने कुछ महीने पहले कहा था कि उन्होंने अपनी कस्टमर सपोर्ट टीम के 90 प्रतिशत लोगों की छुट्टी कर दी है, क्योंकि उनका काम अब एआई एजेंट (एप्लीकेशन) करने लगा है। टेस्ला के सीईओ और इनोवेटरइलोन मस्क एकदम अलग, नए, क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में अमेरिका-सऊदी निवेश मंच की बैठक में कहा कि अगले दस से 20 साल के भीतर पैसा मायने नहीं रखेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट ऐसी स्थिति ले आएंगे कि इंसान के लिए काम करने की अनिवार्यता नहीं रह जाएगी। काम करें या न करें, यह एक वैकल्पिक सवाल होगा। वैसे ही, जैसे आप चाहें तो बाजार से सब्जी ला सकते हैं या अपने बगीचे में खुद सब्जियां उगा सकते हैं। सब्जियां उगाना काफी मेहनत का काम है लेकिन कुछ लोग फिर भी ऐसा करते हैं क्योंकि वह उन्हें पसंद है। जैसे वक्त काटने के लिए कुछ लोग खेल खेलते हैं और कुछ वीडियो गेम खेलते हैं, वैसे ही कुछ लोग-अगर चाहें तो-काम करेंगे।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट ऐसी स्थिति ले आएंगे कि इंसान के लिए काम करने की अनिवार्यता नहीं रह जाएगी, काम करें या न करें, यह एक वैकल्पिक सवाल होगा, वैसे ही, जैसे आप चाहें तो बाजार से सब्जी ला सकते हैं या अपने बगीचे में खुद सब्जियां उगा सकते हैं।

शारीरिक काम करने के लिए रोबोट होंगे

मस्क के मुताबिक भविष्य में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (एजीआई) भी आ चुकी होगी जो क्षमताओं में इंसान के समकक्ष होगी। तब दुनिया भर में काम कर रहे करोड़ों कुशल रोबोट उत्पादकता का ऐसा गुबार उठाएंगे कि हमारे लिए काम करने की मजबूरी नहीं रहेगी। ऑटोमैटिक ढंग से चलने वाली दुनिया का यह सपना, एक हजार अरब डॉलर की तनख्वाह लेने वाले मस्क के लिए अमेरिका के शानदार दफ्तर में बैठकर देखना आकर्षक है। लेकिन जब इसे भारत, ब्राजील या दक्षिण अफ्रीका की नजर से देखते हैं तो वह हकीकत से कटा हुआ दिखाई देता है। वह आज की कड़वी सच्चाइयों को छिपा देता है। अब यह भी सवाल उठाता है कि इस 'रोबोट स्वर्ग' का फायदा किसे मिलेगा और कब मिलेगा? माना कि दुनिया में शारीरिक काम करने के लिए रोबोट होंगे और मानसिक काम करने के लिए चैटबॉट, बॉट्स या ऑटोमैटिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन तथा वेब सेवाएं। वाहन भी अपने आप चल रहे होंगे और बहुत सारे सिस्टम भी इंसानी इनपुट पर निर्भर नहीं होंगे। फिर भी मस्क जिस रफ्तार से दुनिया का कायाकल्प हो जाने की कल्पना कर रहे हैं वह दूर की कौड़ी लगती है। अब तक हुई चारों औद्योगिक क्रांतियों में से किसी ने भी रोशनी या ध्वनि की रफ्तार को मात देते हुए ऐसे परिणाम दिए हैं क्या? जेट और इंटरनेट के दौर में आज भी दक्षिण एशिया तथा अफ्रीका के देशों में किसान जानवरों के साथ हल चलाते हुए दिखाई देते हैं।एआई रोजगार और आमदनी को प्रभावित करेगा?

हर काम करने के लिए रोबोट और एआई एप्लिकेशंस होंगे लेकिन उनकी पहुंच कितनी दूर तक होगी और उन्हें इस्तेमाल करना कितना सस्ता होगा? अगर मस्क की कल्पना का विश्व सामने आता है तो जाहिर है कि एआई बहुत बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार और आमदनी को प्रभावित कर चुका होगा। तब क्या आम आदमी उस पर खर्च करने की स्थिति में होगा। क्या सरकारें जनहित में अपने-अपने देशों में अनगिनत रोबोट तैनात करेंगी? अगर कुछ कंपनियां ही वैश्विक स्तर पर इस तरह के रोबोट तथा बॉट्स के संचालन का दायित्व संभाल लेंगी, जैसा कि आज एआई के मामले में हो रहा है, तो दुनिया का नियंत्रण क्या चंद उद्योगपतियों व कारोबारियों के हाथों में संघनित नहीं हो जाएगा क्या? क्या भारत जैसे विकासशील देशों में, जहां 80 प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में हैं, वहां रोबोटिक्स की बड़े पैमाने पर तैनाती संभव होगी? या यह अमीर देशों की सनक बनकर रह जाएगी? मान लीजिए कि ऐसी तैनाती हो भी जाए तो घर पर बैठे इंसानों के धन का स्रोत क्या होगा? मस्क ने जिस तरह की अवधारणा को आगे बढ़ाया है, उसका जिक्र लेखक स्कॉटिश लेख इयानएम डाट बैंक्स ने अपनी विज्ञान-कथा शृंखला में किया है जिसका नाम है, 'कल्चर'। इसमें कल्पना की गई है कि सुपर इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को काम के बंधन से आजाद कर देती है और धन-दौलत को अर्थहीन बना देती है। लेकिन यह बदलाव कैसे संभव होगा, इस पर बैंक्स की किताबें मुनासिब रोशनी नहीं डालतीं। मस्क इसके लिए 'यूनिवर्सल हाइइन्कम' नाम की अवधारणा को आगे करते हैं। उन्हें लगता है कि सरकारें लोगों को एक तय आय मुहैया कराएंगी।

क्या बदलेगा जीवन का मकसद

आठ अरब की आबादी वाली दुनिया में जहां तमाम तरह की असमानताएं, बाधाएं, नाइंसाफियां और विभाजन मौजूद हैं, वहां क्या ऐसा कर पाना सचमुच संभव है? ऐसी स्थिति में बाजार का क्या होगा? अर्थव्यवस्थाएं कहां होंगी? इलोन मस्क की तुलना में कुछ दूसरे आईटी दिग्गजों ने एआई से आने वाले बदलाव को थोड़ा अधिक व्यावहारिक नजरिए से देखा है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स एआई के कारण काम के सप्ताह को 2-3 दिनों तक कम होते देखते हैं जो काल्पनिक तो लगता है लेकिन मस्क की बातों जितना नहीं। मस्क की 'यूनिवर्सल हाइइन्कम' के बरक्स ओपन एआई के सैमऑल्टमैन 'यूनवर्सल बेसिक इंकम' की बात करते हैं जहां उनकी दिशा अलग है। उनका कहना है कि अगर एजीआई की वजह से कामगार प्रभावित होते हैं तो सरकारें उनके लिए एक न्यूनतम आय की व्यवस्था करेंगी। यह असंभव नहीं है और कुछ हद तक सामाजिक सुरक्षा जैसा ही है। अमेरिका जैसे बहुत सारे देशों में नौकरी छूटने पर कर्मचारियों को सरकारी भत्ता मिलने लगता है। हमारे यहां भी तो किसानों, बुजुर्गों आदि के लिए सरकारी धन की व्यवस्था है। अब कुछ गहरे सवाल, जिनमें से एक यह कि अगर कंप्यूटर और रोबोट हर काम आपसे बेहतर कर सकते हैं, तो आपकी जिंदगी का अर्थ क्या रहा? इलोन मस्क कहते हैं कि हमारी जिंदगी का अर्थ फिर भी रहेगा और वह है-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अर्थ देना (सफल बनाना)। यह बहुत हल्का और सतही जवाब है। जीवन के अर्थ के बारे में जानना है तो उन्हें भारत की ओर देखना चाहिए, हमारे दर्शन और चिंतन की ओर देखना चाहिए। नहीं तो पश्चिमी दुनिया के महान दार्शनिकों को ही पढ़ लेना चाहिए। अगर हमारे जीवन से काम गायब हो जाए तो वह सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं होगा। वह इंसान के होने के मकसद को ही बदल देगा। अगर मस्क के सपनों की दुनिया आई भी तो क्या हम उसे न्यायपूर्ण और समानता पर आधारित बना सकेंगे? या फिर वह चंद अमीर देशों और अमीर लोगों तक सीमित रहेगी जिनके लिए काम एक वैकल्पिक चीज होगा और पैसा कोई मुद्दा नहीं।

डीपफेक का खतरा

भारत में अदृश्य श्रम-बल बहुत बड़ी संख्या में एआई प्रणालियों को प्रशिक्षित करने में जुटा है। हजारों डेटा एनोटेटर्स, कंटेंट मॉडरेटर, क्वालिटी चेकर्स आदि-आदि अक्सर 15,000-25,000 रुपये मासिक कमाते हुए चित्रों को लेबल कर रहे हैं, हानिकारक कंटेंट को चिह्नित कर रहे हैं, एआई से मिलने वाले परिणामों की ग्रेडिंग कर रहे हैं, भाषाई संवादों की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वातावरण, लोगों तथा दस्तावेजों के फोटो लोड कर रहे हैं। वे मशीनों को देखना, बोलना और सोचना सिखा रहे हैं। ऐसा न करने का विकल्प उपलब्ध नहीं है। आने वाले समय में इसका उपयोग बढ़ना तय है। ऐसे में हमें इसके नकारात्मक प्रभावों को लेकर अभी से सचेत हो जाना होगा। यह उनका रोजगार है और यही एआई के हित में भी है। एआई से रोजगार में कमी, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा, तथा नैतिक पूर्वाग्रह जैसी गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। इसके अलावा, डीपफेक से गलत सूचना फैलने, मानव निर्भरता बढ़ने और उच्च-गुणवत्ता वाले डेटा की कमी के कारण एआई सिस्टम के गलत परिणाम देने का जोखिम बढ़ गया है। लेकिन दुनिया में चल रही ऐसी अनगिनत गतिविधियों का अंतिम नतीजा क्या होगा? यह सवाल आपके लिए है।

• अगर हमारे जीवन से काम गायब हो जाए तो वह सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं होगा, वह इंसान के होने के मकसद को ही बदल देगा, अगर मस्क के सपनों की दुनिया आई तो क्या हम उसे न्यायपूर्ण और समानता पर आधारित बना सकेंगे? या फिर वह चंद अमीर देशों और अमीर लोगों तक सीमित रहेगी जिनके लिए काम एक वैकल्पिक चीज होगा और पैसा कोई मुद्दा नहीं।

• माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स एआई के कारण काम के सप्ताह को 2-3 दिनों तक कम होते देखते हैं जो काल्पनिक तो लगता है लेकिन मस्क की बातों जितना नहीं, मस्क की 'यूनिवर्सल हाइइन्कम' के बरक्स ओपन एआई के सैमऑल्टमैन 'यूनवर्सल बेसिक इंकम' की बात करते हैं जहां उनकी दिशा अलग है।

बगोरी गांव का अनोखा सौंदर्य

बगोरी के लोग जड़ी-बूटियों का व्यापार करते हैं, यहां की चाय बहुत मशहूर है, यहां के लोग चाय में एक प्रकार की जड़ी-बूटी डालते हैं, जिससे चाय में अलग ही तरह का स्वाद आता है, सैलानियों को यहां मशरुम की कई प्रजातियां मिल जाएंगी, अगर पर्यटक खाने के शौकीन हैं, तो उन्हें कई स्वादिष्ट व्यंजन यहां खाने को मिल जाएंगे।

अफजल फौजी
नैनीताल

प्रकृति प्रेमी और घूमने के शौकीन लोगों को हमेशा ही नए-नए डेस्टिनेशन की तलाश रहती है, जहां वो कुछ अलग देख सकें और कुछ अलग अनुभव कर सकें। क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड का अधिकांश हिस्सा तो पहाड़ पर ही बसा है। लेकिन घूमने का मजा तब और ज्यादा बढ़ जाता है, जब प्राकृतिक सौंदर्य के साथ उस स्थान का कोई सांस्कृतिक, धार्मिक या ऐतिहासिक महत्व भी हो। उत्तराखंड में वैसे तो बहुत से प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जहां टूरिस्ट बड़ी संख्या में आते हैं और प्रकृति का हिस्सा बनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तराखंड में एक ऐसा गांव मौजूद है, जहां सैलानी खूबसूरत दृश्यों के साथ, कई नायाब चीजें देख सकते हैं। ऐसा ही एक गांव बगोरी उत्तरकाशी जिले में है। जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं से समृद्ध है। यहां टूरिस्ट को कई सारी इमारतों के साथ प्राकृतिक सौंदर्य के बेहद अनोखे अंदाज देखने को मिलते हैं। यह बागोरी गांव खेती, बाग, प्राकृतिक सौंदर्य आदि के लिहाज बहुत खास है। साथ ही, यहां पर्यटकों को हाथ से बनी हुई कई कलाकारी यानी हस्तकला देखने को मिल जाएगी। खासतौर से यहां के लोग जड़ी-बूटियों का व्यापार करते हैं। इसलिए यहां की चाय बहुत मशहूर है, क्योंकि यहां के लोग चाय में एक प्रकार की जड़ी-बूटी डालते हैं, जिससे चाय में अलग ही तरह का स्वाद आता है। इसके अलावा सैलानियों को यहां मशरूम की कई प्रजातियां भी मिल जाएंगी। यहां के लोग खाने में मशरूम ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर पर्यटक खाने के शौकीन हैं, तो उन्हें कई स्वादिष्ट व्यंजन यहां खाने को मिल जाएंगे। यह गांव चीन से बहुत नजदीक है इसलिए यहां पर्यटकों को कई चाइनीज खाने के व्यंजन मिल जाएंगे जैसे, नूडल्स, मोमोज आदि। पर्यटक इन व्यंजनों का भी लुत्फ भी उठा सकते हैं। कुल मिलाकर बागोरी गांव किसी जन्नत से कम नहीं है।

- **'ग्रीन विलेज' यानी हरित गांव के नाम से भी बगोरी को जाना जाता है, ईको-फ्रेंडली डेस्टिनेशन पसंद करने वाले पर्यटकों के लिए ये एकदम बेस्ट ऑप्शन है, इस गांव में चारों ओर हरियाली है, आपको यहां तिब्बती लोग और उनकी संस्कृति, आजीविकाओं के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा।**
- **बगोरी गांव में एक बौद्ध मठ के साथ-साथ मंदिर भी है, जहां सभी आस्था के साथ सिर झुकाते हैं, बगोरी में जादुंग और नेलांग के मूल निवासी रहते हैं, जिन्हें जाड़ कहा जाता है, इसके अलावा गांव में एक आबादी ऐसी भी है, जो यहीं की मूल निवासी है, यहां कुल मिलाकर 250 के करीब परिवार निवास करते हैं, जो सिर्फ गर्मियों में यहां रहते हैं।**

ईको-फ्रेंडली डेस्टिनेशन

उत्तराखंड में अन्य हिल स्टेशन के साथ बगोरी गांव की भी सैर जरूर करनी चाहिए क्योंकि यह गांव अपने आप में बेहद खास है। कहा जाता है कि 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान सीमा पर बसे जादुंग और नेलांग गांव खाली हो गए थे और वहां के अधिकतर परिवार बगोरी गांव में आकर बस गए थे। इसलिए यहां ज्यादातर तिब्बती परिवार मिलेंगे। हालांकि बगोरी बहुत छोटा-सा गांव है, यहां की आबादी भी बहुत कम है। यह जगह बहुत शांत है अगर आपको शांति पसंद है, तो यह जगह आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। यहां आपको कई प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलेंगे। इस गांव के बराबर से जलनधारी नदी भी बहती है, जो आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। साथ ही यहां का सारा एरिया पाइन और चीड़-मजनू के पेड़ों से पटा पड़ा है। सर्दियों में यहां खूब बर्फ गिरती है। यहां टूरिस्ट को सेबों के कई खूबसूरत बाग देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, तो हर्षिल कैंट एरिया के पास छोटा सा मार्केट भी है। जहां से पर्यटक अपनी पसंद का कुछ हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। यह 'ग्रीन विलेज' यानी हरित गांव के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह ईको-फ्रेंडली डेस्टिनेशन पसंद करने वाले पर्यटकों के लिए भी एकदम बेस्ट ऑप्शन है। इस गांव में चारों ओर हरियाली है। अगर आप इस गांव का रुख करते हैं, तो आपको यहां तिब्बती लोग और उनकी संस्कृति, आजीविकाओं के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। यहां आप तिब्बत के पारंपरिक खाने का लुत्फ भी उठा सकते हैं। कुछ स्थान अनछुए होते हैं, जिसे छुआ तो मैले होने का डर रहता है। लिहाजा उन्हें छूकर नहीं, बल्कि देखकर महसूस किया जा सकता है। जैसे उसकी खूबसूरती और उसका नायाबपन अनोखा हो। भोटिया गांव बगोरी अपने आप में खूबसूरती के अलग-अलग आयाम समेटे हुए है। लेकिन यह गांव अभी तक पर्यटकों की नजरों से दूर है, किंतु अब धीरे-धीरे पर्यटक बागोरी गांव पहुंचने लगे हैं। गांव में लकड़ी के खूबसूरत घर और सेब के बगीचे बगोरी गांव की सबसे बड़ी खासियत है।

बगोरी गांव का ऐतिहासिक महत्व

पर्यटन ग्राम हर्षिल से महज एक किलोमीटर की दूरी तय कर बगोरी गांव पहुंच सकते है। दोपहिया गाड़ी भी गांव तक जा सकती है, लेकिन अगर आप पैदल जाएंगे तो कल-कल बहती नदी पर बने सुंदर पुलों और बर्फ से ढकी चोटियों के दीदार आसानी से कर पाएंगे। हिमालय की गोद में बसे इस गांव की प्राकृतिक सुंदरता वाकई अद्भुत है। गांव के चारों ओर नजर घुमाएं तो बर्फ से ढकी चोटियां और देवदार के घने जंगल नजर आते हैं। हर्षिल से बगोरी तक के सफर में सात छोटे-छोटे पुल आते हैं, जो बेहद खूबसूरत हैं। वहीं गांव के आखिरी छोर पर भागीरथी और सिंहगाड का संगम है, जहां हिमालय की गोद में बहती नदी का नजारा वाकई विहंगम होता है। कहा जाता है कि 1962 में भारत-चीन युद्ध से पहले जादुंग और नेलांग के लोग तिब्बत के साथ व्यापार किया करते थे, जो उनकी आजीविका का मुख्य साधन हुआ करता था। बगोरी के ग्रामीणों का कहना है कि वे तिब्बत से नमक का व्यापार करते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनीं कि उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा और उन्होंने आजीविका के नए साधन तलाश लिए। अब सेब की बागवानी के अलावा भी लोग अलग-अलग रोजगारों से जुड़ गए हैं। बगोरी गांव में एक बौद्ध मठ के साथ-साथ मंदिर भी है, जहां सभी आस्था के साथ सिर झुकाते हैं। बगोरी में जादुंग और नेलांग के मूल निवासी रहते हैं, जिन्हें जाड़ कहा जाता है। इसके अलावा गांव में एक आबादी ऐसी भी है, जो यहीं की मूल निवासी है। यहां कुल मिलाकर 250 के करीब परिवार निवास करते हैं, जो सिर्फ गर्मियों में यहां रहते हैं। सर्दियों में गांव बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है इसलिए यहां के परिवार नीचे डुंडा और उत्तरकाशी के आसपास के गांवों की तरफ चले जाते हैं। गांव की एक खासियत यह है कि गांव में सभी घर लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी से बने हैं। यानी घरों पर फूलों से लेकर बेलों तक की शानदार नक्काशी की गई है। घरों के दरवाजों से लेकर खंभों तक की बनावट बरबस ही मन मोह लेती है। वहीं कई घरों पर बौद्ध मंत्र भी खुदे हैं, तो कहीं लोगों ने अपना नाम खुदा रखा है। गांव की पतली सी गली से गुजरते हुए हर एक घर पर नजर ठहर जाती है। पुराने घरों के अलावा यहां कई नए घर सीमेंट से भी बन गए हैं।

बगोरी गांव में लोक उत्सव पर बकरे की बलि की परंपरा है, जिसे स्थानीय देवी-देवताओं को प्रसन्न करने और गांव की खुशहाली व सुरक्षा के लिए 'निकाली पूजा' जैसे अनुष्ठानों के तहत किया जाता है, हालांकि बलि की यह प्रथा भारत के कई हिस्सों में प्रचलित है, जहां श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने या किसी समस्या के निवारण के लिए बलि देते हैं।

ग्रामीणों का जड़ी बूटी का ज्ञान

जंगल और पहाड़ों में रहने वाले बगोरी गांव के अधिकांश परिवारों को जड़ी-बूटियों की पहचान होती है। यहां के लोग चाय में एक विशेष प्रकार की जड़ी-बूटी डालते हैं, जिसका अलग ही स्वाद आता है। यहां आने वाले वो पर्यटक खुशनसीब होते हैं जिन्हें यह जड़ी-बूटी वाली चाय पीने का अवसर मिलता है। यहां मशरूम की कई प्रजातियों का लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। बगोरी गांव के अलावा आसपास के गांवों के लोगों के भी सेब के बगीचे यहां हैं। अप्रैल में गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद ग्रामीणों के बगोरी आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। यह सीजन सेब के फ्लावरिंग का होता है और यहां के निवासियों को अपने सेब के बगीचों की देखभाल करनी होती है। इस दौरान वो कीटनाशक का छिड़काव करते हैं और सेब की तुड़ाई तक यहीं रहते हैं। हर्षिल में खाद्य और प्रसंस्करण की एक यूनिट है, जहां कोल्ड स्टोरेज भी है। इसके अलावा हर्षिल और बगोरी के सेब की मार्केट में भी काफी डिमांड है। बगोरी गांव जाने के लिए सबसे उचित समय अप्रैल अंत और मई के बाद का है, जब ग्रामीण यहां आ जाते हैं और काफी चहल-पहल होती है। देहरादून से 220 किलोमीटर का सफर तय कर बगोरी गांव पहुंचा जा सकता है। हर्षिल तक चार पहिया और दोपहिया गाड़ियां जाती हैं, लेकिन बगोरी जाने के लिए सिर्फ बाइक या पैदल ही सफर तय करना होता है। बगोरी गांव में रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हर्षिल में आपको हर तरह के होटल मिल जाएंगे। यहां गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस भी है, जिसमें आप रिवर व्यू रूम लेकर कल-कल कर बहती भागीरथी को करीब से महसूस कर सकते हैं।

बंद होनी चाहिए बलि प्रथा

बगोरी गांव में लोक उत्सव पर बकरे की बलि की परंपरा है, जिसे स्थानीय देवी-देवताओं को प्रसन्न करने और गांव की खुशहाली व सुरक्षा के लिए 'निकाली पूजा' जैसे अनुष्ठानों के तहत किया जाता है। हालांकि बलि की यह प्रथा भारत के कई हिस्सों में प्रचलित है, जहां श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने या किसी समस्या के निवारण के लिए बलि देते हैं, हालांकि अब कई जगहों पर फल और फूलों का प्रसाद चढ़ाने का प्रचलन बढ़ रहा है। बगोरी जैसे गांवों में हर तीन साल में होने वाली इस विशेष 'निकाली पूजा' में बकरे की बलि दी जाती है, जिसे ग्रामीण देवी-देवताओं को समर्पित करते हैं। मान्यता यह है कि ये प्रथा देवताओं को प्रसन्न करने, बुरी शक्तियों से बचाने और गांव में सुख-समृद्धि लाने के लिए प्रचलित है। जैसा कि मध्य प्रदेश के एक गांव में भी बकरे की बलि के बाद विकास होने की मान्यता है। बगोरी गांव के कई लोग मानते हैं कि यह अनुष्ठान मां काली जैसी देवियों को प्रसन्न करता है और आशीर्वाद दिलाता है। कुछ स्थानों पर खासकर जहां बलि के बाद समस्याएं (संक्रमित मांस खाने) सामने आई हैं, वहां अब फल, नारियल और फूलों से पूजा करने का चलन बढ़ रहा है। नई पढ़ी लिखी पीढ़ी बलि जैसी प्रथा के खिलाफ नजर आ रही है। जेन जी सवाल उठाता है कि बलि देना कहां तक सार्थक है। क्या हम इंसान अपने स्वार्थ के लिए भगवान के नाम पर ये बलि देते है? एक युवा गांव आया तो घर में पूजा, जागर का कार्यक्रम हुआ। 5 बकरियों की बलि दी गई। अपने सामने ये सब कुछ देखकर युवा के मन में कई सवाल पैदा हुए। एक निरीह जीव जो अपनी पीड़ा कह नहीं सकता उस पर ये अत्याचार क्यों? जबकि हमारे पैर में एक कांटा भी चुभ जाता तो दर्द से तड़पने लगते है, लेकिन इनका क्या कौन समझेगा बेजुबानों का दर्द? शायद वही समझ पाएगा जिनके अंदर संवेदना होगी। सवाल ये भी कि क्या बलि के नाम पर यह प्रथा खत्म नहीं की जा सकती है? अल्मोड़ा के गोल्जू देवता के मंदिर में ये प्रथा खत्म हो चुकी है। युवाओं को ऐसी प्रथाओं का विरोध करना चाहिए। जिससे बेजुबानों पर अत्याचार होने से थम सके। ●

अफसोस

लुप्त हो रहे भगनौल

कुमाऊंनी होली रंगों से ज्यादा संगीत और लोकगीतों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, इन्हीं गीतों में ऐसी परंपरा शामिल है जो गांवों में हंसी और ठहाकों की गारंटी मानी जाती थी, इसे 'भगनौल' कहा जाता है, व्यंग्य और चुटकुलों से भरे लोकगीत मनोरंजन का साधन थे, आपसी एकता का प्रतीक भी थे, लेकिन पलायन और आधुनिकता से ये पारंपरिक स्वर धुंधले पड़ते जा रहे है।

डॉ.हरीश चंद्र अंडोला
दून यूनिवर्सिटी

उत्तराखंड देवभूमि के कण-कण में शिवत्व की अनुभूति का एहसास अनुभव किया जा सकता है। इसलिए इस पहाड़ी राज्य को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। जहां बाबा भोलेनाथ की बात हो रही हो तो उनके वाद्य यंत्र की बात कैसे अछूती रह सकती है। जो भगवान शिव को काफी पसंद भी है। माना जाता है कि देवभूमि उत्तराखंड में खास मौकों पर बजाया जाने वाला ढोल-दमाऊ की उत्पत्ति शिव के डमरू से हुई है। उत्तराखंड की कुमाऊंनी होली रंगों से ज्यादा अपने संगीत और लोकगीतों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इन्हीं गीतों में एक ऐसी परंपरा शामिल है जो कभी गांवों में हंसी और ठहाकों की गारंटी मानी जाती थी, जिसे 'भगनौल' कहा जाता है। हल्के व्यंग्य और चुटकुलों से भरे ये लोकगीत न केवल मनोरंजन का साधन थे, बल्कि आपसी एकता का प्रतीक भी थे, लेकिन पलायन और आधुनिकता के शोर में अब ये पारंपरिक स्वर धुंधले पड़ते जा रहे है। भगनौल असल में हंसी-मजाक और व्यंग्य से भरे लोकगीत होते हैं। इन्हें खास तौर पर होली के दौरान गांव के बुजुर्गों द्वारा गाया जाता है। इन गीतों में हल्के कटाक्ष और मजेदार बातें शामिल होती हैं। भगनौल कुमाऊंनी लोक गीतों की एक विधा है। इसके गायक को भगनौली कहते हैं। भगनोल में गायक और उसके साथ उसके सुरों को विस्तार देने वाले (जिसे ह्योव भरना कहा जाता है) दो या तीन साथी होते हैं। बैर-भगनौल दो पक्षों के बीच एक प्रकार का गायन वाकयुद्ध होता है। जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को भगनौल गा कर सवाल-जवाब करते हैं। गायक की कुशलता उसके ज्ञान, वाकचातुर्य और प्रत्युत्पन्नमतित्व पर निर्भर करती है। एक तरह से भगनौल लोक गीत गायकों की व्यंग्य विनोदपूर्ण मनोरंजन रचनाएं है। यानी जब होली के त्योहार पर हुड़दंग के बीच गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो ढोलक, मंजीरा और हुड़के की थाप पर भगनौल की महफिल सजती है। इन गीतों में अक्सर किसी व्यक्ति, जानवर या गांव की किसी रोचक घटना को मजाकिया अंदाज में गाया जाता है, जैसे एक लोकप्रिय भगनौल की पंक्तियां हैं-

'शाबाश मेरा मोतिया बल्दा, तोड़ी लें गे छे सिंगा,
9 रुपये क मोतिया बल्दा, 100 रुपये क सिंगा।'

इन पंक्तियों में मुख्य रूप से इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कभी-कभी किसी व्यक्ति या वस्तु की आंतरिक कीमत (जैसे बैल की कीमत) से कहीं अधिक बाहरी या सजावटी चीजों (जैसे सींगों की कीमत) को महत्व दिया जाता है। यह समाज में मौजूद उस विडंबना को दर्शाता है जहां लोग वास्तविक मूल्य को नजर अंदाज कर दिखावे या सतही चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर देखते हैं। यानी इन पंक्तियों के जरिए मजेदार ढंग से बातें की जाती हैं, जिससे सुनने वाले ठहाके लगाने को मजबूर हो जाते हैं। भगनौल के बाद 'जोड़' गाने की भी एक विशेष परंपरा रही है। जोड़ का अर्थ होता है किसी गीत को आगे बढ़ाना या उसे नया मोड़ देना। इसमें गायक देवी-देवताओं, गांव की प्राचीन मान्यताओं या किसी खास प्रसंग को मुख्य गीत के साथ जोड़ देते थे...।

'धार में देवी को थाना, दुधल नवायो,
तेरो जूठ मी नि खांची, माया लें खवायो।'

यह पंक्तियां माता या देवी के प्रति समर्पण और श्रद्धा को दर्शाती हैं। यानी श्रद्धालु देवी मां से कहता है कि हे माता! आपका मंदिर ऊंची धार पर स्थित है, जहां मैंने आपका दूध से अभिषेक किया है। मैं आपका जूठा (प्रसाद) तो नहीं खाता, परंतु मैं आपका अपना हूं, इसलिए आप मुझे अपनी ममता और प्रेम (माया) से खिलाती हैं। यह पंक्ति देवी के प्रति निश्छल भक्ति और मां-बच्चे के रिश्ते जैसी श्रद्धा को दिखाती है, जहां भक्त देवी को केवल शक्ति नहीं, बल्कि मां मानकर अपनी बात कहता है।

युवा पढ़ाई और नौकरी के लिए शहरों की ओर पलायन कर गए हैं और मोबाइल व फिल्मी गानों के बढ़ते चलन ने पारंपरिक लोकगीतों को पीछे छोड़ दिया है, अब गांवों में केवल कुछ ही बुजुर्ग बचे हैं जो भगनौल गा सकते हैं, जबकि नई पीढ़ी इन गीतों की गहराई से पूरी तरह अनजान है।

आधुनिकता ने भगनौल को पीछे छोड़ा

इस तरह एक गीत से दूसरा गीत जुड़ता जाता था और पूरी रात गीत-संगीत का सिलसिला चलता रहता था। यह परंपरा पीढ़ियों से मौखिक रूप से एक-दूसरे तक पहुंचती रही है। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि पहले के समय में होली के दौरान हर शाम बैठकी होती थी, जहां बुजुर्ग अपने अनुभव और लोकगीतों के जरिए नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ते थे। लेकिन आज पलायन और आधुनिकता के कारण यह परंपरा दम तोड़ रही है। युवा पढ़ाई और नौकरी के लिए शहरों की ओर पलायन कर गए हैं और मोबाइल व फिल्मी गानों के बढ़ते चलन ने पारंपरिक लोकगीतों को पीछे छोड़ दिया है। अब गांवों में केवल कुछ ही बुजुर्ग बचे हैं जो भगनौल गा सकते हैं, जबकि नई पीढ़ी इन गीतों की गहराई से पूरी तरह अनजान है। सांस्कृतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते इस परंपरा को नहीं सहेजा गया, तो आने वाले वर्षों में भगनौल केवल किताबों और यादों तक ही सीमित रह जाएगे। बुजुर्गों का कहना है कि गांवों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना और युवाओं को इन गीतों को सीखने के लिए प्रेरित करना बेहद जरूरी है। पहाड़ी होली की यह अनमोल विरासत हमारी सांस्कृतिक जड़ें हैं। हमें मिलकर इस परंपरा को बचाना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी पहाड़ की इस सादगी और हंसी से जुड़ी रह सकें। स्थानीय लोक संस्कृति के जानकार बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था, जब बस्तियों के चौराहों पर बैर भगनौल करने वालों की भारी भीड़ हुआ करती थी। आज युवा पीढ़ी इससे काफी दूर है। उनका मानना है कि भगनौल के कुछ जानकार आज भी अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए हुए हैं। अगर शासन और प्रशासन इस ओर ध्यान दें तो इस पौराणिक संस्कृति को बचाया जा सकता है।

विदेशी भी चिंतित

देवभूमि उत्तराखंड में खास मौकों पर ढोल-दमाऊ की थाप अभी भी सुनाई देती है। इसके बिना देवभूमि में मांगलिक कार्य अधूरे से लगते हैं। ढोल वाद्य यंत्र से देवी-देवताओं का आह्वान किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में ढोल-दमाऊ से ही देवताओं की नोबत लगाई जाती है। वहीं हुड़के का प्रयोग जागर, झोड़ा, छपेली, चांचरी, भगनौल में किया जाता है। बताते चलें कि ढोल-दमाऊ उत्तराखंड का प्राचीन वाद्य यंत्र है। यह दोनों तांबे से बने होते है और दोनों को साथ ही बजाया जाता है। साथ ही इस बाद्य यंत्र को काफी देखरेख की जाती है। वहीं अब इन बाद्य यंत्रों पर आधुनिकता की मार साफ देखी जा सकती है। शादी-विवाह में अब बैंड बाजों की धुन ज्यादा सुनाई देती है। जिससे पारंपरिक ढोल-दमाऊ बजाने वाले लोगों के आगे रोजी-रोटी का संकट पैदा हो रहा है। अमेरिका की सनसिटी यूनिवर्सिटी के छात्र उत्तराखंड की विलुप्त हो रही परंपरा को सीख रहे हैं।

बैर भगनौली, भगनौल गा कर सवाल-जवाब करते हैं, गायक की कुशलता उसके ज्ञान, वाकचातुर्य पर निर्भर करती है, एक तरह से भगनौल लोक गीत गायकों की व्यंग्य विनोदपूर्ण मनोरंजन रचनाएं है, यानी जब होली के त्योहार पर गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो ढोलक, मंजीरा और हुड़के की थाप पर भगनौल की महफिल सजती है।

लोकगीत गायन से जुड़े रहे दीवान कनवाल के कथनानुसार, पुरानी गायन शैली के अंतर्गत आने वाले बैर और भगनौल अब समाप्ति की ओर हैं। फाग, भडो, हुड़किया बौल भी लगभग समाप्ति की तरफ अग्रसर हैं। हुड़किया बौल में तर्क से हट कर वितर्क किया जा रहा है जिससे उक्त पारंपरिक गायन परंपरा समाप्ति की ओर है। चैती व भिटौली गायन परंपरा आज के डीजे परंपरा में कितने समय तक टिकेगी कहा नहीं जा सकता है। इस लोकगीत रचनाकार का मानना है, गीतों का अपनी जमीन से कटना संस्कृति के लिए बेहद नुकसानदायक है। इससे न गंभीर कलाकार पैदा होंगे, न कला का ही संरक्षण व संवर्धन होगा। गीत रचनाकार व लोकगीत गायक संयम रखे तभी पारंपरिक लोकगायन की लंबी पारी चल सकती है।

संस्कृति का सम्मान करें

रंगमंच के क्षेत्र में गहरा अनुभव रखने वाले दीवान कनवाल के कथनानुसार, नाटकों का मंचन पहाड़ी अंचल में लगभग समाप्त हो गया है। आज के स्थापित कलाकारों को सब कुछ करा कराया चाहिए। उन पर मुंबईया फिल्मी शान-शौकत का असर ज्यादा छा गया है। बिना तालीम कलाकार अपने आप को ज्यादा असरदार समझने लगा है। हर संस्कृति में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। तालीम जरूरी है, सदा अभावग्रस्त कलाकारों की पैरवी करने वाले लोकगीत गायक दीवान कनवाल को कलाकारों का हित साधने और उनके हित में बोलने वाले चन्द्र सिंह राही, गोपाल बाबू गोस्वामी तथा हीरा सिंह राणा का व्यक्तित्व व्यवहार कुशल लगा। कलाकारों व सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रति सरकारी नीतियों व बे-पैर के आदेशों का यह अनुभवी लोकगीत गायक निंदक रहा है। उनका मानना है कि सरकार कार्यक्रम तो कराती है लेकिन गरीब और अभावग्रस्त कलाकारों का मेहताना देने में दो से चार वर्ष तक का समय लगा देती है। कलाकार उक्त सरकारी नीति से टूट रहा है या चापलूसी में जीवन यापन कर रहा है जो अति शर्मनाक है। कलाकारों का उचित पारिश्रमिक समय से चुकता कर देना चाहिए। लोकसंस्कृति को समर्पित इस लोकगीत गायक के कथनानुसार लोग व्यक्ति को नहीं उसकी कला को तवज्जो देते हैं। रचे जा रहे आंचलिक गीतों में शब्दों का चयन घटिया हो गया है। आंचलिक शब्दों की जगह अन्य बोली-भाषाओं के शब्दों का चयन किया जा रहा है। जरूरत है शुद्ध आंचलिक या साहित्यिक शब्दों का तानाबाना बुनकर उनको गीतों में पिरोने की, जिससे अंचल और अंचल के गीतों की गरिमा बनी रह सके। बोली-भाषा के मानकीकरण पर इस लोकगीत गायक का मानना रहा है, कि हर कोश पर अंचल में शब्द बदल जाते हैं। बहुप्रचलित शब्दों का प्रयोग गीतों व बोलचाल में हो। अच्छे लोक कवियों की रचनाओं को प्रतिबद्ध होकर आगे लाया जाना चाहिए जो संबल बने। हर शहर में सांस्कृतिक व सामाजिक संस्थाए हैं, अच्छा कार्य कर रही हैं। कलाकारों के मन-मष्तिष्क में सोच होनी चाहिए वे अपनी लोक संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं, न कि स्वयं के लिए। कलाकार वरिष्ठ कलाकारों का सम्मान करे, संस्कृति का सम्मान करें। अपने दिल की व्यथा-वेदना को शब्दों से गीत गायन तक पहुंचाएं। आंचलिक बोली-भाषा और लोक संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए सदा समर्पित रहे लोकगीत गायक व गीत रचनाकार दीवान कनवाल का सपना है कि उत्तराखंड राज्य सांस्कृतिक समृद्धि की ओर बढ़ कर खुशहाल बने। वहीं प्रोत्साहन के अभाव में देवभूमि का ये पारंपरिक अब अपने ही प्रदेश में अपनी अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहा है। ●

व्यंग्य

नादान की दोस्ती जी का जंजाल

एलओपी जब विदेश के आता हैं तो अपनी बंदूक में कौन सा गोला बारूद लोड कर लाता हैं जो भारत में आते ही खुद पर ही वो गोला बारूद फाड़ लेता है, ये महाशय तो वो हैं जो 'हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे...।' गाते-गाते कांग्रेस को दो इंच और जमीन में भीतर गाड़ देते हैं।

दीप भट्ट
व्यंग्यकार मेरठ

भई ये कहावत तो आप सबने सुन ही रक्खी होगी न कि 'नादान की दोस्ती जी का जंजाल'। समझदार को इशारा काफी है। लो जी एक कहावत वो भी बढ़िया वाली चलो इसी बात पर खुलकर बत्तीसी दिखाओ। ये ऊपर जो हमने कहावत बताई है, उसकी जड़ में आजकल राहुल बाबा (एलओपी) की हरकतें हैं। मियां भाई ऐसी ऐसी लंपटई बातें वो भी संसद के अंदर बाहर दोनों तरफ सच कह रहा हूं मियां कई बार तो यूं लगे है कि बंदा समझदार कब होगा। अरे भाई कोई इसे समझाओ कि तुम्हारी उमर ढल रही है और समझदरिया घट रही है। बखत से समझ जाओ तो ठीक है वरना दो चार साल बाद कांग्रेस में ऐसा कोई न दिखेगा या समझ लो बचेगा जो तुम्हें समझा सके। आखिर उमर है जब ये तुम्हारी बढ़ेगी तो मियां उनकी भी तो बढ़ेगी। अगर कुछ घटेगी तो समझदारी वो भी तुम्हारी वाली 'स-पेशल' उनका क्या है वो तो पुराने वाले कांग्रेसी चावल हैं जिस दिन उन्हें लगा कि अब यहां चावल क्या दाल भी न पकेगी वो भी गुलाम नबी आजाद की तरह छेदी कांग्रेसी नाव से उतर लेंगे। और बना लेंगे अपनी पार्टी। वैसे भी नाव तो सब पार्टियों की काठ की ही बनी हुई है बस देखना ये है छेद किसमें कम हैं। आखिर महत्वाकांक्षी होना कोई गलत बात थोड़े है मियां। जनरल मनोज मुकुंद नरवडे जी की किताब फोर स्टारस ऑफ डेस्टिनी की पांडुलिपि 2023 से रक्षा मंत्रालय की फाइलों में यहां से वहां टहलती हुई अब तक एप्रूवल का इंतजार कर रही है। अब ये भी तो नहीं कह सकते न कि धूल फांक रही है। अब भैया मोदी जी के राज में एक काम तो बढ़िया हो ही गया है कि इससे पहले कोई बाबू अपनी बाबूगिरी दिखाकर फाइल को फ्रिज में डाल दे (आम बोलचाल की सरकारी भाषा में) वो बाबू खुद फ्रिज में लम लेट हो जाता है। इसलिए सब कुछ टाइम बाउंड है इत्ते दिन इसके पास इत्ते दिन उसके पास बीच में जहां फाइल अटकी उस स्तर के बाबू की आत्मा कहां-कहां नहीं भटकेगी ये तो बस मोदी ही जाने या अपने अमित भईया।

54 साल का युवा

भैया जिस किताब के प्रकाशन से देश की सुरक्षा जुड़ी हो वहां उसकी पांडुलिपि को कई-कई लेंसों की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सभी जानते हैं कि ये किताब 15 जून 2020 की चीन और भारत की गलवान घाटी की झड़प पर आधारित है। अब इतनी महत्वपूर्ण घटना पर आधारित किताब में क्या दिखाना है क्या छिपाना है ये तो सेना के अफसर ही तय करेंगे न। वैसे भी महाराज फौज के तीनों अंगों में एक ही चीज कॉमन है और वो है डिसिप्लिन बिना, डिसिप्लिन किसी भी संस्था का कोई औचित्य नहीं है और ये मामला तो विशुद्ध फौज का है, सो दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंक कर ही पिएगा। पर एलओपी जी यानी 'लोप' मतबल 'गायब' और ये महाशय तो जब तब लोप (गायब) होते ही रहते हैं। 'मौज आई फकीर की दिया झोपड़ा फूंक' अपनी इसी तर्ज पर जब मन किया

कई बार तो यूं लगे है कि बंदा समझदार कब होगा, अरे भाई कोई इसे समझाओ कि तुम्हारी उमर ढल रही है और समझदरिया घट रही है, बक्त से समझ जाओ तो ठीक है वरना दो चार साल बाद कांग्रेस में ऐसा कोई ना दिखेगा या समझ लो बचेगा जो तुम्हें समझा सके।

देश में जब मन किया परदेश में। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि इस 55 साल के युवा को विदेश में कौन इनवाइट करता है और काहे को? क्या ये विद्वान है? क्या ये कोई विशेषज्ञ है? कोई मंत्री-संत्री है? फिर विदेश में क्या करने जाता है। और जब विदेश के आता हैं तो अपनी बंदूक में कौन सा गोला बारूद लोड कर लाता हैं जो भारत में आते ही खुद पर ही वो गोला बारूद फाड़ लेता है। ये महाशय तो वो हैं जो 'हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे...।' गाते-गाते कांग्रेस को दो इंच और जमीन में भीतर गाड़ देते हैं।

बेशर्मी की हद

अब आप खुद समझो जो किताब अभी छपी नहीं ये महाराज उसके विषय में लोकसभा में आएं-बाएं-शाएं बोलने लगे। स्पीकर ने विषय का सोर्स पूछा तो 'कारवां' पत्रिका में छपे लेख का हवाला देने लगे। अब बात तो आगे बढ़नी ही थी। भाजपा ने भी पतंग आसमान में जाने से पहले ही हत्थे से काट डाली। समझदार को इशारा काफी, लेकिन समझदार हों तब न। सो स्पीकर पर ठीकरा फोड़ दिया कि स्पीकर 'लोप' को बोलने नहीं दे रहे और अगले दिन घोषणा कर दी कि पूरा विपक्ष स्पीकर ओम बिरला के विरुद्ध नो मोशन कॉन्फिडेंस लाएगा। अगले दिन 108 माननीयों के दस्तखत वाला नोटिस हवा में लहरा दिया। लेकिन गलतियां हैं कि कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ती। उस नोटिस में भी तीन जगह 2026 की जगह 2025 मेंशन कर दिया। ओम बिरला बिफर गए और घोषणा कर दी जब तक फैसला नहीं होगा मैं स्पीकर की सीट पर नहीं बैठूंगा अगले दिन स्पीकर की सीट जगदंबिका पाल ने संभाल ली। आदत खराब हो जाए तो जाते-जाते भी नहीं जाती सो अगले दिन फिर वही रोना धोना और कमाल देखिए अगले दिन भी स्पीकर की सीट पर पूर्व कांग्रेसी जगदंबिका पाल विराजमान थे। 'लोप' ने उनको पुराना कांग्रेसी होने के नाते नसीहत देने की कोशिश की तो जगदंबिका पाल ने गैरजरूरी शोर मचाने से बचने की चेतावनी दे दी। लेकिन भाई लोप तो लोप ठहरे नहीं रुके और अब जब रोके से लोप रुके नहीं तो जगदंबिका पाल ने भी पुरानी खुन्नस में चवन्नी उछालते हुए कह दिया कि अगर आप मेरी सुनते तो विपक्ष में नहीं बैठे होते। लोकसभा में एक क्षण के लिए तो सन्नाटा छा गया कांग्रेसियों को काटो तो खून नहीं लेकिन कुछ क्षण बाद फिर वही हो हल्ला शायद शास्त्रों में इसे ही बेशर्मी कहा गया है।

मुश्किल में 'लोप'

चलो यहां तक तो ठीक था लेकिन दो दिन के बाद नरवडे जी की किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' की पूरी किताब ही सदन में लहरा दी। लहराने वाला भी एक मात्र 'लोप' शायद एक ही किताब छपी या छपवाई गई होगी। शानदार कवर पेज की हल्की मोटी सी किताब लेकिन उसके अंदर क्या है ये तो 'लोप' ही जाने। जिस तरह कुछ समय पहले कांग्रेस जनों ने लोकसभा में संविधान-संविधान खेला था शायद उसी तर्ज पर नरवडे जी की अनपब्लिश्ड किताब के साथ खेला किया गया, लेकिन लेकिन लेकिन 'लोप' और कांग्रेसियों को अंदाजा भी नहीं था ये खेल उन पर उल्टा पड़ने वाला है आखिर संविधान तो पब्लिश्ड है किंतु यह किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' अप्रकाशित है और सीक्रेट एक्ट के दायरे में आती है सो जब तक कांग्रेसियों के दिमाग की बत्ती जलती तब तक राम नाम सत्य हो चुका था। अब चर्चा चल पड़ी कि भाजपा राहुल यानी 'लोप' के खिलाफ प्रिविलेज मोशन यानि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस के पुराने बचे खुचे चावलों को पता है कि नरवडे जी के प्रसंग में 'लोप' के विरुद्ध क्या-क्या हो सकता है। सीक्रेट एक्ट में उनको दो वर्ष की भी यदि सजा हुई तो उनकी संसद सदस्यता जा सकती है शायद 'लोप' को समझ आ गया और उन्होंने तुरंत शातिराना अंदाज में अगले दिन किताब का मुद्दा 'लोप' किया और भारत अमेरिका के बीच हुए करार पर कुछ न समझते हुए किसानों के नुकसान का रोना लेकर बैठ गए।

उम्र 55 की दिमाग बचपन का

किसी भी देश के लिए सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष का मजबूत होना भी आवश्यक माना गया है। चाणक्य नीति भी यही कहती है किंतु यहां चाणक्य नीति

- **भाई एलओपी तो लोप ठहरे वो बोलने लगते हैं तो रुकते भी नहीं और सुनते भी नहीं, इसलिए संसद में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ जगदंबिका पाल ने भी पुरानी खुन्नस में चवन्नी उछालते हुए कह दिया कि अगर आप मेरी सुनते तो विपक्ष में नहीं बैठे होते, अब तो संसद में सन्नाटा छा गया कांग्रेसियों को काटो तो खून नहीं।**
- **वैसे मैं यूं कह रहा था कि राजनीति में सॉफ्टवेयर अपडेट की व्यवस्था नहीं है क्या? अगर है तो भैया लोप के चाइल्ड वर्जन को डिलीट कर कम-से-कम यूथ वाला सॉफ्टवेयर अपडेट ही मार दो क्योंकि बुढ़ापे वाला डाला तो हार्डवेयर क्रश भी हो सकता है।**

की किसे समझ है। वैसे भी समझने के लिए चाणक्य नीति पढ़नी पड़ेगी और 'लोप' के हैंच मैन तो सारे के सारे लेफ्टिस्ट हैं। लेकिन यहां प्रश्न दूसरा है कि जनता ने आपको यानी विपक्ष को इस लायक तो रक्खा कि आप सत्ताधीशों के सामने डटकर खड़े रहें, जनता के हितों के लिए सत्ताधीशों से लड़े लेकिन ये तो खुद आपस में एक दूसरे का सर फोड़ने पर आमादा हैं, तो फिर जनता किससे उम्मीद रक्खे। जाति-जाति का खेल खेलने वाले विपक्षियों के रहते जातिवादी यूजीसी बिल कैसे पास हो गया। उड़ता हुआ तीर हवा में जाने से पहले रोका जा सकता था। लेकिन बात बे बात पे पोस्टर लहराओ कभी लोकसभा में तो कभी राज्यसभा में और अगर ताजी हवा खाने का मन करे तो गांधी जी हैं न उनके पुतले के नीचे खड़े होकर खींसे निपोरो कभी मिमिक्री करो कभी गद्दार-गद्दार कहकर अपने ही पुराने साथी का अपमान करो। ये समझ से परे है कि ये अहम ओछी हरकतें राजनीति शास्त्र के किस पन्ने पर लिखी गई हैं जिनका ये मुजाहिरा करते रहते हैं। जहां तक यूजीसी बिल का प्रश्न है सो ये उड़ता हुआ तीर भाजपा ने चलाया है देखते हैं ये तीर भाजपा में कहां तक और कितना धंसता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसकी आबादी 140 करोड़ से ज्यादा ही है कम तो बिलकुल भी नहीं। उस देश का विपक्षी नेता जिसे एलओपी कहते हैं जिसकी उम्र 55 की है और दिमाग अभी भी बचपन की अंधी गलियों में ही भटक रहा है। कहते हैं कुर्सी जिम्मेदारी का एहसास कराती है, कराती होगी महाराज यहां तो दूर-दूर तक उसका एक भी लक्षण नजर नहीं आ रहा है। सदन हो या सड़क ये बंदा दिखता है एकदम कड़क, लेकिन अंदाज ए बयां बिलकुल सड़क छाप...आप समझ रहे हो न। कुछ लोग उम्र से बड़े हो जाते हैं और कुछ लोग उम्र के बाद भी टिफिन-टाइम वाली मानसिकता से बाहर नहीं आते। 55 की उम्र कैलेंडर में है, पर दिल-दिमाग अभी भी क्लास में लास्ट बेंच पर बैठा है! सिर्फ महंगे कपड़े पहनना ही शालीनता का पैरामीटर नहीं हो सकता। दम बात में होता है कपड़ों में नहीं।

कहां कब बोलना कितना, समझ में गर जो आ जाए,
तो निश्चित मानिए साहिब, कि किस्मत भी बदल जाए।

लेकिन समझदारी और लोप तो दो चुंबकों की तरह नजर आ रहे हैं जिन्हें जितना पास लाओ वो उतना सटने की जगह दूर हट जाते है। सदन या सदन के बाहर हम वही बोलेंगे जो हमारे मूड में होगा जिसे सुनना हो सुनो वरना लोप के पास एक ब्रह्मास्त्र तो है कि तुम बीजेपी के एजेंट हो। वैसे मैं यूं कह रहा था राजनीति में सॉफ्टवेयर अपडेट की व्यवस्था नहीं है क्या? अगर है तो भैया लोप के चाइल्ड वर्जन को डिलीट कर कम-से-कम यूथ वाला सॉफ्टवेयर अपडेट ही मार दो क्योंकि बुढ़ापे वाला डाला तो हार्डवेयर क्रश भी हो सकता है। भैय्या अंत में एक बात तो बताओ 55 की उम्र में इस बंदे की अक्ल दाढ़ कब निकलेगी और निकलेगी भी या नहीं। ●

धुरंधर 2 से नेता हलकान

समीक्षकों ने आदित्य धर की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार करने का श्रेय देते हुए सुझाव दिया कि निर्देशक प्रमुख पुरस्कारों के प्रबल दावेदार हो सकते हैं, फिल्म के संगीत, तकनीकी गुणवत्ता और क्लाइमेक्स को भी उत्कृष्ट तत्वों के रूप में सराहा गया और भविष्यवाणी की गई कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना सकती है।

अरुण सिंह
मुंबई ब्यूरो

निर्देशक आदित्य धर की बहुप्रतीक्षित जासूसी थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2-द रिवेंज' 19 मार्च को देश और विदेश के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। हालांकि रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। रणवीर सिंह, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और सारा अर्जुन अभिनीत यह सीक्वल, पहले भाग की सफलता के लंबे इंतजार के बाद आया है। फिल्म समीक्षक हों या दर्शक सभी ने इस फिल्म की तारीफ की है, लेकिन पाकिस्तान से लेकर भारत के विपक्षी दल इस फिल्म को भाजपा का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। इस सब के बीच फिल्म समीक्षक सुमित कादेल ने धुरंधर-2 फिल्म की जमकर तारीफ की है। उन्होंने इसे 'गेम-चेंजिंग, इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली घटना' बताया है। उन्होंने इसके भव्यता, तीव्रता और भावनात्मक गहराई की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पहले भाग से कहीं बेहतर है। उनके अनुसार लंबी अवधि के बावजूद, फिल्म दर्शकों को एक पल भी उबाऊ नहीं लगने देती, क्योंकि इसकी पटकथा बेहद तेज गति से आगे बढ़ती है। उन्होंने किरदारों और उनकी पृष्ठभूमि की गहराई से पड़ताल पर भी प्रकाश डाला, खासकर मुख्य किरदार के रूपांतरण पर। वो रणवीर सिंह के दोहरे व्यक्तित्व के दमदार अभिनय से बेहद प्रभावित हुए और कहा कि अभिनेता ने अपने किरदार को पूरी तरह से जीवंत कर दिया है। उन्होंने आदित्य धर को इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार करने का श्रेय भी दिया और सुझाव दिया कि निर्देशक प्रमुख पुरस्कारों के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। फिल्म के संगीत, तकनीकी गुणवत्ता और क्लाइमेक्स को भी उत्कृष्ट तत्वों के रूप में सराहा गया और भविष्यवाणी की गई कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना सकती है।

जबरदस्त किरदार

फिल्म के शुरुआत में दर्शकों को लग सकता है कि धुरंधर द रिवेंज में एक दमदार खलनायक की कमी है, लेकिन संजय दत्त और अर्जुन रामपाल ने पहले और दूसरे भाग में अपने दमदार अभिनय से इस कमी को बखूबी पूरा कर दिया है। संजय दत्त के एसपी पहले भाग में खलनायक की भूमिका में छाए रहते हैं, और दूसरे भाग में अर्जुन रामपाल उनकी जगह ले लेते हैं। संजय दत्त अपने किरदार को बखूबी निभाते हैं, वहीं अर्जुन रामपाल के मेजर इकबाल एक क्रूर, शातिर खलनायक का किरदार निभाते हैं, जो किसी निजी कारण से हिंसक हो उठता है। ये दस मिनट का एक बेहद महत्वपूर्ण दृश्य को जन्म देता है, जिसमें अर्जुन अपने पिता का सामना करते हुए एक शानदार अभिनेता के रूप में जान डाल देते हैं। अगर यह कोई और फिल्म होती, तो इस तरह का व्यक्तिगत घटनाक्रम कई मायनों में गलत साबित हो सकता था, लेकिन अर्जुन, आदित्य धर के उन पर रखे भरोसे को सही साबित करते हैं, क्योंकि वे आपको अंत तक बांधे रखते हैं। आर माधवन कमाल के हैं। मतलब वो जब भी स्क्रीन पर आते हैं, प्रभावित करते हैं और स्क्रीन पर कम समय होने के बावजूद भी वो दूसरे हाफ को दमदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वो इतनी बार थिएटर में भारत माता की जय के नारे लगवाते हैं कि दर्शक गिनना ही छोड़ देते हैं। मानव गोहिल भी प्रभावित करते हैं और इतने प्रतिभाशाली अभिनेताओं के बीच कहीं खो नहीं जाते। सारा अर्जुन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरतीं और उनका किरदार एक सहायक किरदार बनकर रह जाता है, लेकिन फिर भी वह अपनी पूरी कोशिश करती हैं। दानिश पंडोर का उजैर बलोच का किरदार निराशाजनक कहा जा सकता है। उनके किरदार से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन कुछ अच्छे दृश्यों के अलावा कुछ खास नहीं हुआ। अंत में राकेश बेदी ने कमाल कर दिया। उनका किरदार शानदार है और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। जिससे दर्शक उनके लिए तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते हैं।

समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने फिल्म की कड़ी आलोचना की और फिल्म के बहाने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की फिल्में राजनीतिक प्रोपेगेंडा का हिस्सा होती हैं, उन्होंने कहा भाजपा के पास एक ऐसी मशीनरी है, जो मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर फिल्में बनवाती है।

धुरंधर-2 से विपक्षी नेता बोखलाए

फिल्म धुरंधर-2 रिलीज होते ही दुनिया में छा गई। लेकिन भारत में फिल्म को लेकर राजनीति भी गरमा गई है। वजह है धुरंधर-2 फिल्म का एक किरदार आतिफ अहमद, जिसकी तुलना यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद से की जा रही है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एआईएमआईएम सहित तमाम दलों के नेताओं के साथ वामपंथी पत्रकारों ने फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया है। कोई इसमें असल घटनाओं के संबंध खोज रहा है तो कोई प्रोपेगेंडा। समाजवादी पार्टी ने तो इस फिल्म के बहाने भाजपा पर ही सवाल उठा दिए हैं। फिल्म में अतीक अहमद से मिलते जुलते किरदार के पाकिस्तानी आईएसआई, अंडरवर्ल्ड, गैंगस्टर से संबंध दिखाए गए हैं। यहां तक कहा गया है कि वह आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के समर्थन से उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान समर्थित सरकार बनाने की साजिश में शामिल था। ये भी दिखाया गया है कि वह किस तरह नकली नोटों के नेटवर्क और भारत में हुई नोटबंदी से जुड़ा था। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने फिल्म की कड़ी आलोचना की और फिल्म के बहाने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की फिल्में राजनीतिक प्रोपेगेंडा का हिस्सा होती हैं। उन्होंने कहा भाजपा के पास एक ऐसी मशीनरी है, जो अपनी मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर फिल्में बनवाती है। फिल्मों के जरिए लोगों के मन में एक खास तरह की छवि बनाने की कोशिश की जाती है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान का कहना है कि, मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप कोई फिल्म बनाते हैं, तो वह ज्ञान और मनोरंजन के लिए होनी चाहिए...लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ पैसे कमाने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्में बनाते हैं। वो केवल एक खास समुदाय के खिलाफ, खासकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत दिखाते हैं...इस तरह की फिल्में माहौल खराब करने के लिए बनाई जाती हैं। सपा के पूर्व सांसद डा. एसटी हसन ने अतीक अहमद को लेकर कहा, कि उनका किससे जुड़ाव था और किससे नहीं, यह हमारी पुलिस बहुत अच्छी तरह जानती है। चाहे संबंध आईएसआई, सीआईए या केजीबी से था, हमारी खुफिया एजेंसियों और पुलिस ने अभी तक इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन फिल्म वाले क्या खुलासा कर दें, इसका कुछ पता नहीं है। हमने सुना है आईएसआई से दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन है। लेकिन अतीक अहमद के कनेक्शन पर किसी जांच एजेंसी ने खुलासा नहीं किया है। अब फिल्में सियासत के लिए बनाई जा रही हैं, समाज के लिए कोई मैसेज नहीं दिया जा रहा है। ऐसी फिल्में सिर्फ पाकिस्तान से ही नफरत नहीं, बल्कि हिंदू-मुस्लिम के ताने-बाने को तोड़ने के लिए बनाई जा रही हैं।

अतीक के किरदार से परेशानी क्यों?

जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने धुरंधर-2 पर संतुलित रुख अपनाया और कहा, मैं फिल्में नहीं देखता, लेकिन यह जिम्मेदारी सेंसर बोर्ड की है कि वह तय करे कि क्या दिखाना सही है और क्या नहीं? अगर फिल्म नियमों के तहत बनाई गई है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी अपराध से जुड़े व्यक्ति को महिमामंडित किया जाता है तो यह समाज के लिए गलत संदेश हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी धुरंधर-2 को लेकर कहा कि फिल्में सरकार नहीं बनाती बल्कि फिल्ममेकर बनाते हैं। फिल्म बनाने वाले वही दिखाते हैं जो दर्शकों को पसंद आता है। शिवसेना की प्रवक्ता शाइना एनसी का कहना है कि यह बहस का हिस्सा हो सकता है कि फिल्म प्रोपेगेंडा है या नहीं, लेकिन बॉलीवुड का मुख्य उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना है। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे विवाद पैदा हो या किसी की भावनाएं आहत हों। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने फिल्म का सपोर्ट करते हुए कहा कि फिल्में समाज में होने वाली घटनाओं को ही दर्शाती हैं और लोगों के सामने सच को रखने का काम करती हैं। मैं अतीक अहमद को संसद के समय से जानता था और उन्हें करीब से देखा है। अगर फिल्म में उनकी कहानी दिखाई जा रही है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है।

- **फिल्म के शुरुआत में दर्शकों को लग सकता है कि धुरंधर द रिवेंज में एक दमदार खलनायक की कमी है, लेकिन संजय दत्त और अर्जुन रामपाल ने पहले और दूसरे भाग में अपने दमदार अभिनय से इस कमी को बखूबी पूरा कर दिया है।**
- **भारत में धुरंधर-2 को लेकर राजनीति गरमा गई है, वजह है धुरंधर-2 फिल्म का एक किरदार आतिफ अहमद, जिसकी तुलना यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद से की जा रही है, इसे लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एआईएमआईएम सहित तमाम दलों के नेताओं के साथ वामपंथी पत्रकारों ने फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया है।**

पाकिस्तानी थर्ड क्लास बता रहे

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर-2 को दुनियाभर में खूब पसंद किया जा रहा है। फिल्म देखने के बाद दर्शक कलाकारों की तारीफ तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेकर्स की तारीफ भी करने से नहीं थक रहे हैं। फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, राकेश बेदी और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार अहम भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां धुरंधर का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं, दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी फैमिली ने धुरंधर-2 को महा घटिया फिल्म करार दिया है। उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपना रिव्यू शेयर किया है। साथ ही ये भी बताया है कि उन्हें फिल्म में सबसे ज्यादा किस कलाकार की एक्टिंग पसंद आई है। पाकिस्तानी परिवार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक पाकिस्तानी फैमिली ने यूके के थिएटर में धुरंधर-2 देखी। धुरंधर-2 देखने के बाद थिएटर से निकलते हुए उन्होंने धुरंधर-2 पर अपना रिएक्शन दिया। वीडियो में पाकिस्तानी फैमिली ने कहा कि उन्हें धुरंधर-2 पसंद नहीं आई। फिल्म की कहानी से लेकर कास्ट तक ने उन्हें निराश कर दिया। वीडियो में उस परिवार के एक शख्स ने तो फिल्म को थर्ड क्लास तक बताया। उसने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी थर्ड क्लास फिल्म कभी नहीं देखी। वहीं दूसरी महिला ने कहा अगर घटिया और थर्ड क्लास से भी कोई बुरा शब्द है तो वो इस फिल्म के लिए है। पूरे परिवार ने धुरंधर-2 की खूब बुराई की। वहीं इसी परिवार के कुछ लोगों ने मेजर इकबाल जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इससे पहले इसी पाकिस्तानी परिवार ने धुरंधर देखने के बाद उसकी खूब तारीफ की थी और कहा था कि इसे जरूर देखें। बता दें धुरंधर-2 जबसे रिलीज हुई है, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। ये फिल्म पाकिस्तान में बैन है। लेकिन इसकी पायरेटेड कॉपी खूब बिक रही है।

मासिक राशिफल

पंडित उपेन्द्र कुमार उपाध्याय
9897450817, 9897791284
ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदरत्न, कथावाचस्पति, यज्ञानुष्ठान विशेषज्ञ
अध्यक्ष-श्री शिवशक्ति ज्योतिष पीठ, बदायूं
निवास प्रभातनगर, निकट इंद्राचौक, सिविल लाइंस, बदायूं (यूपी)

मेष-

इस माह धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। भागीदारी वाले व्यवसायों और चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में निवेश न करें। आपके वरिष्ठ इस माह देवदूतों जैसा व्यवहार करने वाले हैं। अप्रेल में आपको ढेरों दिलचस्प निमंत्रण मिलेंगे-साथ ही आपको आकस्मिक उपहार मिलने के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन का आनंद लेने के पर्याप्त मौके हैं मिलेंगे। उपाय: मानसिक हिंसा से बचे, प्रभु में विश्वास रखें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 9

वृषभः-

इस माह आपके चेहरे पर मुस्कान बिखरी रहेगी और अजनबी भी जाने-पहचाने से महसूस होंगे। यह माह ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया है, जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। घरेलू जिंदगी सुकूनभरी और रुशनुमा रहेगी। इस माह आपको सब-कुछ प्रेम के रंग में रंगा दिखाई देगा। कार्यालय में कोई आपको बढ़िया खबर दे सकता है। उपाय: गणेशजी की चार परिक्रमा लेकर आशीर्वाद ले कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8

मिथुनः-

इस माह खीज और चिढ़चिढ़ेपन के अहसास को खुद पर हावी न होने दें। इस माह धन योग है। आप काफी धन कमा सकते हैं। बच्चे आपको व्यस्त रखेंगे और सुकून देंगे। प्रिय के साथ बाहर जाते समय अपने पहनावे और बरताव में नयापन दिखाएं। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करते समय अपने शब्दों को ध्यान से चुनें। जीवनसाथी के साथ शांत रहे ताकि लड़ाई-झगड़ा न हो। उपाय: काले चने, उड़द, तिल, सरसो का तेल दान करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 6

कर्कः-

इस माह बिना वजह के वाद-विवाद से कुछ हासिल नहीं होगा। कोई बेहतरीन विचार आपको आर्थिक तौर पर फायदा पहुंचा सकता है। अपने शब्दों पर काबू रखें, वरना परिवार के बुजुर्ग आहत हो सकते हैं। उन्हें अहसास कराएं कि आप उनका खयाल रखते हैं। इस माह के अंत में कारोबार के लिए की जाने वाली यात्रा फायदेमंद साबित होगी। जीवनसाथी आपका काम बिगाड़ सकता है। धैर्य रखें। उपाय: काला-सफेद कपड़ा साधु संतों को दान करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 1

सिंहः-

इस माह आपका आत्मविश्वास और आसान कामकाज आपको आराम के लिए समय देंगे, लेकिन धन आपकी मुट्ठी से सरक सकता है। आपके अच्छे सितारे आर्थिक तंगी नहीं आने देंगे। ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती हैं, जो आपको खुद अपनी जिंदगी से ज्यादा प्रेम करता होगा। कार्यालय में जिसके साथ आपकी सबसे कम बनती है, उससे संबंध सुधरेंगे। वैवाहिक जीवन का असली स्वाद चख सकते हैं। उपाय: गुरु या पिता की आज्ञा का पालन करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8

कन्याः-

इस माह रियल एस्टेट संबंधी निवेश अच्छा-खासा मुनाफा दे सकता है। घर में कुछ बदलाव भावुक बना सकते हैं। अपने प्रिय जीवनसाथी के बिना समय बिताने में दिक्कत महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में चीजें वाकई बेहतरी की ओर बढ़ सकती हैं। यात्रा और शिक्षा से जुड़े काम आपकी जागरुकता में वृद्धि करेंगे। आपके लिए यह माह खूबसूरत रोमानी रहेगा। सेहत का ख्याल रखे वरना आपकी परेशानी बढ़ सकती है। उपाय: धर्म स्थान पर झंडा दान करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 7

तुलाः-

लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आदि इस माह आपको मिल जाएंगे। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीजें दिला सकती है। आपके जहन में काम का दबाव होने के बावजूद आपका प्रिय आपके लिए खुशी के पलों को लाएगा। किसी लघु या मध्यावधि पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर अपनी तकनीकी क्षमताओं में निखार लाने का समय है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। उपाय: अपने पार्टनर को गुलाब दें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 9

वृश्चिकः-

रिश्तेदारों का सहयोग तनाव कम करेगा। सगे संबंधियों से मिलन होगा। उधार मांगने वाले लोगों को नजर अंदाज करें। बच्चे और परिवार को केंद्र में रखें। किसी दिलचस्प इंसान से मुलाकात की प्रबल संभावना है। अहम प्रोजेक्ट जिस पर आप काफी समय से काम कर रहे हैं वह टल सकता है। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करते वक्त शब्दों का ध्यान रखें। जीवनसाथी प्रेम से भरपूर रहेगा। उपाय: पूजा स्थान पर सफेद शंख स्थापित करें, कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 2

धनुः-

इस माह खुद को किसी सृजनात्मक काम में व्यस्त रखना बेहतर रहेगा। बीमारी से लड़ने के लिए खुद को तैयार रखें। इस माह आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन धन का व्यय आपकी योजनाओं में बाधा डाल सकता है। प्रिय से रोमांटिक मुलाकात होगी। कार्यक्षेत्र में तरक्की मिल सकती। जीवनसाथी यह बताएगा कि आप उसके लिए कितने कीमती हैं। उपाय: सोते समय तांबे के बर्तन में पानी रखे सुबह घर के बाहर पेड़ पौधों में डाले कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8

मकरः-

यह माह मौज-मस्ती और आनंद से भरा रहेगा। मजे लेने की अपनी प्रवृत्ति पर काबू रखें। मनोरंजन पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। बिना कुछ खास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। एक लंबा दौर जो काफी समय से आपको दबोचे हुए था, खत्म हो चुका है। जल्दी ही आपको जीवन-साथी मिलने वाला है। आपके वैवाहिक जीवन में और निखार आने का प्रबल योग है। उपाय: किसी तरह का घमंड न करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8

कुंभः-

इस माह कमीशन, लाभांश या रायल्टी के जरिए फायदा होने का योग बन रहा है। आपको ऐसी योजनाएं शुरू करनी चाहिए, जो पूरे परिवार के लिए समृद्धि लाने में सहायक हों। आपका प्यार आपके दिल को ठेस पहुंचा सकता है। लेखन और मीडिया के क्षेत्र में कार्य करने वालों को बड़ी ख्याति प्राप्त होने से प्रसन्नता होगी। अपने व्यक्तित्व और रंग-रूप को बेहतर बनाने की कोशिश संतोषजनक साबित होगी। उपाय: छोटी कन्याओं को भोजन कराएं कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 6

मीनः-

यह माह फायदेमंद साबित होगा। आप किसी पुरानी बीमारी से राहत और आराम महसूस करेंगे। अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन खर्च में इजाफा आपकी बचत को मुश्किल बना देगा। आप अपनी कामयाबी की फेहरिस्त में एक नया मोती जड़ेंगे। दूसरों के सामने आदर्श स्थापित करने के लिए खुद को बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखें। इस माह आपको निराशा हाथ लग सकती है। उपाय: अपने प्रिय को पिंक कलर के मोती या सिप की बनी हुई वस्तु गिफ्ट करें। कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 3

नुपुर नृत्य कला केंद्र हल्द्वानी

में सभी के लिए
01 फरवरी 2021 से पुनः
कक्षाएं आरंभ
हो गई है।

जिसमें क्लॉसिकल डांस, तबला वादन, सेमी क्लासिकल, गिटार, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करते हुए तथा कक्षों (क्लास) को नियमित रूप से सेनेटाइज कर आधुनिक तरीके से देने की व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है।

एडमिशन के लिए संपर्क करें।

NUPUR
www.nupurnritya.com
HALDWANI
Call: 05946-220841

www.facebook.com/nupurnrityakalakendra
You Tube: Search: nupurnrityakalakendra
nupurnritya99@gmail.com
www.nupurnritya.com

NEAR KANDPAL ENT. Hospital, SHAKTI SADAN GALI, NAWABI ROAD, HALDWANI (NAINITAL), Uttarakahnd

05946 220841, 91 9760590897
91 9411161794